

# लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF 3rd

LOK SABHA DEBATES

[ ग्यारहवां सत्र ]  
[ Eleventh Session ]



[ खंड 39 में अंक 21 से 30 तक हैं ]  
[ Vol. ~~33-34~~ contains Nos. 21-30 ]

40  
लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT  
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price • One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी / हिन्दी में किये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुबाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].

विषय-सूची

अंक 24, बुधवार, 24 मार्च, 1965/3 चैत्र 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

	विषय	पृष्ठ
<b>*तारांकित</b>		
<b>प्रश्न संख्या</b>		
543	तेल यातायात तथा भारतीय तेलवाहक जहाज	2187-88
544	पाइराइट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	2189-90
545	पंडित नेहरू का स्मारक	2190-92
546	आदर्श विश्वविद्यालय अधिनियम	2192-94
547	अध्यापकों के वेतनक्रम	2195-2200
548	महात्मा गांधी जन्म शताब्दी समारोह	2200-03
549	विश्वविद्यालय शिक्षा में सैनिक पाठ्यक्रम	2203-05
550	माध्यमिक शिक्षा	2205-08
551	अखिल भारतीय कृषि सेवा	2208-09

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रश्न संख्या

552	बरौनी तेल शोधनशाला के निकट पेट्रो-केमिकल कारखाना	2209-10
553	दिल्ली की यातायात समस्याएँ	2210
554	तकनीकी शिक्षा का माध्यम	2210
555	आसाम और नागालैण्ड के बीच सीमांकन	2211
556	पेट्रो-केमिकल उद्योग	2211
557	गांधी हरिजन स्कूल, मदनगिरि, दिल्ली	2211-12
558	नागाओं द्वारा आसाम के निकट एक चाय बाग पर कब्जा	2212-13
559	भंगियों की हड़ताल	2213-14
560	भूतपूर्व उपमन्त्री के विरुद्ध जांच	2214
561	शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2215
562	रूम १० में तीसरी श्रेणी	2216
563	जम्मू और काश्मीर द्वारा ऋण का भुगतान	2216
564	कलकत्ता के गोदी श्रमिकों पर पाकिस्तानी प्रभाव	2216-17
565	मोटी सतह वाली सड़कें	2217
566	राष्ट्रीय एकता परिषद्	2217-18

\*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

# CONTENTS

No. 24—Wednesday, March 24, 1965/Chaitra 3, 1887 (Saka)

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred  
Questions  
Nos.*

*Subject*

**PAGES**

543.	Oil Traffic and Indian Tankers . . . . .	2187—88
544.	Pyrites and Chemicals Ltd. . . . .	2189—90
545.	Memorial to Pandit Nehru . . . . .	2190—92
546.	Model University Act . . . . .	2192—94
547.	Salary Scales of Teachers . . . . .	2195—2200
548.	Mahatma Gandhi Birth Centenary . . . . .	2200—03
549.	Military Science in University Education . . . . .	2203—05
550.	Secondary Education . . . . .	2205—08
551.	All-India Agricultural Service . . . . .	2208—09

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred Questions Nos.*

552.	Petro-Chemical Complex near Barauni Refinery . . . . .	2209—10
553.	Traffic Problem of Delhi . . . . .	2210
554.	Medium of Technical Education . . . . .	2210
555.	Demarcation of Boundary between Assam and Nagaland . . . . .	2211
556.	Petro-Chemical Industries . . . . .	2211
557.	Gandhi Harijan School, Madangiri, Delhi . . . . .	2211—12
558.	Occupation of a Tea Estate near Assam by Nagas . . . . .	2212—13
559.	Sweepers' Strike . . . . .	2213—14
560.	Enquiry against former Deputy Minister . . . . .	2214
561.	National Programme of Physical Education . . . . .	2215
562.	Third Class M.As. . . . .	2216
563.	Repayment of Loan by Jammu and Kashmir . . . . .	2216
564.	Pakistani Influence among Calcutta Dock Workers . . . . .	2216—17
565.	Roads with Thicker Surface . . . . .	2217
566.	National Integration Council . . . . .	2217—18

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1420	हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी	2218
1421	जिला गजटियर	2218
1422	विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना	2219
1423	विस्थापित व्यक्तियों की नागरिकता	2219
1424	मद्रास उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले	2220
1425	विथ्यूर सब-जेल, केरल	2220
1426	विथ्यूर सब-जेल, केरल	2220
1427	राष्ट्रमण्डलीय युवक समारोह	2221
1428	लाहौर में अफ्रीकी-एशियाई गोष्ठी	2221
1429	संश्लिष्ट औषधि कारखाना, हैदराबाद	2221
1430	देहरादून में चुम्बकीय वैधशाला	2222
1431	संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों पर गोली चलाया जाना	2222
1432	दिल्ली शिक्षा संहिता	2222
1433	बम्बई में उर्वरक कारखाना	2223
1434	विक्रम विश्वविद्यालय	2223
1435	पुलिस तथा जनता के पारस्परिक सम्बन्ध	2223-24
1436	टोकियो ओलम्पिक खेल	2224
1437	कालकाजी में विस्थापितों के लिये भूमि का विकास	2224
1438	जस्टिस मित्र का मामला	2224-25
1439	केरल में स्कूलों के अध्यापक	2225
1440	दिल्ली में मकान एलाट करना	2225
1441	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन	2226
1442	आसाम-भूटान सीमा	2226
1443	ललित कला अकादमी	2226-27
1444	साहित्य अकादमी तथा ललित कला अकादमी	2227-28
1445	नेशनल बुक ट्रस्ट	2228
1446	नेशनल बुक ट्रस्ट	2228
1447	अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प संस्था, नई दिल्ली	2228-29
1448	शल्य चिकित्सा औजार कारखाना, मद्रास	2229
1449	अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	2229
1450	उत्तर में दूसरा तेल शोधक कारखाना	2230
1451	न्यूजीलैण्ड से जेट नौकायें	2230
1452	निष्क्रान्त सम्पत्ति	2230-31
1453	निष्क्रान्त सम्पत्ति का बकाया किराया	2231
1454	सरकारी कर्मचारियों के लिये सहकारी स्टोर	2231-32
1455	हकीमपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस का गोली चलाना	2232

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

*Unstarred*

*Questions*

Nos.	Subject	PAGES
1420.	Hindustani Culture Society . . . . .	2218
1421.	District Gazetteers . . . . .	2218
1422.	Foreign Languages Scholarships Scheme . . . . .	2219
1423.	Citizenship of Displaced Persons . . . . .	2219
1424.	Pending Cases in Madras High Court . . . . .	2220
1425.	Viyyoor Jail, Kerala . . . . .	2220
1426.	Viyyoor Sub-Jail, Kerala . . . . .	2220
1427.	Commonwealth Youth Festival . . . . .	2221
1428.	Afro-Asian Seminar in Lahore . . . . .	2221
1429.	Synthetic Drug Factory, Hyderabad . . . . .	2221
1430.	Magnetic Observatory at Dehradun . . . . .	2222
1431.	Firing on U. N. Observers . . . . .	2222
1432.	Delhi Education Code . . . . .	2222
1433.	Fertilizer Factory, Bombay . . . . .	2223
1434.	Bikram University . . . . .	2223
1435.	Relationship between Police and Public . . . . .	2223—24
1436.	Tokyo Olympics . . . . .	2224
1437.	Development of land in Kalkaji for Displaced persons . . . . .	2224
1438.	Justice Mitter's Case . . . . .	2224—25
1439.	School Teachers in Kerala . . . . .	2225
1440.	Allotment of Tenements in Delhi . . . . .	2225
1441.	Pensions to Freedom Fighters . . . . .	2226
1442.	Assam-Bhutan Border . . . . .	2226
1443.	Lalit Kala Akademi . . . . .	2226—27
1444.	Sahitya Akademi and Fine Arts Academy . . . . .	2227—28
1445.	National Book Trust . . . . .	2228
1446.	National Book Trust . . . . .	2228
1447.	All India Fine Arts and Crafts Society, New Delhi . . . . .	2228—29
1448.	Surgical Instruments Factory, Madras . . . . .	2229
1449.	Scheduled Castes Employees . . . . .	2229
1450.	Second Refinery in the North . . . . .	2230
1451.	Jet Boats from Newzealand . . . . .	2230
1452.	Evacuee Property . . . . .	2230—31
1453.	Rent arrears form Evacuee Property . . . . .	2231
1454.	Co-operative Stores for Government Employees . . . . .	2231—32
1455.	Police Firing at Hakimpur Railway Station . . . . .	2232

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1456	गोआ में ज्वत की गई पुर्तगाली आस्तियां	2232-33
1457	भूमि अर्जन विभाग, दिल्ली	2233
1458	सरकारी विभागों में कल्याण अधिकारी	2233-34
1459	मुरैना में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई	2234
1460	इन्द्रावती तथा सबरी के बेसिनों में लोगों को बसाना	2234-35
1461	मध्य प्रदेश में बहु-प्रयोजनीय स्कूल	2235
1462	मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्तियां	2236
1463	राज्यों में राजभाषा के रूप में प्रादेशिक भाषा	2236
1464	विज्ञान शिक्षा	2236-37
1465	प्रादेशिक भाषाओं की पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद	2237
1466	नई दिल्ली नगरपालिका की बकाया राशि की वसूली	2237-38
1467	राष्ट्रीय सन्धियों का संरक्षण	2239
1468	ईराक और कुवैत में तेल सम्बन्धी रियायत	2239
1469	ग्रामीण संस्थायें	2239-40
1470	विश्वविद्यालयों को मान्यता देना	2240
1471	मद्रास के लिये तीन भाषाओं वाला सूत्र	2240-41
1472	भारतीय सैनिक अकादमी के पास चीनी कारतूसों का पाया जाना	2241
1473	त्रिपुरा के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता	2241-42
1474	भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन	2242
1475	कोटा के पास खाद कारखाना	2242
1476	तेल की खोज के लिये फ्रांसीसी सहयोग	2242-43
1477	उत्तर प्रदेश में पोलिटैकनीक संस्थायें	2243
1478	मन्त्रियों की विदेश यात्रा	2243-44
1479	उर्वरक कारखाना, गोरखपुर	2244
1480	भ्रष्टाचार के मामले	2244-45
1481	इंजीनियरी कालिजों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देना	2245
1482	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	2245-46
1483	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	2246
1484	भाहे में भूमि सुधार	2246-47
1485	दिल्ली में एक राजदूतावास से केबल की चोरी	2247
1486	उड़ीसा में संस्कृत संस्थायें	2247-48
1487	कम मूल्य वाली अमरीकी पुस्तकें	2248-49
1488	विद्रोही नागा	2249-50
1489	त्रिपुरा में शरणार्थी	2250
1490	शरणार्थियों को सहायता	2250-51
1491	डाक-तार खेल कूद नियन्त्रण बोर्ड	2251
1492	लन्दन रायल इन्स्टीट्यूट के डिप्लोमे	2251-52

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

*Unstarred*

*Questions*

<i>Nos.</i>	<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
1456.	Portuguese Assets seized in Goa . . . . .	2232—33
1457.	Land Acquisition Department, Delhi . . . . .	2233
1458.	Welfare Officers in Government Departments . . . . .	2233—34
1459.	Archaeological Excavation in Morena . . . . .	2234
1460.	Rehabilitation in Indravati and Sabri Basins . . . . .	2234—35
1461.	Multi-purpose Schools in M.P. . . . .	2235
1462.	Post Matric Scholarships . . . . .	2236
1463.	Regional Language as Official language in States . . . . .	2236
1464.	Science Education . . . . .	2236—37
1465.	Hindi Translation of Regional Language Books . . . . .	2237
1466.	Recovery of Arrears due to N.D.M.C. . . . .	2237—38
1467.	Protection of National Plants . . . . .	2239
1468.	Oil Concession in Iraq and Kuwait . . . . .	2239
1469.	Rural Institutes . . . . .	2239—40
1470.	Recognition to University . . . . .	2240
1471.	Three Language formula for Madras . . . . .	2240—41
1472.	Discovery of Chinese Cartridges near Indian Military Academy . . . . .	2241
1473.	Compensatory Allowance to Tripura Employees . . . . .	2241—42
1474.	Anti-Corruption Drive . . . . .	2242
1475.	Fertilizer Factory near Kotah . . . . .	2242
1476.	French Collaboration for oil Exploration . . . . .	2242—43
1477.	Polytechnics in Uttar Pradesh . . . . .	2243
1478.	Visit by Ministers Abroad . . . . .	2243—44
1479.	Fertilizer Factory, Gorakhpur . . . . .	2244
1480.	Corruption Cases . . . . .	2244—45
1481.	Training of Engineering College Teachers . . . . .	2245
1482.	Employees belonging to S.C. and S.T. . . . .	2245—46
1483.	S.C. and S.T. Employees . . . . .	2246
1484.	Land Reforms in Mahe . . . . .	2246—47
1485.	Theft of Cable Wire from an Embassy in Delhi . . . . .	2247
1486.	Sanskrit Organisations in Orissa . . . . .	2247—48
1487.	Low-priced American Books . . . . .	2248—49
1488.	Naga Hostiles . . . . .	2249—50
1489.	Refugees in Tripura . . . . .	2250
1490.	Aid for Refugees . . . . .	2250—51
1491.	Posts and Telegraphs Sports Control Board . . . . .	2251
1492.	London Royal Institute Diplomas . . . . .	2251—52

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या

विषय

पृष्ठ

1493	पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी	2252
1494	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल कारखाना	2252
1495	हिन्दी विरोधी आन्दोलन	2252-53
1496	सरकारी सेवायें	2253
1497	केरल में नजरबन्द व्यक्ति	2253-54
1498	सिंदरी उर्वरक कारखाने में अमोनिया सन्यन्त्र	2254
1499	विहटले परिषद्	2254-55
1500	अंकलेश्वर-कोयली पाइप लाइन	2255
1501	जवाहर ज्योति ले जाने वाली जीप पर हमला	2255
1502	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में सूर्य शक्ति चालित यन्त्र	2256
1503	मोतिया खान, दिल्ली में आग	2256-57
1504	केरल में पुलिस की ज्यादतियों के बारे में शिकायतें	2257
1505	गुजरात तेल शोधक कारखाना	2257-58
1506	मध्य प्रदेश में स्कूल विज्ञान प्रयोगशालायें	2258
1507	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109	2258
1508	केरल में नजरबन्द व्यक्ति	2259
1509	दिल्ली के स्कूलों में लाइब्रेरियन	2259
1510	दिल्ली में स्कूल शिक्षा	2259

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

2259-60

सभा पटल पर रखे गये पत्र	2261-62
राज्य सभा से सन्देश	2262
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक	2262
राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में	2262
तारांकित प्रश्न संख्या 226 के उत्तर में शुद्धि	2263
सरकारी कार्यालयों में काम के घंटों	2263
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	2263
साठवां प्रतिवेदन	2263

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा

श्री पी० रा० रामकृष्णन्	2263-64
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित	2263-66
श्री नारायण दांडेकर	2267-70

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION—*contd.*

*Unstarred  
Questions  
Nos.*

<i>Subject</i>	<i>PAGES</i>
1493. Arrest of Pakistanis . . . . .	2252
1494. Hindustan Organic Chemical Factory . . . . .	2252
1495. Anti-Hindi Agitation . . . . .	2252-53
1496. Government Services. . . . .	2253
1497. Detenus in Kerala . . . . .	2253-54
1498. Ammonia Plant, Sindri Fertiliser Factory . . . . .	2254
1499. Whitely Council . . . . .	2254-55
1500. Ankleshwar Koyli Pipe-Line . . . . .	2255
1501. Attack on the jeep carrying Jawahar Jyoti . . . . .	2255
1502. Solar Energy Instruments at N.P.L. . . . .	2256
1503. Fire in Motia Khan, Delhi . . . . .	2256-57
1504. Complaints of Police repression in Kerala . . . . .	2257
1505. Gujarat Refinery . . . . .	2257-58
1506. School Science Laboratories in U.P. . . . .	2258
1507. Section 109 of Criminal Procedure Code . . . . .	2258
1508. Detenus in Kerala . . . . .	2259
1509. Librarians in Delhi Schools . . . . .	2259
1510. School Education in Delhi . . . . .	2259
Re : Calling Attention Notices . . . . . (Query)	2259-60
Papers laid on the Table . . . . .	2261-62
Message from Rajya Sabha . . . . .	2262
Industries (Development and Regulation) Amendment Bill . . . . .	2262
As passed by Rajya Sabha . . . . .	2262
Correction of Answer to S.Q. NO. 226 . . . . .	2263
Working hours of Government Officers . . . . .	2263
Committee on Private Members' Bills and Resolutions Sixtieth Report . . . . .	2263
General Budget—General Discussion . . . . .	2263
Shri P. R. Ramakrishnan . . . . .	2263-64
Shrimati Vijay Lakshmi Pandit . . . . .	2264-66
Shri N. Dandekar ] . . . . .	2267-70

सामान्य आय व्ययक-सामान्य चर्चा--(जारी)

विषय	पृष्ठ
डा० राम मनोहर लोहिया . . . . .	2270—72
श्री व० बा० गांधी . . . . .	2272—73
डा० सरोजिनी महिषी . . . . .	2273—75
श्री म० ला० वर्मा . . . . .	2275
श्रीमती सहोदराबाई राय . . . . .	2276
श्री कर्नी सिंहजी . . . . .	2276—78
श्री द्वारका दास मन्त्री . . . . .	2278—79
श्री रा० गि० दुबे . . . . .	2279—80
श्रीमती विजयराजे सिंधिया . . . . .	2280—81
श्री प्रकाशवीर शास्त्री . . . . .	2281—83
श्री ब० रा० भगत . . . . .	2283—85
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा . . . . .	2286

केरल में राष्ट्रपति के शासन सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में वक्तव्य—

श्री नन्दा	2286—88
------------	---------

General Budget—General Discussion—*contd.*

	<i>Subject</i>	PAGES
Dr. Ram Manohar Lohia . . . . .		2270—72
Shri V.B. Gandhi . . . . .		2272-73
Dr. Sarojini Mahishi . . . . .		2273—75
Shri M.L. Varma . . . . .		2275
Shrimati Sahodra Bai Rai . . . . .		2276
Shri Karni Singhji . . . . .		2276—78
Shri D.D. Mantri . . . . .		2278-79
Shri R.G. Dubey . . . . .		2279-80
Shrimati Vijaya Raje Scindia . . . . .		2280-81
Shri Prakash Vir Shastri . . . . .		2281—83
Shri B. R. Bhagat . . . . .		2283—85
Shrimati Jyotsna Chanda . . . . .		2286
Statement Proclamation regarding President's Rule in Kerala—		
Shri Nanda . . . . .		2286—88

लोक-सभा  
LOK SABHA

बुधवार, 24 मार्च, 1965/3 चैत्र, 1887 (शक)

Wednesday March 24, 1965/Chaitra 3, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

( अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए )  
( MR. SPEAKER in the Chair )

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तेल यातायात तथा भारतीय तेल वाहक जहाज

543. { श्री यशपाल सिंह :  
श्री भागवत झा आजाद :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 29 दिसम्बर, 1964 को कलकत्ता में राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड के सभापति द्वारा दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिये तेल यातायात को विदेशी तेलवाहक जहाजों की बजाय भारतीय तेलवाहक जहाजों को सौंपने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि कम से कम सरकारी क्षेत्र की तेल शोधन-शालाएं भारतीय तेलवाहक जहाजों का प्रयोग करें, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय कच्चे तेल के यातायात के लिए भारतीय तेल वाहक जहाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है । इन का उस समय प्रयोग किया जायेगा जब वे प्रतियोगी दरों पर तेल यातायात के वहन के लिए उपलब्ध होंगे ।

**Shri Yashpal Singh** : As we have not got our own tankers, may I know the annual loss to us ? How much amount we have to pay annually for the foreign tankers ?

श्री हुमायून कबीर : अनेकों विदेशी टैंकर इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

**Shri Yashpal Singh :** I want to know the amount which we have to pay annually for the crude oil.

श्री हुमायून कबीर : मैं ने पूर्व सूचना मांगी है क्यों कि इसमें विस्तृत रूप से हिसाब लगाना पड़ेगा ।

**Shri Yashpal Singh :** By what time India would be self sufficient in this respect ?

श्री हुमायून कबीर : यह कहना कठिन है कि हम कब तक आत्म-निर्भर हो जाएंगे । लेकिन हम यथाशीघ्र अपने टैंकर बनाना चाहते हैं । मैं ने यह भी सुझाव दिया है कि क्योंकि टैंकरों का पैसा 4 या 5 वर्षों में पूरा हो सकता है अतः यथासम्भव शीघ्र अधिक संख्या में टैंकरों में धन लगाना लाभप्रद होगा ।

श्री हेडा : क्या किसी गैर-सरकारी जहाजी कम्पनी ने अथवा कम्पनियों ने कोई प्रस्ताव रखा है और क्या उन्होंने कोई रियायत मांगी है ? यदि हां तो क्या सरकार उस पर विचार कर रही है ?

श्री हुमायून कबीर : जयन्ती शिपिंग कम्पनी के पास दो टैंकर हैं । यदि और कोई प्रार्थना की जाती है, तो हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे ।

श्रीमती सावित्री निगम : भाड़ा के रूप में हम प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा में कितना धन देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूर्व-सूचना मांगी है ।

श्रीमती सावित्री निगम : उन्हें क्षमता का पता नहीं होगा लेकिन दर का पता तो होगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह ने भी यही प्रश्न पूछा था ।

श्री कपूर सिंह : वह हिन्दी में था; यह अंग्रेजी में है ।

श्रीमती सावित्री निगम : हम कितना भाड़ा दे रहे हैं ? यह बड़ा स्पष्ट प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के पास यह जानकारी है या नहीं है ?

श्री हुमायून कबीर : जैसा मैंने बताया, मैं ठीक आंकड़े नहीं बता सकता । लेकिन मैं दर बता सकता हूँ । कुल भुगतान वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने जहाज इस्तेमाल करते हैं और हर वर्ष यह संख्या भिन्न होती है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : बाहर से हम कितनी मात्रा में कच्चा तेल और पेट्रोल लाएंगे और भारतीय टैंकरों द्वारा कितना तेल लाया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न :

## पाइराइट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

\*544. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाइराइट्स तथा केमिकल्स विकास कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विभिन्न इकाइयों का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा तथा उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं। कम्पनी की निम्नलिखित दो परियोजनायें जनवरी, 1965 में सरकार द्वारा अनुमोदित की गईं :—

(1) बिहार में अमझोर नामक स्थान पर पाइराइट्स धातु के 2.4 लाख मीटरी टन के वार्षिक उत्पादन के लिए खनन परियोजना।

(2) सिन्दरी में पाइराइट्स पर आधारित प्रति दिन 400 मीटरी टन की क्षमता-युक्त एक सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र की स्थापना के लिए परियोजना।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अप्रैल, 1967 में दोनों परियोजनाओं द्वारा उत्पादन होने की सम्भावना है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : इन संयंत्रों की उत्पादन-क्षमता कितनी होगी ?

श्री अलगेशन : जैसा मैं ने बताया कि अमझोर में यह 2.4 लाख टन अयस्क निकालने की है। गन्धकीय एसिड संयंत्र के लिए क्षमता 400 टन प्रति दिन है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : इसमें लागत कितनी आएगी ?

श्री अलगेशन : गन्धकीय एसिड संयंत्र के लिए यह 201.51 लाख रुपए है और खनन परियोजना के लिए 439 लाख रुपये है।

श्री श्याम लाल सराफ़ : क्या गैर-सरकारी तौर पर किन्हीं और निक्षेपों का पता चला है, यदि हां, तो किस स्थान पर और उनमें से कुछ का काम इस निगम को सौंपा जाएगा ?

श्री अलगेशन : अभी यह बिहार-अमझोर में है। मुझे पता नहीं है कि इसका किसी और स्थान पर भी पता लगाया गया है या नहीं।

**Shri Onkar Lal Berwa :** May I know whether some foreign help is also sought or this; if so the nature of help or the name of the collaborator ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : गन्धकीय एसिड संयंत्र में कोई विदेशी सहयोग नहीं होगा। ब्रिटेन के मेसर्स साइमन कार्व्स ठेकेदार होंगे। खनन परियोजना में कोई सहयोगी नहीं है लेकिन हमें क्रयादेश दे दिए हैं।

श्री सं० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूँ कि इन दो परियोजनाओं की अनुमति से पूर्व कितने स्थानों का सर्वेक्षण किया गया था ?

श्री अलगेशन : हमें भारतीय खान ब्यूरो से एक रिपोर्ट मिली और उसके फलस्वरूप हमें पता चला कि वहां पर अनुमानतः कितने निक्षेप हैं और कितने निकाले जा सकते हैं ।

### पंडित नेहरू का स्मारक

+

\*545. { श्रीमती सावित्री निगम :  
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :  
श्री रा० गि० दुबे :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू की स्मृति बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय स्मारक स्थापित करने से सम्बन्धित कोई विशिष्ट योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) . स्वर्गीय प्रधान मंत्री के निवास स्थान, तीन मूर्ति भवन (हाउस) में 'नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय' की स्थापना के अतिरिक्त सरकार ने स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू की स्मृति रूप में राष्ट्रीय स्मारकों के स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई है ।

श्रीमन् मैं मूल प्रश्न में कुछ और जोड़ता हूँ ताकि यह पूरा हो जाए । प्रश्न में विशिष्ट प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है । हम "अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिए नेहरू पुरस्कार" नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार लागू करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहे हैं । क्यों कि यह एक विशिष्ट योजना नहीं है इसलिए मैं ने यह मूल उत्तर में नहीं बताया लेकिन मैं समझता हूँ कि सभा में यह बताना उचित है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्यों कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री और प्रिय नेता बच्चों को सदैव बहुत प्यार करते थे : । क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या इस समिति ने कभी अपंग बच्चों के लिए गृह स्थापित करने के बारे में भी सोचा है ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां । यह एक सरकारी योजना ही नहीं है लेकिन सरकारी योजना के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू स्मारक ट्रस्ट की बच्चों के सांस्कृतिक और मनोरंजन के हित के लिए जवाहर भवन स्थापित करने की भी एक योजना है । माननीय सदस्या का प्रश्न मैं ट्रस्ट उप-समिति के समक्ष रख दूंगा कि वे अपंग बच्चों की ओर भी ध्यान दें ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस ट्रस्ट के सदस्य कौन कौन हैं और क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या वे इस प्रयोजन के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं अथवा कल्याण संगठनों से कोई विशेष योजनाएं आमंत्रित कर रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : उप-समिति के सदस्यों की सूची मेरे पास यहां नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ कि उप-राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष हैं, एक सदस्या श्रीमती पण्डित हैं और कुछ अन्य व्यक्ति भी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : एक मैं भी हूँ ।

श्रीमती सावित्री निगम : तब फिर हम आशा करें कि अपंग बच्चों को भी कुछ मिलेगा ।

**Shri Sheo Narain** : I want to know whether it is contemplated to issue the summary of the life sketch of Pandit Nehru in the book form for the use of children.

श्री मु० क० चागला : केवल नेहरू की जीवनी के बारे में ही नहीं बल्कि नेहरू के समय के बारे में भी कई प्रकार से खोज की जा रही है । हम जो पुस्तकालय स्थापित कर रहे हैं, वह आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए होगा जिसमें राम मोहन राय के समय से लेकर वर्तमान समय तक की सामग्री होगी । अतः 1947 से अब तक का समय भी इसमें शामिल होगा ।

श्री रा० गि० दुबे : क्यों कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री एक राष्ट्रीय नेता थे, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इसी प्रकार के स्मारक देश के अन्य भागों में भी बनाए जाएंगे ?

श्री मु० क० चागला : जी, हाँ । जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू स्मारक ट्रस्ट का सम्बन्ध है देश के अन्य भागों में जवाहर भवन बनाए जायेंगे और नेहरू शिलालेख लगाए जाएंगे जिन पर स्वर्गीय प्रधान मंत्री की उक्तियाँ अंकित की जाएंगी जो उस स्थान के उपयुक्त होंगी जहाँ शिलालेख लगाए जाएंगे ।

श्री हेम बरुआ : कुछ समय पूर्व ऐसा लगता था कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री के तीन मूर्ति स्थित निवास के कुछ भाग को भी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में विदेशी विद्यार्थियों के लिए अनुसंधान केन्द्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा । यदि ऐसा है, तो उस सुझाव का क्या हुआ ?

श्री मु० क० चागला : मुझे अभी समूची योजना को एक परियोजना रिपोर्ट मिली है । योजना इस प्रकार है । यह पुस्तकालय इस विशेष अवधि के लिए प्रमुख होगा और इसमें भारत के और विदेश के—दोनों स्थानों के विद्यार्थी भारतीय इतिहास की इस विशेष अवधि के बारे में अनुसंधान कर सकेंगे । भारत में बहुत थोड़े इतिहासवेत्ता हैं और अब कुछ और इतिहासवेत्ता इस विषय पर लिख रहे हैं ।

**Shri Jagdev Singh Siddhanti** : May I know whether some old manuscripts, rocks and coins would be kept in this memorial ?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं । जहाँ तक संग्रहालय का सम्बन्ध है, यह नेहरू संग्रहालय है । इसमें स्वर्गीय प्रधान मंत्री की जीवनी, उन के लेखों, पुस्तकों आदि के सम्बन्ध में जानकारी रहेगी ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्यों कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय सूझबूझ के एक महान अधिकारी थे । क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार शांति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सूझबूझ कर संस्था स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाएगी ?

श्री मु० क० चागला : नेहरू अकादमी बनाने की एक परियोजना है । लेकिन, जैसा मैंने बताया, हम एक पुरस्कार स्थापित कर रहे हैं जो कि उस नोबल पुरस्कार जैसा होगा जो अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए सर्वाधिक कार्य करने वाले को दिया जाता है ।

**Shri Kishen Pattnayak** : Do the Government not believe that memory of Nehru will always remain in the minds of the people even without these memorials ?

श्री मु० क० चागला : मुझे विश्वास है कि स्मारक बनाए बिना भी लोगों के मन में नेहरू सदा रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कृत्रिम राष्ट्र को स्मारक बनाने ही चाहिए।

आदर्श विश्वविद्यालय अधिनियम

+

- \*546. { श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :  
 श्री ज० ब० सिंह :  
 श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :  
 श्री कृ० चं० अन्त :  
 श्री रम लोचन दाव  
 श्री राम चन्द्र उताका :  
 श्री बुजेश्वर मीना :  
 श्री दी० चं० शर्मा :  
 श्री रामेश्वर टांटिया :  
 श्री विद्याचरण शुक्ल :  
 डा० चन्द्र भान सिंह :  
 श्री राम सहाय पाण्डेय :  
 श्री उइके :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदर्श विश्वविद्यालय अधिनियम सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों सम्बन्धी वर्तमान कानून में संशोधन करने के बारे में समिति के क्या मुख्य प्रस्ताव हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [मुस्तफालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4043/65]

(ग) और (घ) प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

**Shri Siddheshwar Prasad :** I want to know the extent of the implementation of these recommendations on the Universities under the control of the Centre ?

श्री मु० क० चागला : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक प्रवर समिति के समक्ष है। हम जिन प्रस्तावों को स्वीकार करेंगे उन्हें इस विधेयक में रखने का प्रयत्न करेंगे।

**Shri Siddheshwar Prasad :** Sir, besides universities many suggestions and recommendations have been given in the statements in regard to affiliated colleges. I want to know the reaction of the State Governments and universities on these recommendations and the steps being taken by the Government in this respect for taking an early action ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि विवरण में लिखा है, आदर्श समिति को रिपोर्ट एक महीने पहले ही मिली है। यही रिपोर्ट हमने विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों को भेज दी है। अभी हमने भी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया है। हम इस समिति के प्रस्तावों पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : इस विवरण के अन्तिम पैरा में लिखा है :

“विश्वविद्यालयों में, अन्य प्रशिक्षणों में विद्यार्थी—सरकार के प्रशिक्षण की अवहेलना नहीं की जानी चाहिये”

क्या मैं जान सकता हूँ कि यह केवल दिखावा मात्र है या मंत्रालय ने इस पर गंभीरता से विचार किया है। क्योंकि छात्र-सरकार एक संघ के समान होता है और यह संघ अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायक है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस “छात्र-सरकार” शब्द का वास्तव में क्या तात्पर्य है।

श्री मु० क० चागला : जैसा मैं समझता हूँ इसका मतलब है कि हर विश्वविद्यालय में एक छात्र संघ, एक सरकारी समिति और एक भोजन समिति होनी चाहिये जो विद्यार्थियों के मामले को निबटाए, कि वे क्या भोजन करते हैं आदि आदि। मैं समझता हूँ कि माडल समिति ने इस रूप में विद्यार्थियों के लिये स्व-सरकार का यह शब्द प्रयोग किया है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या सरकार सभी विश्वविद्यालयों के मामले में राष्ट्रपति को विजिटर बनाने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से और इसके पक्ष में विचार कर रही है और क्या सरकार इस माडल अधिनियम को सभी राज्य सरकारों में सभ्य विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाये जाने के लिए परिचालित करेगी ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि सिफारिशों को पढ़ने से पता चलता है, उनमें यह सुझाव नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति सभी विश्वविद्यालयों के विजिटर हों; यह व्यवस्था केवल केन्द्र के अधीनस्थ विश्वविद्यालयों के लिये है। विश्वविद्यालयों सम्बन्धी विषय राज्य-सूची का विषय है और राष्ट्रपति के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों का विजिटर बनना कठिन है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : सभ्रू समिति ने यह सिफारिश की है।

श्री मु० क० चागला : सभी राज्यों के लिये नहीं।

श्री रंगा : इसका यह मतलब नहीं कि आप ऐसा न करें।

**Shri Sarjoo Pandey :** In the fourth para of the statement it is said that the committee is unable to recommend any one pattern for the appointment of a Vice-Chancellor. There are so many ways for that. I want to know the suggestions being considered by the Government specially in regard to the appointment of a Vice-Chancellor and the recommendations which they are going to accept ?

श्री मु० क० चागला : समिति ने दो सुझाव दिये हैं। एक नए विश्वविद्यालयों के लिये और दूसरा पुराने विश्वविद्यालयों के लिये। इस समय मेरी अपनी प्रतिक्रिया यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने वाइस चांसलर नियुक्त करने का जो तरीका अपनाया है वह सबसे अच्छा रहा है। हम बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक में इसी प्रकार का संशोधन करेंगे।

**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या इस समिति ने उच्च स्तर के ऐसे स्वायत्त कालिजों की स्थापना के बारे में विचार किया है जिनमें अध्यापकों को वही वेतन और सुविधाएं प्राप्त हों जो विश्व-विद्यालय के अध्यापकों को मिलती हैं।

**श्री मु० क० चागला :** जहां तक वेतन का संबंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न हाल में ही कालिज-अध्यापकों के वेतन क्रमों को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव दिये हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में या किसी अन्य रिपोर्ट में कालिजों को स्वायत्त बनाने के लिये कोई सुझाव नहीं दिये गये हैं। अमरीका में कुछ कालिज ऐसे हैं जिनकी स्थिति विश्वविद्यालयों जैसी है। हमारे देश में वह प्रणाली नहीं अपनाई गई है।

**Shri Madhu Limaye :** I want to draw the attention of the Hon. education Minister to item No. 14(d) of the statement wherein it is stated that there should be provision to enable colleges to try out new methods and courses. There is great demand of colleges in cities, where most of the people are employed. They want to know whether there would be morning or evening shifts in colleges. To meet this demand whether the Hon. Minister of Education or this Committee is ready to recommend that there should be morning and evening both shifts in every college.

**श्री मु० क० चागला :** मैं इस बात से सहमत हूँ। उच्चतर शिक्षा की बड़ी मांग है और विश्व-विद्यालयों पर बड़ा दबाव डाला जा रहा है जिसके फल स्वरूप स्तर गिर रहा है। अतः हमारी योजना है कि यथासंभव तेजी से डाक द्वारा शिक्षा को फैलाया जाए और सवेरे और शाम को अंश-कालिक कालिज खोले जाएं।

**Shri Bade :** May I know whether in view of the report of this committee for Model Act for universities, the universities will become federal or they would remain unitary. There is a demand for quite a long time in the country that there should be Rural and Federal universities. Just now the Hon. Minister has stated that Model Act is meant for federal universities.

**श्री मु० क० चागला :** जी नहीं। यह फ़ेडरल विश्वविद्यालयों के लिये नहीं है। रिपोर्ट की एक प्रति हर राज्य सरकार को भेज दी गई है और विचार यह है कि जिस हद तक राज्य सरकारें सहमत हों, इनको अपने विश्वविद्यालय कानून में संशोधन करना चाहिये ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय अंशतः एक फ़ेडरल विश्वविद्यालय है। यह रिपोर्ट फ़ेडरल विश्वविद्यालयों के बारे में नहीं है।

**Shri Tulsidas Jadhav :** Today in colleges or universities, students do not stress much upon text books but try to find out some guide to getting through the examinations. Has it come to the knowledge of the Central Government and if so, the steps taken by the Government in this respect ?

**श्री मु० क० चागला :** सस्ती पाठ्य पुस्तकें छापने और प्रकाशित करने की हमारी तीन योजनाएँ हैं। एक अमरीका के सहयोग से दूसरी ब्रिटेन के सहयोग से और तीसरी रूस के सहयोग से हम यह महसूस करते हैं कि हमारे विद्यार्थी कालिजों में इस्तेमाल होने वाली पाठ्य-पुस्तकों का मूल्य नहीं दे सकते। लेकिन जहां तक पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित करने का सम्बन्ध है हर विश्वविद्यालय स्वायत्त है और यह काम विश्वविद्यालय का है। इसको कोई भी नियमित नहीं कर सकता कि विद्यार्थी पाठ्य-पुस्तकें पढ़ें या उनकी कुंजी पढ़ें।

## अध्यापकों के वेतन क्रम

+

\* 547. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :  
 श्री प्र० चं० बरुआ :  
 श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :  
 श्री कृ० चं० पन्त :  
 श्रीमती राम बुलारी सिन्हा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारने विश्वविद्यालयों और कालिजों के अध्यापकों तथा कालिजों और स्कूनों के अध्यापकों के वेतनों के बीच के वर्तमान अन्तर को कम करने के विचार का समर्थन किया है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तीसरी पंचवर्षीय योजना में खोले गये नये कालेजों के अध्यापकों के वेतनों को बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये सहमत हो गया है ; और

(ग) यह सहायता सम्बन्धित संस्थाओं को किन शर्तों पर तथा कितने समय के लिए दी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) तीसरी पंच वर्षीय आयोजना में स्थापित कालेजों को उनके अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर रहा है।

(ग) योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता, इस योजना को कार्यान्वित करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए हिस्से के आधार पर अर्थात् पुरुषों के कालेजों के लिए 50 प्रतिशत तक तथा महिलाओं के कालेजों के लिए 75 प्रतिशत तक सीमित है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को स्वीकार करते हुए कि अध्यापक हड़तालें और सत्याग्रह करने में अन्य लोगों की तुलना में सबसे पीछे हैं, क्या माननीय मंत्री जी ने विश्वविद्यालयों को कहा है कि उनसे अच्छा व्यवहार करना अनिवार्य है ?

श्री मु० क० चागला : मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि अध्यापकों को अनुशासन के बारे में विद्यार्थियों के समक्ष एक उदाहरण पेश करना चाहिये, और अध्यापकों द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही करना एक बहुत ही गलत तरीका है। यदि हमारे अध्यापकों में ही अनुशासन नहीं होगा, तो हम विद्यार्थियों से अनुशासन की आशा कैसे कर सकते हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अध्यापकों को अत्याधिक विद्यार्थियों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, क्या माननीय मंत्री जी ने विश्वविद्यालयों को बताया है कि अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच अनुपात नियत किया जाना चाहिये तथा अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिये मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिये ?

श्री मु० क० चागला : प्रश्न के पहले भाग से मैं सहमत हूँ कि विद्यार्थी अध्यापक अनुदात बहुत अधिक है और यह कम होना चाहिये परन्तु इसके लिये हमें अधिक धन और कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में उत्तर यह है कि विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के कल्याण की कई परियोजनाएँ हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस प्रयोजन के लिये कालेजों तथा विश्वविद्यालयों की सहायता कर रहा है।

श्री प्र० चं० बहग्रा : क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की सामाजिक सेवा समिति ने अध्यापकों को मिलने वाले अपर्याप्त वेतन के बारे में अप्तोष प्रकट किया है और यदि हाँ, तो समिति ने अध्यापकों के वेतन के ढाँचे में कौनसी त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया है और उन त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री मु० क० चागला : स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में केवल विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण किया था। मुझे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में पुनरीक्षण करने के बारे में अभी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण सिकारिश यह है कि यदि अर्हताएँ समान हों तो विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में, जहाँ तक सम्भव हो, असमानता नहीं होनी चाहिये। दूसरे शब्दों में यह कि विश्वविद्यालय अध्यापक तथा कालेज अध्यापक को उसकी अर्हता के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिये न कि इस कारण से कि वह विश्वविद्यालय में अथवा कालेजों में पढ़ाता है। परन्तु यह रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है और हमने इस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की है :

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध न केवल विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतनक्रमों के पुनरीक्षण से है परन्तु स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रमों में पुनरीक्षण तथा उनको बढ़ाने, विश्वविद्यालयों और स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में अन्तर को दूर करने से भी है। प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्कूल के अध्यापकों से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु मैं यह बता सकता हूँ कि स्कूल के अध्यापकों के लिये हमने क्या किया है। तीसरी योजना के दौरान हम उस प्रत्येक राज्य को अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाने के लिये 50 प्रतिशत सहायता देते रहे हैं जिसने अध्यापकों का वेतन बढ़ाया है और बहुत से राज्यों ने इस पेशकश से लाभ उठाया है।

**Shri Siddheshwar Prasad :** The hon. Minister has just said that the Government have been trying to upgrade the pay scales of teachers; would they lay a statement on the Table of the House showing the disparity among the pay scales of teachers 15 years ago *vis-a-vis* the position to-day? What was the difference between the pay scales of teachers of States' universities and those of central universities 15 years ago *vis-a-vis* the disparity between the present pay scales?

**Mr. Speaker :** Can the hon. Minister lay the statement on the table giving the requisite information of fifteen years ago?

श्री मु० क० चागला : क्या मेरे माननीय मित्र विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों अथवा प्रारम्भिक स्कूलों अथवा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों अथवा सभी के

वेतनक्रमों का विवरण चाहते हैं ? मैं एक विवरण तैयार करूंगा और समा पटल पर रख दूंगा। परन्तु मुझे यह पता नहीं लगा कि मेरे माननीय मित्र क्या चाहते हैं।

**Shri Sidheswar Prasad :** The hon. Minister just said that he had been trying to reduce the disparity some how, may I know whether a statement would be laid on the Table of the House ?

**Mr. Speaker :** A statement giving the requisite information may be laid on the Table of the House .

**श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** वह राज्य कौनसा है जिसमें विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों और कालेजों तथा स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में सबसे अधिक अन्तर है और इस अन्तर को दूर करने के लिये कितनी अनुमानित राशि की आवश्यकता पड़ेगी ?

**श्री मु० क० चागला :** जहां तक मैं जानता हूं, उत्तर प्रदेश के प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को सबसे कम वेतन मिलता है। विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के राज्यवार वेतनों में अन्तर के बारे में मुझे आंकड़े तैयार करने पड़ेंगे।

**श्री दी० चं० शर्मा :** कालेजों के अध्यापक तीन श्रेणियों में आते हैं : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापक, राज्य विश्वविद्यालयों के अध्यापक, और सम्बद्ध कालेजों के अध्यापक। इन श्रेणियों के अध्यापकों के वेतनक्रमों में बहुत भारी अन्तर है। क्या चौथी योजना में एक और दूसरे तथा दूसरे और तीसरे के वेतनक्रमों के अन्तर को पूरा करने के लिये कोई प्रयत्न किया जायेगा ?

**श्री मु० क० चागला :** मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। हमारा उद्देश्य यह है कि प्रत्येक कालेज के अध्यापक को उसकी अर्हता के अनुसार वेतन दिया जाये। यदि उसकी अर्हता अधिक है तो उसे वेतन भी अधिक मिलना चाहिये।

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** माननीय मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि जब भी कोई राज्य सरकार माध्यमिक स्कूल अध्यापकों के वेतनक्रमों में वृद्धि करेगी उसको 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। वह राज्य कौन से हैं जिन्होंने वेतनक्रमों में वृद्धि नहीं की है और जिन्होंने अनुदान लेने से इन्कार कर दिया है ?

**श्री रंगा :** और क्यों ?

**श्री मु० क० चागला :** मेरे विचार में प्रत्येक राज्य ने न केवल माध्यमिक स्कूलों के लिये परन्तु प्रारम्भिक स्कूलों के लिये भी अनुदान लिया है। समस्या यह है कि वे इससे भी अधिक सहायता चाहते हैं, वे कहते हैं कि वे 50 प्रतिशत राशि भी जुटाने की स्थिति में नहीं हैं। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रमों में वृद्धि करने के लिये तीसरी योजना की कालावधि में क्रमशः 8.34 करोड़ तथा 3.3 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई थी। तथ्य तो यह है कि इन योजनाओं पर वास्तविक व्यय इससे बहुत अधिक हुआ था। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये वास्तव में क्रमशः 22.94 करोड़ तथा 14.63 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

**Shri Hukam Chand Kachhavaia :** The teachers of those schools which are given 95% aid do not get their pay. When they reported this matter to the Education Department authorities, Shri Balmiki, hon. member of our Parliament went there and said that in case any action would be taken,

he would get the officer concerned removed from service as he had access to the Prime Minister not only this, the teachers were got beaten through the sanitary staff of Lok Sabha and when they went to the police station to report this matter, the police did not take any action because that member of Parliament had also repeated the same thing there ?

श्री मु० क० चागला : मेरा देहली के स्कूलों से कोई सम्बन्ध नहीं है . . . .

**Mr. Speaker :** The question was about disparity between pay scales of teachers but the hon. Member is asking about beating etc.

**Shri Hukam Chand Kachhavaia :** They asked for the salary which they did not get...

**Mr. Speaker :** The question is about the disparity between pay scales of teachers.

श्री हेम बहूआ : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को कुछ निश्चित समय तक अनुदान देने की पेशकश की है उसके पश्चात् वे अनुदान नहीं देंगे । क्या सरकार विशेषतया माननीय मंत्री जी इससे अवगत हैं कि कुछ विश्वविद्यालयों और कालेजों को एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि निश्चित समय के पश्चात् अनुदान न मिलने पर अध्यापकों को वही पुराना वेतन दिया जाता है ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां; मैं इस दुखपूर्ण समस्या से अवगत हूँ । गैर-सरकारी कालेजों के कई अध्यापकों के शिष्टमण्डल मुझे मिलने आये थे । विचार यह था कि जब यह अनुदान बन्द कर दिया जायेगा तो राज्य सरकार 50 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत अनुदान देगी । परन्तु मुझे ऐसे मामलों का पता है जिनमें राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जिम्मेदारी को नहीं सम्भाला । परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साधन भी सीमित ही हैं । यह राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को स्पष्ट कर दिया गया था कि अनुदान केवल 5 वर्ष तक के लिये दिया जायेगा और तत्पश्चात् इस व्यय को जुटाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार भारत के नागरिकों की विभिन्न श्रेणियों की योग्यताओं, अर्हताओं और जिम्मेदारियों के बीच वर्तमान अन्तर को कम करने के पक्ष में है ? यदि हां, तो कब ?

अध्यक्ष महोदय : श्री वासुदेवन नायर ।

श्री कपूर सिंह : माननीय मंत्री उत्तर देना चाहते हैं . . . . .

श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार इससे अवगत है कि कई विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों में सरकारी कालेजों की तुलना में गैर-सरकारी कालेजों की संख्या अधिक है और उन कालेजों में कई अध्यापक कई कारणों से कष्ट सहन कर रहे हैं जिनमें से एक कारण यह है कि प्रबन्धकर्ता उनका शोषण करते हैं ? वे महसूस करते हैं कि गैर-सरकारी कालेजों में अध्यापकों की भारी संख्या को देखने वाला कोई नहीं है । क्या सरकार उनके लिये कुछ करने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि 85 प्रतिशत विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वे गैर-सरकारी कालेजों में हैं और इसी लिये

ही तो मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वेतनक्रमों के पुनरीक्षण करने के बारे में कहा है। मुझे पता है कि उनमें से कइयों को बहुत कम वेतन मिल रहा है। मेरे विचार में हम उच्च शिक्षा में तब तक सुधार नहीं कर सकते जब तक हम कालेज के अध्यापकों की स्थिति नहीं सुधार सकते।

**श्री जयपाल सिंह :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई राज्य इतना अनुदान नहीं दे सकते हैं, तो सरकार इस अनुपात को क्यों नहीं बदल देती ?

**श्री मु० क० चागला :** चौथी योजना में हम इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि अनुदान जुटाने के लिये कोई अन्य ढंग अपनाया जाये क्योंकि राज्य सरकारें हमारे मुकाबले में अनुदान देने की स्थिति में नहीं हैं।

**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :** माननीय मंत्री अफ्रीका के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों से क्या सीखना चाहते हैं जो अपने अध्यापकों को उच्चतम वेतनक्रम देते हैं ?

**श्री मु० क० चागला :** मैं तो हमेशा सीखने के लिये तैयार हूँ और मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम अपने अध्यापकों से अपने चपरासियों की तुलना में अच्छा व्यवहार करें।

**Shri Sheo Narain :** In view of the fact that strike of teachers is going on in many states of the country because of defects in the educational system, is the hon. Minister ready for this thing that the Government should take over its management after nationalising it ?

**Mr. Speaker :** It is only a suggestion.

**Shri Yashpal Singh :** Are the Government aware that the teachers of intermediate classes in U.P. get half of what the teachers of intermediate classes in Delhi get and since their pay scale is so low that thousands of teachers are on strike there and they have boycotted the examinations; is so, what step are being taken by the Government to remove this disparity ?

**Shri M. C. Chagla :** I have asked the U.P. Government to raise the pay scales of teachers there and we would give them 50% assistance. Under the Plan we cannot give them more than 50% . I have also pointed out them that it is not good for teachers to indulge in direct action.

हम उनकी मांगों पर सहानुभूति से विचार करेंगे जब वे इस प्रत्यक्ष कार्यवाही को वापस ले लेंगे।

**Shri Sarjoo Pandey :** The Education Minister said that he had asked the U.P. Government that they would give 50% assistance; may I know the demand put forward by the U.P. Government to meet the demands of the teachers ?

**श्री मु० क० चागला :** राशि तो बहुत अधिक है परन्तु हमने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को वचन दिया है कि 50 प्रतिशत सहायता के अतिरिक्त हम इस बारे में सहानुभूति से विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या हम उत्तर प्रदेश से एक विशेष मामले के रूप में व्यवहार कर सकते हैं परन्तु उस हालत में पहली शर्त यह है कि अध्यापक इस प्रत्यक्ष कार्यवाही को वापस लें। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी उनसे अपील की है। प्रधान मंत्री मुझे और उत्तर प्रदेश

के शिक्षा मंत्र को उनसे सहानुभूति है परन्तु हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उनकी यह प्रत्यक्ष कार्यवाही जारी है।

**Shri R.S. Tiwary :** The hon. Minister has expressed sympathy for the Secondary and college teachers. May I know whether the same treatment would also be meted out to the primary school teachers and when he would be able to take an early step in this regard.

**श्री मु० क० चागला :** यदि मेरे माननीय मित्र का आशय यह है कि हम प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों जितना वेतन कब दे सकेंगे, तो मैं नहीं जानता वह कब सुनहरी जमाना आयेगा, मेरे जीवन काल में तो यह निश्चय ही नहीं आयेगा।

### Mahatma Gandhi Birth Centenary

\*548. { **Shri K. C. Pant:**  
**Shri Sidheshwar Prasad:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the question of celebrating Mahatma Gandhi's birth centenary is under consideration of the Ministry;

(b) if so, the broad outline of the programme, if any, formulated in this behalf; and

(c) whether the question of celebrating it as a national festival in foreign countries has also been considered?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :** (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

**Shri Sidheshwar Prasad:** I want to know what are the obstacles before the Government in celebrating Gandhi's Birth Centenary as a national festival and what are the reasons for not taking a positive decision in this connection.

**श्री मु० क० चागला :** बाधाओं का कोई प्रश्न नहीं है। गांधी स्मारक निधि, जिसके श्री दिवाकर सभापति हैं, ने गांधी जन्म शताब्दी को मनाने का कार्य अपने हाथ में लिया था। हमारे विचार में गांधी जी किसी एक दल या सरकार से सम्बन्धित नहीं थे; वह राष्ट्रपिता थे, अतः राष्ट्र को इस शताब्दी को मनाना चाहिये। पहले भी 1857 की शताब्दी का संगठन किया गया था। उँगोर शताब्दी का आयोजन, स्वर्गीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक पंजीकृत निकाय ने किया था। मोतीलाल नेहरू शताब्दी का आयोजन एक गैर-सरकारी एजेन्सी ने किया था और विवेकानन्द शताब्दी का आयोजन रामकृष्ण मिशन ने किया था। इस समारोह को विश्वविख्यात करने के लिये यह मंत्रालय कुछ सहायता दे सकता है। मैंने श्री दिवाकर को बता दिया था कि वह इस मंत्रालय से सहायता की आशा कर सकते हैं। सुझाव यह है कि क्या सरकार इसका स्वयं आयोजन करे। यह हमारे लिये कठिन है क्योंकि एक पंजीकृत संस्था इस कार्य को पहले ही कर रही है।

**Shri Sidheshwar Prasad:** It is a matter of great surprise that the Government is not taking any proper decision about it. Keeping in view that the Government is assisting Gandhi Samarak Nidhi in this programme, I want to

know what programme has been chalked out by the Gandhi Samarak Nidhi and to what extent the Government is going to assist it.

**श्री मु० क० चागला :** मार्च, 1964 को श्री दिवाकर ने मुझे लिखा कि 1969 में होने वाले गांधी जन्मदिन को मनाने के लिये विस्तृत कार्यक्रम, दोनों दीर्घावधि और छोटी अवधि के लिये, तैयार करने के लिये निधि ने एक तैयारी समिति की नियुक्ति की है; उन्होंने यह भी लिखा था कि वह योजना पहले ही तैयार करना चाहते हैं जिससे योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने के लिये सभी स्तरों पर, राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर यथोचित व्यवस्था की जाय; कि कुछ सुझाव और प्रस्ताव पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और यदि शिक्षा मंत्री कुछ समय निकाल सकें तो अपने सुझाव दे दें और सभी सुझावों के प्राप्त होने पर तैयारी समिति उनकी जांच करेगी और अन्ततः सुझावों को एक राष्ट्रीय समिति के सामने रख देगी जिसका उस कार्य के लिये गठन किया जायेगा। मैंने भी अपने सुझाव दिये हैं। अब समिति प्राप्त सुझावों की जांच करेगी और अब निधि का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय समिति का गठन करे।

**Shri Radhey Lal Vyas :** The way Tagore Centenary was celebrated and the Government prepared all its programmes, could the government not prepare any scheme along with Gandhi Samarak Nidhi to celebrate the Mahatma Gandhi Centenary.

**Shri M. C. Chagla:** As I had already told, we are prepared to help the Nidhi.

**Shri A. P. Sharma:** Have the Government prepared some scheme ?

**Shri M. C. Chagla:** Nidhi is preparing the scheme.

**Mr. Speaker:** It is a suggestion.

**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या सरकार के पास यह सुझाव भी आया है कि, क्योंकि राष्ट्रपिता देश में मद्य-निषेध लागू करने के बहुत इच्छुक थे, उस समय तक सारे देश में पूर्ण मद्य-निषेध लागू हो जाना चाहिये।

**श्री मु० क० चागला :** यह सुझाव मुझे प्राप्त नहीं हुआ।

**श्री रघुनाथ सिंह :** इस समारोह में सरकार की ओर से क्या तैयारी हो रही है।

**श्री मु० क० चागला :** मैं मंत्रालय की ओर से उत्तर दे रहा हूँ न कि सम्पूर्ण सरकार की ओर से।

**श्री रघुनाथ सिंह :** मेरा विचार था कि मंत्रालय और सरकार एक ही हैं।

**श्री मु० क० चागला :** मैं अपने दायित्व से नहीं बचना चाहता। मैंने प्रश्नों का उत्तर देते समय बताया था कि मंत्रालय ने क्या किया है। परन्तु मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में सब दलों की एक समिति बनाई जाय।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न-काल में मंत्री महोदय से केवल उन्हीं के विषय के सम्बन्ध में पूछा जा सकता है। परन्तु उनको यह अवश्य पता होगा कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है।

श्री मु० क० चागला : निधि जो कर रही है उसके अतिरिक्त सरकार की कोई योजना नहीं है। परन्तु मैं इस ओर ध्यान दूंगा और यह प्रयत्न करूंगा कि सभी दलों की सरकार एक समिति बनाये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : हमें यह तर्क सुन कर बहुत दुःख हुआ है कि क्योंकि वह पार्टी के ओर सरकार के नेता नहीं थे इसलिये इसे सरकारी तौर पर नहीं मनाया जायेगा। क्या उनका कहने का यह मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दल से सम्बन्धित हो तभी उसकी शताब्दी मनाई जा सकती है और न कि इसलिये कि वह राष्ट्रपिता थे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या इस विषय पर मंत्रिमंडल स्तर पर विचार हो चुका है और उसे न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिये क्या सरकार ने गंभीर रूप से विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : हम इसका कारण जानना चाहते हैं।

श्री हेम बरुआ : भारतीय संस्कृति के अनुसार और विशेषतया हिन्दू संस्कृति के अनुसार मृत्यु बरसी नहीं बल्कि जन्म बरसी मनाई जाती है और मृत्यु बरसी मनना प्राधुनिक विचार है जो पाश्चात्य प्रभाव के कारण है। क्या सरकार ने समस्या के उस दृष्टिकोण पर भी विचार किया है या नहीं ?

श्री मु० क० चागला : जी नहीं। सरकार ने इस पहलू पर विचार नहीं किया।

श्री दी० चं० शर्मा : शिक्षा मंत्री, जो न कि सरकार बल्कि अपने मंत्रालय की ओर से बोल रहे हैं, ने कहा था कि उन्होंने श्री दिवाकर को कुछ सुझाव दिये थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि उन्होंने क्या सुझाव दिये थे ?

श्री मु० क० चागला : मैं ने कहा था कि गांधी जी के आदर्श के प्रचार के लिये वर्तमान कार्यक्रम को और विस्तृत बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जाये। श्री दिवाकर ने मेरे पत्र पढ़ने की सूचना देते हुये कहा कि वह मेरे सुझाव के लिये आभारी हैं और वह इस पर विचार करेंगे। क्योंकि यह शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित था इसलिये मैंने यह सुझाव दिया था।

**Shri Madhu Limaye:** Whenever the matter is regarding Mahatmaji, Sardar Patel, or Subhash Babu, we find that the Government is complacent..

**Some hon. members:** No, No.

**Shri Madhu Limaye:** Leave it of. It is not correct. Will the Government suggest to the committee that the noblest part of Mahatma Gandhi's life—the lesson of civil disobedience which he gave to the poor and oppressed, which is being followed in America also—should be made the central idea in celebrating his birth centenary. Would the Government have any such suggestion or not ?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय मित्र द्वारा दिये गये इस सुझाव का जोरदार शब्दों में खंडन करता हूँ कि सरकार इस शताब्दी को मनाने में अभिरुचि नहीं रखती है। यह सही नहीं है। मैं यह बता दूँ कि श्री दिवाकर के इस पत्र को प्रधान मंत्री जो को भेजा गया था।

**श्री रंगा :** आपने ही तो इन सुझावों तथा इस शंका के लिये गुंजाइश रखी ।

**श्री मु० क० चागला :** श्री दिवाकर के उस पत्र को प्रधान मंत्री के पास भेजा गया था । उनका उत्तर यह है :

“हम इस मामले पर निःसन्देह विचार करेंगे और सरकार इस शताब्दी को सफल बनाने के लिये अवश्य ही हर सम्भव कार्य करेगी ।”

मेरे माननीय मित्र द्वारा दिये गये विभिन्न सुझाव उस समिति के समक्ष रखे जायेंगे जिसको इस शताब्दी को मनाने के लिये स्थापित किया जायेगा ।

**श्री रंगा:** यहां पर दिये गये सुझावों की दृष्टि से मंत्री द्वारा स्थिति पर पुनः विचार करने की तत्परता के लिये हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं । यदि मंत्रीजी ने उत्तर तैयार करने से पूर्व इस नये वातावरण तथा नये ढंग को सुझाया होता तो हम उसकी सरहाना करते । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर की शताब्दी मनाई गई थी तो उस समय इसको मनाने में शान्ति निकेतन के अतिरिक्त सारे भारत में से कई अन्य संस्थायें भी अभिरुचि रखती थीं, ऐसा होते हुए भी भारत सरकार ने मेरे माननीय मित्र श्री हुमायूँ कबिर के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन चलाया था, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या माननीय मित्र शिक्षा मंत्रीजी मंत्रिमण्डल से सलाह करने की कृपा करेंगे और इस शताब्दी को न केवल शिक्षा मंत्रालय की ओर से परन्तु राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिये सारे राष्ट्र तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से एक निर्णय करेंगे, विशेष रूप से मानव अधिकारों के कारण से, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हरिजनों तथा दलित लोगों के लिये बहुत कुछ किया, जिन के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकारों की समिति है।

**श्री मु० क० चागला :** मैं यह बता दूँ कि टैगोर शताब्दी स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक पंजीकृत निकाय द्वारा मनाई गई थी जिसके लिये सरकार ने आर्थिक सहायता दी । इस बारे में भी मैंने कहा और उसे पुनः दुहराता हूँ कि सरकार यह देखने के लिये हर सम्भव कार्य करेगी कि गांधीजी की शताब्दी न केवल भारत में ही परन्तु सारे संसार में पूर्ण सफलता से मनाई जाये ।

### विश्वविद्यालय शिक्षा में सैनिक पाठ्यक्रम

\* 549. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या शिक्षा मंत्री 23 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 654 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में सैनिक पाठ्यक्रम को अध्ययन का एक विषय बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन देने में अनावश्यक विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) समिति के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इस समस्या के कुछ पहलुओं से सम्बन्धित एक प्रश्नावली विभिन्न विश्वविद्यालयों के पास भेजी गई थी । बहुत से विश्वविद्यालयों से

अभी उत्तर आने बाकी हैं। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले समिति सम्भवतः कुछ विश्व-विद्यालयों का दौरा करे।

**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच नहीं है कि संसार के उन बड़े स्वतंत्र देशों में से भारत ही एक ऐसा देश है, जिसको सैनिक रूप से खतरा है और जो अब भी घिरा हुआ है, जिसमें सैनिक पाठ्यक्रम को किसी विश्वविद्यालय की पाठ्यचर्या में शामिल नहीं किया गया तथा अब भी शामिल नहीं है; और यदि हां, तो इस अवहेलना तथा उदासीनता के क्या कारण हैं ?

**श्री मु० क० चागला :** इस सम्बन्ध में कोई अवहेलना अथवा उदासीनता नहीं है। मैं माननीय मित्र से सहमत हूँ कि हमारे देश में विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों में से एक विषय सैनिक पाठ्यक्रम होना चाहिये। इसीलिये तो मैंने बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति नियुक्त की है और इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है। पहले कि हम किसी विश्व-विद्यालय में किसी विषय को आरम्भ करें, हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या हमारे पास अपेक्षित उपकरण, कर्मचारी तथा सुविधायें भी हैं। जब तक इससे हम न्याय नहीं कर सकते तब तक इस विषय को आरम्भ करने का कोई लाभ नहीं होगा।

**श्री हरि विष्णु कामत :** पिछले 17 वर्षों में आप क्या करते रहे हैं ?

**श्री मु० क० चागला :** मैं 17 वर्षों के बारे में कुछ नहीं जानता। इसकी ओर हमारा ध्यान केवल 1963 में आकर्षित किया गया था जब बिहार राज्य शिक्षा आयोग ने सैनिक पाठ्यक्रम को एक विषय के रूप में डिग्री के प्रथम प्रकरण में आरम्भ करने के लिये एक प्रस्ताव रखा था। तभी से हम इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और मैं माननीय मित्र को विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस विषय को, जहां तक सम्भव हुआ, अत्यधिक विश्वविद्यालयों में आरम्भ करने का प्रयत्न करेंगे।

**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या दूर दूर फैले इस विश्वास अथवा शंका में काफी सचाई है कि 1962 में हुए चीनी आक्रमण से आई अति जागरूकता की आकस्मिक स्फुरण और इस बारे में आये विचार के पश्चात् सरकार में चीनियों द्वारा आरोपित एक पक्षीय युद्ध विराम के कारण निद्रालुता तथा आत्मतुष्टि की भावना आ गई है, और सरकार में इस मामले के बारे में शिथिलता का वास्तविक कारण भी यही है ?

**श्री मु० अ० चागला :** जी, नहीं, मैं इस सुझाव का प्रत्याख्यान करता हूँ। चीनी आक्रमण से निद्रालुता आने की बजाय हमें उत्तेजना मिली है . . . . .

**श्री हरि विष्णु कामत :** उन्होंने मेरा प्रश्न ही नहीं सुना है। मैंने कहा है कि युद्ध विराम के फलस्वरूप आत्मतुष्टि की निद्रालुता आ गई है।

**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने इसे अच्छी तरह सुना है।

**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमन्, मेरे विचार में अच्छी तरह नहीं सुना।

**श्री मु० क० चागला :** इससे न ही निद्रालुता आई है और न ही आत्मतुष्टि प्राप्त हुई है। इसके विपरीत इस खेदजनक आक्रमण से हमें अपने देश में सैनिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिये उत्तेजना मिली है।

**श्री नाथ पाई :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति के कार्य को अन्तिम रूप देने से पहले, क्या सरकार उन विश्वविद्यालयों जैसे पूना विश्वविद्यालय को अनुदान देने की वांछनीयता तथा औचित्य पर गम्भीरता से विचार करेगी, जिसने इस विषय की महत्ता तथा इसकी राष्ट्रीयता प्रतिरक्षा से सम्बन्ध को महसूस करते हुए सैनिक पाठ्यक्रम को अध्ययन का विषय बनाया है और क्या इस बारे में वही प्रक्रियात्मक विलम्ब से, जिसमें यह मंत्रालय निपुण है, इस मामले को अलग रख दिया जायेगा और क्या इसमें कोई पहल दिखायी जायेगी ?

**श्री मु० क० चागला :** यदि कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें यह विषय पढ़ाया जा रहा है, तो मैं निस्संदेह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सुझाव दूंगा कि उसकी आवश्यक सहायता की जाये ।

**श्री श्याम लाल सराफ :** श्री नाथ पाई ने मेरे प्रश्न को आंशिक रूप से पूछ लिया है । सभी विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में राष्ट्रीय छात्र सेना आरम्भ की गई है, इसलिये क्या सरकार कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में सैनिक पाठ्यक्रम को आरम्भ करने के बारे में अन्तिम निर्णय करने तक इस संचलन को अधिक से अधिक राशि की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया है ?

**श्री मु० क० चागला :** प्रतिरक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय छात्र सेवा के लिये वित्त की व्यवस्था करती है । परन्तु सैनिक पाठ्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बारे में विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ।

**Shri Jagdev Singh Siddhanti:** Would the Government consider teaching of dancing and singing in schols and colleges for the name of cultural programmes and art should be discontinued and instead military training should be made compulsory ?

**श्री मु० क० चागला :** सैनिक पाठ्यक्रम तथा नाटक और संस्कृति दोनों ही आवश्यक हैं ।

**Shri Onkar Lal Berwa:** May I know the number of scholarships which were given in military schools in 1964?

**श्री मु० क० चागला :** जैसा कि मैंने बताया, सैनिक पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये अभी कोई योजना तैयार नहीं की गई है । अतः छात्रवृत्तियां देने का प्रश्न ही नहीं उठता । जब हम इस पाठ्यक्रम का अध्ययन उचित रूप से आरम्भ कर देंगे, तब छात्रवृत्तियां देने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

### माध्यमिक शिक्षा

550. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सारे देश में माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या माध्यमिक शिक्षा का कोई केन्द्रीय स्कूल स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

**शिक्षा मंत्री (श्र मु० क० चागला) :** (क) जी, हां ।

(ख) 1964 में शरू की गई योजना के अन्तर्गत, निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है :—

- (i) विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना ;
  - (ii) विज्ञान अध्यापकों का विशेष प्रशिक्षण और विज्ञान शिक्षा के यूनिट की स्थापना ;
  - (iii) स्कूल पुस्तकालयों का सुधार ;
- (ग) जी, नहीं ।
- (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या इस समय इस देश की माध्यमिक शिक्षा की सफलता के बारे में कोई निर्धारण किया गया है ; यदि हां, तो निर्धारण का क्या परिणाम निकला है ?

**श्री मु० क० चागला :** जैसा कि मेरे मित्र जानते हैं हमने माध्यमिक शिक्षा के बारे में मुदालियर समिति बनाई थी । हाल में ही हमने शिक्षा आयोग नियुक्त किया है । मैं आशा करता हूँ कि इसका प्रतिवेदन हमें अगले वर्ष मिल जायेगा और तभी मेरे माननीय मित्र को मालूम हो जायेगा कि इस विशेषज्ञ वर्ग ने क्या निर्धारण किया है ।

**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या सरकार को यह जानकारी है कि एक निश्चित बाधा आने के परिणामस्वरूप राज्य सरकारें अपने शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में तथा माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रमों में परिवर्तन करने में धन लगाने के लिए सक्षम नहीं हैं, यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का है कि शिक्षा नुविद्यार्थें बढ़ें क्योंकि कुछ राज्यों में यह सुविधायें लागू करने में विलम्ब हो रहा है ?

**श्री मु० क० चागला :** प्रश्न के दो भाग हैं । पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि राज्य जिस क्षेत्र में भी माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधार करना चाहते हैं केन्द्र उन सभी में सहायता देने को तैयार है । जहां तक दूसरे भाग अर्थात् अध्यापकों के वेतन बढ़ाने का सम्बन्ध है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी राज्य अध्यापकों के वेतन बढ़ाना चाहते हैं हम उनको इस बारे में होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत देने को तैयार हैं ।

**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** यह पर्याप्त नहीं है ।

**Shri Tulsi das Jadhav:** All those students who are coming out of High Schools cannot write or speak correct English. May I know whether Government has introduced any ways and means so that the standard of Education may rise ?

**श्री मु० क० चागला :** मुझे खेद है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है और इसलिए अब सरकार चाहती है कि माध्यमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाने का महत्व समझा जाये ।

**श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** ये माध्यमिक स्कूल क्या वैसे ही होंगे जैसे पहले थे अथवा 'बेसिक' होंगे ?

**श्री मु० क० चागला :** हम सभी चाहते हैं कि हमारे स्कूलों का स्तर अच्छा हो चाहे वह स्कूल प्राथमिक हो अथवा माध्यमिक ।

**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को विज्ञान लैबोरेटरी तथा शिक्षा में सुधार के लिए जो धन दिया है क्या उसका पूरा पूरा उपयोग कर लिया गया है ?

**श्री मु० क० चागला :** मेरे पास आंकड़े हैं। यदि मेरे माननीय मित्र यह जानना चाहते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में हमने विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता दी है तो मैं उसके बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दूंगा क्योंकि वह एक लम्बी सूची है।

**श्री कण्डप्पन :** क्या सरकार ऐसी पत्रिकाओं को सहायता देने को तैयार है जो विज्ञान सम्बन्धी जानकारी प्रदेशों की मातृभाषाओं में प्रकाशित करती है ?

**श्री मु० क० चागला :** जी हां। हम बच्चों के लिए विज्ञान सम्बन्धी साहित्य अपनी सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करना चाहते हैं और एक सीमा तक सहायता दे रहे हैं।

**श्री रंगा :** उन्होंने पूछा है कि क्या कोई प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये।

**Shri Yudhvir Singh:** We have been discussing this matter to raise the standard of Secondary education since some years and government has received Mudaliar Committee report in this connection. May I know whether all the recommendations of the Mudaliar Committee have been implemented or this committee is appointed due to the non-acceptance of these recommendations ?

**श्री मु० क० चागला :** सिफारिशें बहुत हैं। प्रश्न साधन जुटाने का था। जितना संभव था उतना हमने उनको लागू कर दिया है। मामले पर पुनः विचार करने के लिए नया आयोग नियुक्त किया गया है।

**श्री नाथ पाई :** मैं माननीय मंत्री के इस कथन का स्वगत करता हूँ कि उनका मंत्रालय बालकों की विभिन्न पत्रिकायें निकालने का विचार कर रहा है। क्या सरकार ने एक विस्तृत योजना तैयार की है कि उन आदर्शवादियों को सहायता दी जाये जो इस उद्देश्य से पत्रिकायें निकालते हैं कि हमारे बच्चों को सर्वोत्तम साहित्य मिलना चाहिए क्योंकि हमारा भविष्य उन्हीं के हाथों में है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है अथवा बनाने का विचार है ?

**श्री मु० क० चागला :** सी एस आई आर द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित विज्ञान पत्रिका हम निकालते हैं। हमारा विचार इसको प्रादेशिक भाषाओं में भी निकालने का है। हमने एक योजना यह बनाई है कि विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर सस्ते निबन्ध प्रकाशित किए जायें। अभी वह अंग्रेजी तथा हिन्दी में उपलब्ध हैं। हमने उनका प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने की योजना बनाई है।

**श्री नाथ पाई :** हमने यह स्वीकार कर लिया है कि सभी भारतीय भाषायें राष्ट्र भाषा हैं तथा प्रादेशिक भाषा नहीं हैं।

**श्री मु० क० चागला :** मैं गलती की माफी चाहता हूँ।

**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** गुजरात राज्य में बहुत से विज्ञान क्लब हैं। ये लगभग 300 से 400 हैं। क्या सरकार इन क्लबों को वित्तीय सहायता देने को तैयार है ?

**श्री मु० क० चागला :** जी हां । हमारी योजनाओं के अनुसार हम सहायता देने को तैयार हैं । माननीय सदस्य उन संस्थाओं से कहें कि वह अपनी योजनायें पेश करें । हम यह देखेंगे कि हम क्या सहायता दे सकते हैं ।

**Shri Lahtan Chaudhury:** May I know whether Government knows that the Bihar Government has decided to change all Secondary Schools into State subsidized Schools? The aid Central Government propose to give to State Governments in view of that?

**श्री मु० क० चागला :** मैं प्रश्न समझा नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न

**अखिल भारतीय कृषि सेवा**

+

- \* 551. { श्री क० ना० तिवारी :  
श्री विभूति मिश्र :  
श्री हेम राज :  
श्री प्र० चं० बरुआ :  
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :  
श्री रामेश्वर टांटिया :  
श्री विद्याचरण शुक्ल :  
श्री राम सहाय पाण्डेय :  
डा० चन्द्रभान सिंह :  
श्री उइके :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) अखिल भारतीय कृषि सेवा के गठन में क्या प्रगति हुई है ; और  
(ख) किन राज्य सरकारों ने इसके पक्ष में विचार व्यक्त किये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). भारतीय कृषि सेवा के गठन के लिये सारी राज्य सरकारें सिद्धांततः सहमत हो गई हैं । राज्य सभा के चालू अधिवेशन के दौरान इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 312 (1) के अधीन एक अध्यादेश प्रस्तुत किया जा रहा है ।

**Shri K. N. Tiwary:** what will be the pay scale for this Service. May I know whether that will be same as is given to I.A.S. and I.P.S. ?

**Shri Hathi:** The Officers in that Service will be designated as Directors of Agriculture, Additional Directors, Deputy Directors, Assistant Directors, etc. For higher grade the Pay scale will be Rs. 2000 to 2500 and for lower grade Rs. 400 to 1250.

**Shri K. N. Tiwari:** May I know whether the persons of these services will be employed in Agricultural Pilot Projects ?

**Shri Hathi:** Now we propose that the officers who are working in a post should be appointed in those posts.

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस सेवा की शर्तों तथा वेतन क्रमों में भारतीय प्रशासन सेवा की शर्तों तथा वेतन क्रमों में कितना अन्तर है ? क्या दोनों में कोई अन्तर है ?

श्री हाथी : वेतन क्रमों के बारे में मैं बता चुका हूँ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : दोनों में कितना अन्तर है ?

श्री हाथी : इसके गठन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पहले राज्य सभा में इस बारे में एक संकल्प पारित होगा तथा बाद में उसके बारे में संसद् में विधान बनाया जायेगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या चौथी योजना की क्रियान्विति से पहले अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ? उन राज्यों में क्या किया जायेगा जो इस सेवा के बमाये जाने का विरोध करती है ?

श्री हाथी : इस प्रस्ताव का किसी राज्य ने विरोध नहीं किया है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : अखिल भारतीय सेवा बनाने के क्या लाभ हैं ?

श्री हाथी : अन्य अखिल भारतीय सेवाओं को मिलने वाले लाभ इस सेवा को भी मिलेंगे।

श्री राम सहाय पांडेय : अखिल भारतीय कृषि सेवा में कितने अधिकारी होंगे ? परन्तु क्योंकि यह विषय राज्य का विषय है तो इस सेवा का लाभ आप कैसे उठायेंगे ?

श्री हाथी : यह सेवा भी आइ० ए० एस० तथा आई० पी० एस० सेवा के समान ही होगी। भरती किए जाने के बाद इन को विभिन्न राज्यों को बांट दिया जायेगा। उसके बाद इन को एक राज्य से दूसरे में स्थानान्तरित किया जायेगा ?

### प्रश्नों के लिखित उत्तर

#### WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बरौनी तेल शोधनशाला के निकट पेट्रो-केमिकल कारखाना।

\* 552. { श्री प्र० चं० बरुआ :  
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :  
श्री विभूति मिश्र :  
श्री द्वा० ना० तिवारी ।

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधनशाला के निकट एक पेट्रो-केमिकल कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है :

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस दिशा थे में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलमेशन) : (क) चौथी योजना की अवधि के दौरान में कार्यान्विति के लिये अस्थाई स्कीमें तैयार की गई हैं।

(ख) बेनजीन (benzene) और जाइलीन (xylene) जैसे एरोमैटिक पदार्थों (aromatics) का निष्कासन इन स्कीमों का मुख्य पहलू हो सकता है, तथा इन पदार्थों से अन्य अनुप्रवाही रसायनों के कारखाने बन सकते हैं जिनका यथा-समय परीक्षण किया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### दिल्ली की यातायात समस्याएँ

\* 553. { महाराज कुमार विजय आनन्द :  
श्रीमती लक्ष्मीबाई :  
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री भगवान सहाय के सभापतित्व में राजधानी की यातायात समस्याओं सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में देरी के क्या कारण हैं ; जिसने 1½ वर्ष पहले अपना प्रतिवेदन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है, तथा उन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

### तकनीकी शिक्षा का माध्यम

\* 554. { श्री विद्याचरण शुक्ल :  
श्री यशपाल सिंह :  
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :  
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :  
श्री विभूति मिश्र :  
श्री क० ना० तिवारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् ने यह सिफारिश की है कि इंजीनियरी और विज्ञान शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम रहना चाहिए ; और

(ख) क्या सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है ?

शिक्षा मंत्री (श्री सु० क० चागला) : (क) और (ख) : जी, हां।

## आसाम और नेफा के बीच सीमांकन

\* 555. श्री रवीन्द्र वर्मा :  
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने यह सुझाव दिया है कि आसाम और नेफा के बीच औपचारिक रूप से सीमा का रेखांकन किया जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार सुझावों को कार्यरूप देने के लिये क्या कदम उठाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## पैट्रो-कैमिकल उद्योग

\* 556. श्री मलाइछामी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 27 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रो-कैमिकल उद्योगों के विकास सम्बन्धी कार्यवाही दल के प्रतिवेदन पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगसेन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## Gandhi Harijan School, Madangiri, Delhi

\* 557. {  
Shri Hukam Chand Kachhaviya :  
Shri Prakash Vir Shastri:  
Shri Bade:  
Shri Sheo Narain:  
Shri Mate:  
Shri D. S. Patil:  
Shri S. M. Banerjee:  
Shri P. H. Bheel:  
Shri Madhu Limaye:  
Shri Sham Lal Saraf:  
Shri Jagdev Singh Siddhanti:  
Shri Y. D. Singh:  
Shri Gauri Shankar Kakkar:  
Shri U. M. Trivedi:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that teachers of Gandhi Harijan School, Madangiri, Delhi have not received their pay for the last one or one and a half years;

(b) whether it is also a fact that some of the teachers have been removed from service without assigning any reason therefor and some others have been got manhandled by goondas;

(c) whether Government have received any complaints from the teachers of that place and if so, the details thereof; and

(d) whether Government contemplate to take over the management of aforesaid school?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla):** (a) No, Sir.

(b) Some teachers were removed from service by the management, but were later reinstated, on the intervention of the Government. A couple of instances have been reported in which two teachers were involved in a scuffle with outsiders.

(c) Complaints regarding belated payment and non-payment of salaries, general unsatisfactory treatment of teachers, corruption and nepotism in the school management have been received.

(d) No, Sir. Consequent on the shifting of the school from Chanakayapuri to Madangiri, the school will now fall under the jurisdiction of the Delhi Municipal Corporation, and it will then be for the Corporation to consider this issue.

नागाओं द्वारा आसाम के निकट एक चाय बाग पर कब्जा

\* 558. { श्री रामेश्वर टांटिया :  
श्री प्र० चं० बरुआ :  
श्री राम हरख यादव :  
श्री मुरली मनोहर :  
श्री हुकम चन्द कछवाय :  
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागाओं ने आसाम राज्य क्षेत्र के पास एक चाय बाग पर बलात कब्जा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आगाओ नागाओं ने दावा किया है कि आसाम राज्य तथा नागालैंड के बीच बहुत पहले से एक सीमा विवाद चला आ रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नागाओ ने वन भूमि को साफ कर दिया है और आसाम सरकार को अनुमति के बिना उस भूमि में खेती शुरू कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो नागाओं तथा आसाम सरकार के बीच कोई संघर्ष न हो इसके लिये संघ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) . एक विवरण सभा हॉटल पर रख दिया गया है ।

#### विवरण

यह सच है कि आसाम और नागालैंड के बीच सीमा, विशेषतया आसाम राज्य के सिवसागर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में, के सम्बन्ध में कुछ सन्देह है ।

2. आसाम सरकार के अनुसार, इस क्षेत्र के नागा ग्रामीण आसाम राज्य के वन प्रदेश में घुस आते हैं। दूसरी ओर नागा ग्रामीण का यह दावा है कि यह क्षेत्र उन्हीं के गांवों का भाग है, अतः इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जताने के लिये वह इस भूमि पर अधिकार करते रहे हैं।

3. आसाम सरकार ने यह सभाचार दिया है कि 28 जनवरी, 1965 को नागालैण्ड के जापुकौंग क्षेत्र के कुछ नागा ग्रामीणों ने नागिनी चाय बागान में अनधिकार प्रवेश और वहां की भूमि पर कब्जा कर लिया। आसाम सरकार के अनुसार, 13 और 16 फरवरी, 1965 को भी इसी प्रकार के अनधिकार प्रवेश हुये थे। अब तक, इस क्षेत्र में नागाओं ने वृक्ष और बांस काट कर 150 एकड़ भूमि कृषि के लिये साफ कर दी है।

आसाम सरकार ने बताया है कि इस सम्बन्ध में मरायनी पुलिस स्टेशन में इन नागाओं के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये हैं और जांच की जा रही है, और 23 फरवरी, 1965 को 4 नागा गिरफ्तार किये गये थे।

### भंगियों की हड़ताल

- \* 559. { श्री द्वा० ना० तिवारी :  
 श्री नवल प्रभाकर :  
 श्री रा० गि० दुबे :  
 श्रीमती सावित्री निगम :  
 श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :  
 श्री प्र० चं० बरुआ :  
 श्री क० ना० तिवारी :  
 श्री हुकम चन्द कछवाय :  
 श्री भागवत झा आजाद :  
 श्री यशपाल सिंह :  
 श्री दी० चं० शर्मा :  
 श्री विभूति मिश्र :  
 श्री बड़े :  
 श्री ओंकार लाल बेरवा :  
 श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :  
 श्री मोहन स्वरूप :  
 श्री कोल्ला वैक्य्या :  
 श्री म० ना० स्वामी :  
 श्री राम सेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के भंगियों द्वारा दिसम्बर, 1964 के मध्य में यकायक की गई हड़ताल के कारणों का पता लगाया गया है तथा उन की जांच की गई है ;

(ख) उस में कितने भंगियों ने भाग लिया ; और

(ग) क्या हड़ताल करने वाले किन्हीं भंगियों को दण्ड भी दिया गया ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) 25 दिसम्बर, 1964 से 28 दिसम्बर, 1964 तथा 12 जनवरी, 1965 से 18 जनवरी, 1965 तक नगर निगम के भंगियों द्वारा की गई हड़ताल के कारणों का पता तथा उनकी जांच दिल्ली नगर निगम ने की है।

(ख) प्रथमावस्था में 2182 ने तथा द्वितीय अवस्था में 2562 ने।

(ग) उन सारे भंगियों को जिन्होंने हड़ताल की थी सेवा पर वापिस ले लिया गया, तथा उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई गई।

#### भूतपूर्व उप मंत्री के विरुद्ध जांच

\*560. { श्री यशपाल सिंह :  
श्री भगवत झा आजाद :  
श्री हरि विष्णु कामत :  
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :  
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :  
श्री कोया : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 6 जनवरी को पटना में वित्त मंत्रालय में भूतपूर्व उपमंत्री द्वारा सनाचार पत्र वालों को दिए गए इन्टरव्यू की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें भूतपूर्व उपमंत्री ने शिकायत की थी उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने तथा निष्कर्षों को घोषित करने में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) निर्णय कब घोषित किया जाएगा ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

## शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम

- \* 561. { श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :  
 श्री ज० ब० सिंह :  
 श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :  
 श्रीमती सावित्री निगम :  
 श्री रा० गि० दुबे :  
 श्री सुबोध हंसदा :  
 श्री स० चं० सामन्त :  
 श्री बाल्मीकी :  
 श्री राम हरख यादव :  
 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :  
 श्री द्वा० ना० तिवारी :  
 श्री राम चन्द्र उलाका :  
 श्री धुलेश्वर मीना :  
 श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मंत्री 2 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 309 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल फिटनेस कोर (राष्ट्रीय स्वस्थता दल) नामक शारीरिक शिक्षा के एकीकृत एक नए कार्यक्रम के अप्रैल, 1965 से चालू करने के प्रस्ताव पर विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है, जो शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय अनुशासन योजना और सहायक सेना छात्र दल (आग्नि-लियरी केडेट कोर) के वर्तमान कार्यक्रमों का सम्मिश्रण है ;

(ख) योजना के क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) राज्य सरकारों ने आम तौर पर नए कार्यक्रम का स्वागत किया है ।

(ख) राज्यों के शिक्षा सचिवों और शिक्षा निदेशकों की 27 फरवरी, 1965 को हुई बैठक में नए कार्यक्रम पर विचार किया गया था । नए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये प्रशासनिक और वित्तीय व्योरे तैयार करने के लिये समिति ने एक उप-समिति की नियुक्ति की । उप-समिति की सिफारिशों पर शीघ्र ही समिति की पूरी बैठक में विचार किया जाएगा । आशा है कि नया कार्यक्रम, वर्तमान राष्ट्रीय अनुशासन योजना अनुदेशकों, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों तथा ए० सी० सी० के उन अध्यापकों के सहयोग से जो नए कार्यक्रम में शामिल होना चाहें, 1965-66 के शिक्षा सत्र से अधिकाधिक स्कूलों में शुरू कर दिया जायेगा । नए कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये जिन अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा उनके लिए पुनरनुस्थापन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है ।

एम० ए० में तीसरी श्रेणी

62. { श्री प्र० चं० बरुआ :  
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एम० ए० और एम० एससी० में तीसरी श्रेणी समाप्त करने के प्रश्न पर अन्तिम विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित परीक्षा सुधार समिति ने अन्य सिफारिशों के साथ साथ एम० ए० और एम० एससी० परीक्षाओं के परिणामों में तीसरी श्रेणी को समाप्त करने की भी सिफारिश की थी क्योंकि मास्टर के स्तर पर तीसरी श्रेणी नियमों के विपरीत मालूम पड़ती है। आयोग ने समिति के विचारों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिये परिचालित कर दिया था। मार्च, 1964 में हुई अपनी बैठक में आयोग ने इस विषय पर विचार किया था और विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए यह राय ज़ाहिर की कि इस विषय में आगे कार्यवाही करना अलग-अलग विश्व-विद्यालयों का कार्य है।

जम्मू और काश्मीर द्वारा ऋण का भुगतान

\* 563. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर सरकार ने लगभग 60 करोड़ रुपये के केन्द्रीय ऋण को लौटाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) ऋण को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). 1963-64 के वित्तीय वर्ष के अन्त में स्वीकृत ऋणों की अदायगी के लिये मूलधन के रूप में जम्मू और काश्मीर राज्य पर 17, 46, 12,000 रुपये की राशि देय थी। क्योंकि राज्य सरकार यह राशि नक़द लौटाने असमर्थ थी, इस राशि का एक नया ऋण 4 दिसम्बर, 1964 को राज्य सरकार को दिया गया।

कलकत्ता के गोदी श्रमिकों पर पाकिस्तानी प्रभाव

64. { डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :  
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता में गोदी श्रमिकों पर पाकिस्तानी प्रभाव बढ़ रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि हाल में पाकिस्तानी समर्थन तथा धन से गोदी श्रमिकों की एक यूनियन बनी है और यह गुप्त कार्यों में लगी हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने कलकत्ता में गोदी श्रमिकों के संघों के संगठन तथा इतिहास के विषय में अब तक कोई जांच पड़ताल की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) इस सम्बन्ध में ऐसी कोई जांच नहीं की गई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### मोटी सतह वाली सड़कें

\*565. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या शिक्षा मंत्री 16 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 535 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटी सतह वाली सड़कों के निर्माण के बारे में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या इन सिफारिशों के अनुसार कोई कार्य किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो परम्परागत तरीके और केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था द्वारा सिफारिश किये गये तरीके में क्या अन्तर है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था द्वारा की गई सिफारिशों तकनीकों सलाह सम्बन्धी हैं । सड़कों के निर्माण के लिये उत्तरदायी एजेंसियां इन सिफारिशों से परिचित हैं ।

(ख) जांच करने के बाद संस्था द्वारा की गई सिफारिशों, नीचे दिये गये मामलों के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा, लागू कर दी गई है :—

- (1) दुर्गापुर स्टील टाऊनशिप रोड,
- (2) जम्मू-बनिहाल रोड,
- (3) दिल्ली मथुरा रोड, और
- (4) श्रीनगर टनल रोड ।

(ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

### राष्ट्रीय एकता परिषद्

\*566. श्री प्र० च० बहगुना :  
श्री गोकुला नन्द महन्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक शीघ्र ही होने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कार्यसूची में क्या विषय ; और

(ग) इसकी बैठक कब और कहां होगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग). अभी यह प्रश्न ही नहीं उठता।

### Hindustani Cultural Society

1420. { Shri K. C. Panth :  
Shri Siddeshwar Prasad :

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the grants given to Hindustani Cultural Society for the construction of a building and the year in which given;

(b) whether it is also a fact that the building was constructed at Kanpur while the grant was sanctioned for Allahabad;

(c) the details of the work done so far; and

(d) the action, if any, taken against the Society for giving wrong information about the land?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis) : (a)

	Amount	Year
(i)	25,000	1951-52
(ii)	25,000	1956-57
(iii)	25,000	1961-62

(b) No, Sir. The grant was given for construction of the building at Kanpur

(c) Main Hall with adjacent rooms are completed. Wood work for doors, windows, etc. are also completed.

(d) Does not arise, as the Government were aware of the construction at Kanpur.

### जिला गजटियर

1421. श्री हेम राज : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितन-कितन राज्य सरकारों ने अपने राज्य गजेटियर पूरे तथा प्रकाशित करा लिये हैं ;  
और

(ख) राज्य गजेटियरों को तैयार करने में राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेखों का कहां तक उपयोग किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुसायूं कबिर) : (क) राज्य गजेटियरों के संशोधन से सम्बन्धित स्कीम को अभी हाथ में नहीं लिया गया है। सारे जिला गजेटियरों के प्रकाशन होने के बाद राज्य गजेटियरों के प्रकाशन से सम्बन्धित कार्य को शुरू किया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना

1422. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 तथा 1964-65 में विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के व्यय पर कितने विद्यार्थी विदेशों में भेजे गये ;

और

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थी हैं ;  
और

(ग) इन में उड़ीसा राज्य के कितने विद्यार्थी हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरतबीस) : (क) बाईस/तथापि, इन सबको उनके चयन के समय ही नियोजित कर लिया गया था और वे किसी शिक्षा संस्था के विद्यार्थी नहीं थे ।

(ख) और (ग). कोई भी नहीं ।

## विस्थापित व्यक्तियों की नागरिकता

1423. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी विस्थापित व्यक्तियों ने अपने को भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीबद्ध करा लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन विस्थापित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिन्हें अभी पंजीबद्ध किया जाना है ; और

(ग) उनके रजिस्ट्रेशन में क्या कठिनाइयां हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). नागरिकता नियम 1956 के अधीन भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकरण की शर्तें इस प्रकार हैं :—

(i) सम्बन्धित व्यक्ति मूलतः भारतीय है और प्रार्थना पत्र देने से पहले लगातार 6 मास से भारत में रह रहा है ;

(ii) उसके निकट के सम्बन्धी भारत में हैं ।

(iii) भारत में स्थायी रूप से बसना चाहता है ;

(iv) प्रार्थनापत्र में दी हुई शपथ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ;

(v) चालचलन का अच्छा आदमी है और सब तरह से भारत के नागरिक के रूप में पंजीबद्ध किये जाने योग्य है ।

दिसम्बर, 1964 के अन्त तक 4,76,140 व्यक्ति भारत के नागरिकों के रूप में पंजीबद्ध किये जा चुके हैं । ऐसे व्यक्तियों की संख्या का पता लगाना सम्भव नहीं है जिन्हें अभी पंजीबद्ध किया जाना है ।

## मद्रास उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले

1424. { श्री म० पं० स्वामी :  
श्री परमशिवन :  
श्री अरुणाचलम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 को मद्रास उच्च न्यायालय में इसके मूल तथा अपीलीय विभाग में कितने मामले विचाराधीन थे ; और

(ख) ये मामले निबटाने में देर होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) मूल विभाग में—3597 ।

अपीलीय विभाग में —19329 ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

## बिय्यूर जेल, केरल

1425. श्री अ० क० गोपालन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि सेन्ट्रल जेल, बिय्यूर, केरल, में उचित जल प्रदाय व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार को यह भी विदित है कि नजरबन्दों के लिये समुचित स्नानगृह भी नहीं हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). कुछ कठिनाई हुई थी, परन्तु अब त्रिचुर वाटर सप्लाय एक अस्थाई कनेक्शन ले लिया गया है ।

(ग) विशेष उप जेल में कोई स्नानगृह नहीं हैं, परन्तु नजरबन्दों को स्नान के लिये अस्थाई छोटे कमरे मुहैया किये गये हैं ।

## बिय्यूर सब-जेल, केरल

1426. श्री अ० क० गोपालन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्पेशल सब-जेल, बिय्यूर, केरल, में जहां नजरबन्दों को रखा गया है आवास्थान सम्बन्धी कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) एक कोठरी में कितने नजरबन्दों को रखा जाता है ; और

(ग) कोठरी के फर्श का कितना क्षेत्रफल है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) चार ।

(ग) कमरे का क्षेत्रफल 229 वर्गफुट है ।

### राष्ट्रमण्डलीय युवक समारोह

1427. श्री राम हरख यादव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या प्रथम राष्ट्रीयमण्डलीय युवक समारोह भारत में आयोजित करने का सरकार का विचार है ;
- (ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और
- (ग) इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). भारत में राष्ट्रमंडलीय युवक समारोह आयोजित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होना अभी बाकी है ।

### लाहौर में अफ्रीकी-एशियाई गोष्ठी

1428. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1965 में लाहौर में एक अफ्रीकी-एशियायी गोष्ठी हुई थी ;
- (ख) यदि हां, तो बैठक में क्या क्या निर्णय किये गये ;
- (ग) क्या पाकिस्तान से कोई सांस्कृतिक शिष्टमण्डल भारत आ रहा है ; और
- (घ) यदि हां, तो इसके कब तक आने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनबीस) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि की रिपोर्ट के अनुसार, अगले दो वर्षों में एक अन्य सेमिनार आयोजित करने के लिये एक समिति गठित की गई थी और आयोजकों ने अफ्रीकी-एशियाई एकता अभियान में, जिसका केन्द्रीय कार्यालय काहिरा में है, शामिल होने का प्रस्ताव किया था ।

(ग) और (घ). कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

### संश्लिष्ट औषधि कारखाना, हैदराबाद

1429. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि हैदराबाद के संश्लिष्ट औषधि कारखाने में, जिसे सोवियट संघ से सहायता प्राप्त हुई है उत्पादन-कार्य मूल समय सूची से कम से कम एक साल पीछे है ;
- (ख) यदि हां, तो देरी के क्या मुख्य कारण हैं ; और
- (ग) देरी को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

**देहरादून में चुम्बकीय वैधशाला**

1430 श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वे आफ इण्डिया की चुम्बकीय वैधशाला, जो कई वर्ष पहले करनपुर ऐस्टेट से देहरादून ले जाई गई थी, अभी तक काम नहीं कर रही है तथा वहां तक कोई सड़क भी नहीं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं। चुम्बकीय वैधशाला, देहरादून के नजदीक 'सभावाला' में काम कर रही है (जहां यह करनपुर ऐस्टेट से ले जाई गई थी) यह दो तरफ से सड़क द्वारा मिली हुई है ( चकराता रोड से तथा दूसरी 'तिमली' की ओर से) ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**Firing on U. N. Observers;**

1431. { **Shri Hukam Chand Kachhavaia :**  
**Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the East Pakistan Rifles opened fire on the United Nations Observers in Karimpur; and

(b) if so the details of the action taken by Government ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):**

(a) and (b): There are no United Nations Observers on the Indo-East Pakistan border. Hence the question does not arise.

**दिल्ली शिक्षा संहिता**

1432. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा किसी संहिता के अन्तर्गत नहीं आती है ;

(ख) क्या दिल्ली के लिये शिक्षा संहिता बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : दिल्ली के लिये शिक्षा संहिता प्रकाशित कर दी गई है और इसे दिल्ली के सभी स्कूलों में 15-2-1965 से लागू कर दिया गया है। इस संहिता में अन्य बातों के साथ साथ ये विषय शामिल हैं :—

विभागीय संगठन पर अध्याय, स्कूलों का निरीक्षण, मान्यता के नियम, सहायक अनुदान के नियम, सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की सेवा शर्तें, जिनमें दण्ड देने और अपील करने के नियम भी शामिल हैं, छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने के नियम, दाखिले के सम्बन्ध में स्कूलों द्वारा अपनाए जाने वाले नियम, तबादले, अगली कक्षा के लिये तरक्की, चिकित्सा परीक्षा, आदि ।

### बम्बई में उर्वरक कारखाना

1433. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के उर्वरक कारखाने को इस तरह बनाया गया है कि बम्बई में काफी मात्रा में पानी न मिलने के कारण वह निर्धारित क्षमता तक पूरा पूरा उत्पादन न कर सके ;

(ख) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही गीकी गई है ; और

(ग) वार्षिक उत्पादन तथा हानि कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

### विक्रम विश्वविद्यालय

1434. श्री रा० गि० दुबे :  
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से सम्बद्ध विभिन्न इमारतों के निर्माण की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इमारतों की अनुमानित लागत क्या होगी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कितनी राशि देगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय की विभिन्न भवन प्रायोजना की अनुमति लागत 57,78,537 रुपये है जिसमें से आयोग का हिस्सा 34,39,966 रुपये होगा ।

### पुलिस तथा जनता के पारस्परिक सम्बन्ध

1435. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय ने पुलिस तथा जनता के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में सभी राज्य पुलिस आयोगों के प्रतिवेदनों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विभिन्न पुलिस आयोगों की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं तथा केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को पुलिस तथा जनता के पारस्परिक सम्बन्धों में और सुधार करने के बारे में क्या सलाह दी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) विभिन्न राज्य पुलिस आयोगों की रिपोर्टों का अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) पुलिस तथा जनता के बीच सम्बन्धों पर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा स्थापित किये गये पुलिस आयोगों तथा केरल पुलिस पुनर्गठन समिति

की मुख्य मुख्य सिफारिशों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4044/65।]

इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को कोई सलाह नहीं दी है।

### टोकियो ओलम्पिक खेल

1436. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खेल कूद संस्था के दो सदस्यों के एक प्रेक्षक दल ने, जो हाल में हुए ओलम्पिक खेलों के दौरान टोकियो गया था, भारत सरकार का ध्यान ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के सामने आई कुछ कठिनाई की ओर दिलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो हमारे खिलाड़ियों को क्या क्या मुख्य कठिनाइयां हुईं तथा उक्त प्रेक्षक दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार उनके लिये कौन उत्तरदायी है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) अक्टूबर, 1964 में टोकियो में हुए 18 वें ओलम्पिक खेलों को देखने के लिये बोर्ड ने राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान, पटियाला के बोर्ड आफ गवर्नर्स के अध्यक्ष तथा संस्थान के निदेशक को प्रतिनियुक्त किया था। उनकी रिपोर्टों की प्रतियां इस मंत्रालय में प्राप्त हुई थीं; लेकिन चूंकि बोर्ड आफ गवर्नर्स ने इन पर विचार नहीं किया था इस लिये संस्थान को सलाह दी गई है कि इन रिपोर्टों को पहले बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय। बोर्ड की सम्मति सहित मंत्रालय में रिपोर्टें प्राप्त होने पर उन पर यथापूर्वक विचार किया जायेगा।

### कालकाजी में विस्थापितों के लिए भूमि का विकास

1437. { श्री स० च० सामन्त :  
श्री म० ला० द्विवेदी :  
श्री सुबोध हंसदा :

क्या पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित लोगों के लिये प्रस्तावित कालकाजी कालोनी का पूरी तरह विकास हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति एकड़ विकास लागत क्या होगी ;

(ग) क्या विस्थापित लोगों से आवेदन-पत्र मांगे गए हैं ; और

(घ) प्रत्येक परिवार को अधिकतम कितनी भूमि दी जायेगी ?

पुनर्वासि मंत्री (श्री त्यागी) : (क) बस्ती में विकास का कार्य पूरे जोर से चल रहा है और आशा है शीघ्र ही पूरा हो जायेगा।

(ख) लागत का पता विकास कार्य के पूरा होने तथा कार्य के लेखों को चुकाने पर ही लगेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) 200, 300 और 400 वर्ग गज के प्लॉटों के विकास के लिये प्रस्तावित किये गये हैं।

### जस्टिस मित्र का मामला

2438. श्री यशपाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री जस्टिस मित्र के मामले के सम्बन्ध में 9 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1202 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको जन्मतिथि के मामले पर अब नक निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) मामला अभी तक विचाराधीन है ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 217(3) के अधीन श्री मित्र की जन्मतिथि का फैसला करने से पहले सारे मामले पर ध्यान से जांच करना जरूरी है ।

### केरल में स्कूलों के अध्यापक

1439. श्री यशपाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री 9 दिसम्बर, 1964 के अतारंकित प्रश्न सख्या 1201 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सहायता प्राप्त तथा सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को दिये जाने वाले मकान, किराया-भत्ते के मामले में असमानता समाप्त की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

### दिल्ली में मकान अलाट करना

1440. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :  
श्री प्र० चं० बरुआ :  
श्रीमती सावित्री निगम :  
श्री रा० गि० दुबे :  
श्री रामेश्वर टांटिया :  
श्री हेडा :  
श्री रा० बरुआ :  
श्री यशपाल सिंह :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्दी बस्तियों सम्बन्धी विभाग के कुछ पदाधिकारियों ने अनधिकृत व्यक्तियों को दिल्ली की तिहाड़ कालोनी में 162 मकान एलाट किये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय ने 14 वर्ष पूर्व इस कोलोनी में शरणार्थी परिवारों को 500 प्लॉट दिये थे किन्तु प्लॉटों में बनाये गये मकान गिर गये हैं और इन मकानों के मालिक तिलक नगर में जाकर बस गए हैं ;

(ग) क्या बाद में वहां के मूल निवासियों के लिये मकान फिर बनाये गये थे किन्तु ये मकान उन लोगों को दिए गए हैं जो तिहाड़ में कभी भी किसी प्लॉट के मालिक नहीं थे ; और

(घ) क्या सरकार ने मकानों की अनधिकृत एलाटमेंट के बारे में कोई जांच की थी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): (क) जी नहीं।

(ख) तिहाड़ गांव में 452 मकान जो मुसलमानों द्वारा छोड़े गए थे, वे पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों को एलाट कर दिए गए थे। कुछ घर वर्षा के कारण गिर गए थे। विस्थापित व्यक्तियों को आश्रय देने के लिये, 263 मकान प्रभावित व्यक्तियों को अस्थायी रूप से एलाट कर दिए गये थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन

1441. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :  
श्री क० ना० तिवारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अन्य राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे अपने अपने राज्य में रहने वाले राष्ट्रीय सघर्ष में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सहायता तथा पेंशन दें ; और

(ख) राजनीतिक कार्यकर्ताओं को केन्द्र से किस प्रकार की सहायता मिलती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देने की योजनाएं राज्य सरकारों ने स्वतः ही अपनाई हैं।

(ख) कठिनाई के अलग-अलग मामलों में गृह मंत्री के विवेकानुदान से राजनीतिक पीड़ितों को एक मुश्तलघु नकद अनुदान दिये जाते हैं। राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें देने के लिये एक योजना भी है, जिसका व्यय शिक्षा मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के बीच बांट लिया जाता है।

### आसाम-भूटान सीमा

1442. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :  
श्री प्र० चं० बरुआ :  
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम-भूटान सीमा पर एक मील लम्बी "रवामिहीन" भूमि में जासूसों तथा तस्कर व्यापारियों के अड्डे बने हुए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सीमा के पार असैनिक यातायात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं ; और

(ग) क्या पूर्वी तिब्बत में घने जंगलों में स्थित बताये जाने वाले प्राइवेट रेडियो स्टेशनों के माध्यम से गुप्त समाचार देने के लिये एक गुप्त जाल बिछा हुआ है जिसे चीन से आर्थिक सहायता मिलती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ग) सरकार के पास इस बात के कोई सबूत नहीं हैं।

### Lalit Kala Akademi

1443. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the names of the officials and members of the Board of Lalit Kala Akademi;

(b) the names of the Honorary Editor of Akademi's publications and the date and the mode of his appointment of this post;

(c) the name of the firm which has been given the sole agency of Akademi's publications and the terms of the agency; and

(d) whether it is a fact that the same firm has again been appointed as an agent for another two years although it did not fulfil the terms previously ?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla):**

(a) *Officers of the Akademi*

Shri Mehdi Nawaz Jung	. . . . .	Chairman
Prof. N. S. Bendre	. . . . .	Vice-Chairman
Shri K. N. Channa	. . . . .	Financial Adviser
Shri B. C. Sanyal	. . . . .	Secretary

*Members of the Executive Board'*

7. Shri Mehdi Nawaz Jung
2. Prof. N. S. Bendre
3. Shri K. N. Channa
4. Shri A. K. Ghosh
5. Shri P. N. Tagore
6. Shri T. N. Ramachandran
7. Shri K. C. S. Paniker
8. Shri P. Das Gupta
9. Shri S. G. Thakur Singh
10. Shri Y. K. Shukla
11. Shri Gopal Deuskar
12. Shri Karl J. Khandalavala
13. Shri Vimal Kumar
14. Dr. Mulk Raj Anand
15. Shri M. V. Minajgi

(b) Title of publication	Name of Hony. Editor	Date of appointment
Ancient Series	Sh. Karl J. Khandalavala	8-9-1958*
Lalit Kala Journal		
(Ancient Art)	Dr. Moti Chandra	8-9-1958*

\*Prior to 8-9-1958. Shri Karl J. Khandalavala functioning as the General Editor of all the publications of the Akademi since 11-5-1955;

These are not paid posts in the Akademi's office. Appointments were made by the Executive Board.

(c) M/s Four Oceans (P) Ltd., Bombay. A copy of the initial agreement for the sole agency is laid on the Table. [Placed in library See Nos L. T. 4045/65]

(d) Yes. Sir. This was done after duly considering the performance of the firm and quotations received from other leading firms in the country.

**Sahitya Akademi and Fine Arts Academy**

**1444. Shri Sidheshwar Prasad:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the sale of the publications brought out by Sahitya Akademi and Fine Arts Academy has so far been very poor;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) the further steps proposed to be taken to enhance the sale of their publications?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla):** (a) and (b) : Considering that the publications brought out by Sahitya & Lalit Kala Akademies are of a serious nature and they do not find ready market in the present state of literacy and art consciousness in the country the sale of these publications has on the whole been satisfactory.

(c) The two Akademies have appointed Special Committees to advise them on various measures to be taken to push up the sale of their publications. Further steps will be taken in the light of suggestions made by these Committees.

#### National Book Trust

**1445. Shri Sidheshwar Prasad:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the amount given to the National Book Trust upto January, 1965 and for what type of work;

(- ) the names of the books published by the Trust during this period and names of other books to be published by the end of 1965)

(c) whether it is a fact that the expenditure on publication of books is borne by the Ministry of Information and Broadcasting; and

(d) whether in view of the present position the Trust has considered the question of maintaining its separate accounts in respect of publication and sale of books?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla):** (a) Rs. 15,35,300.00 for their normal activities and office expenses.

(b) A statement giving the requisite information is laid on the Table. [Placed in library See No. LT. 4046/65]

(c) Yes Sir; in respect of those titles which are published by the Ministry of Information and Broadcasting.

(d) This is being done already in respect of books published direct by the Trust.

#### National Book Trust

**1446. { Shri Sidheshwar Prasad:  
          { Shri K. C. Pant:**

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Tarachand Committee appointed in 1961 to evaluate the work of the National Book Trust pointed out several irregularities of the Trust and referred to the stagnation in its activities; and

(b) if so, the action taken so far to remedy the situation?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla):** (a) and (b) : The Committee did not point out any irregularities as such; but made certain suggestions regarding the scope of activities and structure of the Trust. The Trust was re-organised in 1962 on the basis of these suggestions

#### अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प संस्था, नई दिल्ली

**1447. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस लक्ष्य की ओर दिलाया गया है कि सरकार ने अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प संस्था, नई दिल्ली को सरकार से लिये गये ऋण का भुगतान करने के लिये कुछ धन का अनुदान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण तथा अनुदान की क्रमशः राशि कितनी है, और

(ग) किन कारणों से ऐसी असाधारण कार्यवाही आवश्यक समझी गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री भु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) ऋण 5,50,000.00 रुपये। सहायता अनुदान 1,65,000.00 रुपये ।

(ग) ऋण संस्था भवन निर्माण के लिये दिया गया था । उसके बाद, सांस्कृतिक संस्थाओं को भवन-अनुदान देने की एक योजना शुरू की गई और संस्था के काम को देखते हुए तथा भवन अनुदान के लिये उसकी पात्रता और ऋण अदा कर सकने की उसकी कठिन वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए, भवन-आयोजना के लिये भारत सरकार ने आंशिक रूप से 1,65,000/- रुपये का अनुदान दिया था । यह अनुदान नकदी में नहीं दिया गया, बल्कि कर्ज की बकाया रकम के हिसाब में लगा दिया गया था ।

### शल्य चिकित्सा औजार कारखाना, मद्रास

1448. महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से मद्रास के शल्य चिकित्सा औजार कारखाने के लिये आवश्यक शल्य चिकित्सा औजारों का निर्माण करने के लिये अपेक्षित विशेष प्रकार का इस्पात प्राप्त करने के हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लि०, जो मद्रास में शल्य चिकित्सा औजार संयंत्र को रॉन्वित कर रहा है, परियोजना का के लिये अपेक्षित इस्पात की विशेष श्रेणियों की आरम्भिक आवश्यकताओं के आयात के लिये सोवियत ट्रेड आर्गनाईजेशन, मैसर्ज प्राइमस्यरायन इम्पोर्ट (M/s Premsyrion-import) के साथ ठेका किया है और जो कि अभी रुपया-लेखा (rupee account) पर देशीय रूप में उपलब्ध नहीं है ।

### Scheduled Castes Employees

1449. Shri Naval Prabhakar : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the number of Class I and Class II employees in his Ministry who belong to Scheduled Castes and their percentage as against the total number of employees in the Ministry ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): A statement containing the requisite information is placed on the table of the House.

### STATEMENT

Total number of Class I and Class II employees in the Ministry as on 1-1-1965.	Number of employees belonging to Scheduled Castes.	Percentage of Scheduled caste employees as against the total number.
Class I . . . . . 85	2	2.35
Class II . . . . . 453	9	1.98
Total . . . . . 538	11	2.04

उत्तर में दूसरा तेल शोधक कारखाना

1450. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर में हल्दिया के पास एक दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और कब ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Jet Boats From Newzealand

\*1451. { Shri Onkar Lal Berwa:  
Shri Hukam Chand Kachhavaia:  
Shri Bhagwat Jha Azad :  
Shri Yashpal Singh.

Will the Minister of **Home** **Affair** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain Jet-boats are being given to India by Newzealand;

(b) if so, on what terms;

(c) names of places and work for which they are going to be used; and

(d) when they are likely to arrive ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra):**

(a) Yes.

(b) As a gift, under the Colombo Plan.

(c) In Punjab, for flood relief work.

(d) They were expected to arrive some time this month.

निष्क्रान्त सम्पत्ति

1452. { श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :  
श्री सोलंकी :  
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950 से 1964 तक की अवधि में कुल कितने अनुमानित मूल्य की निष्क्रान्त सम्पत्ति अर्जित की गई ;

(ख) इन सम्पत्तियों से अब तक कितना किराया वसूल किया गया है ; और

(ग) शहरों में अर्जित की गई कितने मूल्य की सम्पत्तियां विक्रय अथवा आवंटन द्वारा हस्तांतरित की गई ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) अर्जित की गई निष्क्रान्त सम्पत्तियां दो प्रकार की हैं :—

- (1) शहरी निष्क्रान्त सम्पत्तियां
- (2) कृषि भूमि तथा ग्रामीण सम्पत्तियां ।

1955 के बाद निष्क्रान्त सम्पत्तियां विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 की धारा 12 के अंतर्गत अर्जित की गई थीं । शहरी निष्क्रान्त सम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य 88 करोड़ रुपये है । इसके अतिरिक्त 60 लाख ए. ए. डी. भूमि निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में प्राप्त की गई थी, जो प्रायः पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले भूमि दावेदारों को बांट दी गई थी । ग्रामीण मकान अनुबन्ध के रूप में माने गये थे और अधिकतर कृषि भूमि के साथ ही दे दिये गये थे ।

(ख) अर्जित करने के उपरान्त इन सम्पत्तियों के बारे में लग-भग 7 करोड़ रुपये किराया प्राप्त हुआ है ।

शहरों में अर्जित की गई बिक्रय तथा आवंटन द्वारा हस्तांतरित की गई निष्क्रान्त सम्पत्तियों का मूल्य लगभग 93 करोड़ रुपये है जिसमें 7 करोड़ रुपये जो अभी किस्तों के आधार पर दी गई सम्पत्तियों से किस्तों के रूप में वसूल करने शेष हैं, भी सम्मिलित हैं ।

#### निष्क्रान्त सम्पत्ति का बकाया किराया

1453. { श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :  
श्री सोलंकी :  
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 1964 के अन्त में निष्क्रान्त सम्पत्ति का कुल कितना किराया बकाया था; और
- (ख) इसको वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) प्रादेशिक बन्दोबस्त आयुक्तों परिक्षकों के कार्यालयों में रखे गये रिजिस्ट्रों के अनुसार 31-10-64 तक 411.45 लाख रुपये बकाया थे ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4047 / 65 ।]

#### सरकारी कर्मचारियों के लिए सहकारी स्टोर

1454. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री 9 दिसम्बर 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1170 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये इस बीच कितने सहकारी स्टोर खोले गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिये मद्रास में एक उपभोक्ता सहकारी समिति बनाई गई है और उसने सात शाखा

स्टोर खोले हैं। बम्बई और कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिये उपभोक्ता सहकारी समितियां संगठित करने की कार्यवाही चल रही है।

### Police Firing at Hakimpur Railway Station.

1455. { **Shri Mohan Swarup:**  
**Shri P. R. Chakraverti:**  
**Shri P. C. Borooah:**  
**Shri Yashpal Singh:**  
**Shri Ram Harkh Yadav:**  
**Shri Vishwa Natth Pandey**  
**Shri Krishnapal Singh:**

Will the Minister of **Home affairs** be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the police fired on students at Hakimpur Railway Station near Moradabad on the Northern Railway on the 12th January; 1965;
- (b) if so, the details of the incident; and
- (c) the number of casualties as a result of the firing; and
- (d) whether any inquiry has been ordered to investigate into this incident?

**The Minister of State in The Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):** (a) Yes, Sir.

(b) On January 12, 1965, two students who were travelling by the 56 Down Train had to be taken into custody for failure to pay the fine levied on them by the magisterial checking staff at the Hakimpur railway station for ticketless travel. Other students who were travelling by the same train stopped it at the outer signal by pulling the alarm chain and began demanding the release of these two students. A mob soon collected on the spot and began indulging in violence. Owing to the imminent danger to life and damage to railway property, the Railway Magistrate declared the assembly unlawful and ordered it to disperse. Not only did this prove futile but the mob, in fact, became more threatening. Firing had, therefore, to be ordered as a last resort by the Magistrate after due warning.

(c) Three persons were injured.

(d) Yes, Sir. A Magisterial enquiry has been ordered.

### गोआ में जब्त की गयी पुर्तगाली आस्तियां

1456. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ को स्वतन्त्र कराने के बात सरकार ने गोआ में कितने मूल्य की पुर्तगाली राष्ट्रजनों और पुर्तगाली सरकार की आस्तियां जब्त की हैं ;

(ख) मोज़ाम्बिक और अन्य पुर्तगाली उपनिवेशों से लौटाये गये भारतीयों द्वारा पीछे छोड़ी गई आस्तियों का मूल्य क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार गोआ में भूतपूर्व पुर्तगाली राष्ट्रजनों तथा गोआ सरकार की जब्त की गई आस्तियों में से स्वदेश लौटाये गये इन भारतीयों को उनकी आस्तियों की हानि के लिये क्षतिपूर्ति देने का है ?

गृह-कार्य त्रालय मंत्र राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ख) मोजाम्बिक से लौटाये गये भारतीयों द्वारा अब तक दायर किये गये दावों के अनुसार सम्बन्धित आस्तियों का मूल्य लगभग 5.30 करोड़ रुपये है जिस में से लगभग 1.60 करोड़ रुपये की अचल आस्तियां हैं तथा लगभग 3.69 करोड़ रुपये के चल आस्तियां।

(ग) हाल में सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

भूमि अर्जन विभाग, दिल्ली

1457. { श्री रामेश्वर टांटिया :  
श्री हुकम चन्द कछवाय :  
श्री ओंकार लाल बेरवा :  
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :  
श्रीमती मैमूना सुल्तान :  
श्री रा० बरुआ :  
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री ह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के भूमि अर्जन विभाग के साथ हाल में लगभग 1,30,000 रुपये का धोखा हो गया है ;

(ख) क्या कोई जांच करने का आदेश दिया गया ?

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) इसके लिये उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां। सही राशि 1,28,115 रुपये है।

(ख) से (घ) तक : 18 जनवरी 1965 को पता चला कि दिल्ली के लैंड ऐं वीजिशन कलक्टर के दफ्तर में एक बैंक बुक के बैंकों के 12 खाली फार्म गायब हैं। स्टेट बैंक आफ इंडिया को एकदम सूचना दी गई और उन 12 बैंकों का भुगतान रोकने के लिये कहा गया। बैंक ने सूचित किया कि उनमें से तीन बैंक धोखा दे कर भुना लिये गये। इन बैंकों की कुल राशि 1,28,115 रुपये थी। मामले की रिपोर्ट पुलिस को तुरन्त की गई और भारतीय दंड संहिता की 380/409/420/468/471/120-ख धाराओं के अधीन थाना सब्जी मंडी, दिल्ली में रिपोर्ट संख्या 52 दिनांक 18 जनवरी 1965 के अधीन एक मामला दर्ज किया जा चुका है। इस मामले की जांच काफी आगे बढ़ चुकी है। अब तक दस व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

सरकारी विभागों में कल्याण अधिकारी

1458. श्रीमती सावित्री निगम : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में कितने कल्याण अधिकारी हैं ;

(ख) 1964-65 में अब तक प्रत्येक अधिकारी को कितनी शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) उनके द्वारा कितनी शिकायतों पर विचार किया गया, कितनों पर कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया तथा किस आधार पर इन पर कार्यवाही नहीं की गई?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 47.

(ख) और (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

### मुरैना में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

1459 { श्री उइके :  
श्री राम सहाय पाण्डेय :  
श्री विद्याचरण शुक्ल :  
श्री राधे लाल व्यास :  
डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की समिति ने 11 दिसम्बर, 1964 को हुई अपनी बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक के वहां कौंटवार (मुरैना) के स्थानों में खुदाई करने के सुझाव पर विचार किया है, जहां ईस्वी सन् के आरम्भ से समय के मिट्टी के बर्तनों का भारी संग्रह बताया जाता है,

(ख) क्या समिति ने उस स्थान की खुदाई करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां। कालाकुत (जिला-मुरैना) के स्थान के सम्बन्ध में एक सुझाव था और 'पुरातत्व केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड' की स्थायी समिति ने अपनी 3 सितम्बर, 1964 को हुई बैठक में इस पर विचार किया था।

(ख) और (ग) समिति ने कुछ अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए इच्छा व्यक्त की थी और राज्य सरकार से सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

### इन्द्रावती तथा साबरी के बेसिनों में लोगों को बसाना

1460 { श्री उइके :  
श्री राम सहाय पाण्डेय :  
श्री विद्याचरण शुक्ल :  
श्री राधे लाल व्यास :  
डा० चन्द्रभान सिंह :  
श्री हुकम चन्द कछवाय :  
श्री प० ह० भील :  
श्री वाडीवा :  
श्री बाबू नाथ सिंह :  
श्री रा० स० तिवारी :

क्या पुनर्वासि मंत्री 2 दिसम्बर, 1964 के अतारंकित प्रश्न संख्या 831 के उत्तर के

सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रावती तथा सावरी बेसिनों सम्बन्धी योजनाओं का मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञों के दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में और क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) से (ग). इन्द्रावती तथा सावरी के बेसिनों के सम्बन्ध में सिंचाई तथा जल-विद्युत संभाव्य के मूल्यांकन के बारे में टीम ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है और मसौदे की रिपोर्ट तैयार कर ली है। कुछ अंशों के बारे में टीम के सदस्यों में चर्चा हानी अभी शेष है। यह आशा की जाती है कि रिपोर्ट को मार्च, 1965 तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा। टीम की सिफारिशों पर ही आगे कार्यवाही की जायेगी।

#### मध्य प्रदेश में बहुप्रयोजनीय स्कूल

1461. { श्री उडके :  
श्री राम सहाय पाण्डेय :  
श्री विद्याचरण शुक्ल :  
श्री राधे लाल व्यास :  
डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहु-प्रयोजनीय स्कूल योजना के आरम्भ किये जाने के बाद मध्य प्रदेश में कितने बहु-प्रयोजनीय स्कूल खोले गये हैं ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये मध्य प्रदेश सरकार को तीसरी योजना में अब तक कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में 38 बहुदेशीय स्कूल हैं।

(ख) और (ग) बहुदेशीय स्कूलों को सुदृढ़ बनाने की केन्द्र संचालित योजना के अधीन, राजकीय (बायज) उच्च माध्यमिक स्कूल टी० टी० नगर, भोपाल को एक प्रायोगिक आदर्श बहुदेशीय स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए, मई 1964 में 50,000 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था।

## मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां

1462. { श्री उडके :  
श्री राम सहाय पाण्डेय :  
श्री विद्याचरण शुक्ल :  
श्री राधे लाल व्यास  
डा० चन्द्र भान सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियों के लिये कोई अनुदान दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह अनुदान किस आधार पर दिया जाता है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हाजरनवीस) : (क) जी हां ।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए	.	.	.	1,64,600 रुपये
अनुसूचित कबीलों के लिए	.	.	.	81,000 रुपये
अन्य पिछड़े वर्गों के लिए	.	.	.	6,02,000 रुपये

(ग) यह अनुदान, योजना के विकेन्द्रीकरण से पहले वर्ष अर्थात् 1958-59 के दौरान हुए खर्च के आधार पर मंजूर किया गया है ।

## राज्यों में राज भाषा के रूप में प्रादेशिक भाषा

1463. { श्री कोल्ला वैकैया :  
श्री म० ना० स्वामी :  
श्री राम सेवक यादव :  
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन राज्यों ने प्रादेशिक भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में ज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : आंध्र प्रदेश, केरल तथा नागालैण्ड के विधान मण्डलों ने अभी तक राज्य के अन्तर्गत व्यवहार होने वाली भाषा या भाषाओं को राज्य के समस्त अथवा किसी विशेष प्रयोजन में व्यवहार के लिये राज्य भाषा या राज्य भाषाओं के रूप में विधिवत अंगीकार नहीं किया है ।

## विज्ञान शिक्षा

1464. { श्रीमती सावित्री निगम :  
श्री ईश्वर रेड्डी :  
श्री बड़े :

श्री श्रीकार साल बेरवा :  
श्री कोया :  
श्री विभूति मिश्र :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यूनेस्को दल ने यह सिफारिश की है कि विज्ञान-शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिये पहली अवस्था में ज्ञान का अध्यापन अधिक प्रभावकारी और उपयोगी होगा; और  
(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां। 'यूनेस्को प्लैनिंग मिशन' ने पहली श्रेणी से ही विज्ञान व गणित के अध्यापन की सिफारिश की थी।

(ख) स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के कार्यक्रमों को विकसित करने के विचार से इस सिफारिश की जांच की जा रही है।

#### प्रादेशिक भाषाओं की पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद

1465 श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 1960-61 से 1964-65 तक सरकार द्वारा सभी प्रादेशिक भाषाओं की कितनी पुरानी और नई उच्च कृतियों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए अनुदान दिये गये हैं ; और  
(ख) उक्त अवधि में प्रति वर्ष किन किन संस्थाओं को (प्रत्येक भाषा के लिए पृथक पृथक) ये अनुदान दिए गए हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). ऐसे ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद के प्रकाशनार्थ 1960-61 से 1964-65 की अवधि में वित्तीय सहायता के लिए किसी संस्था से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई।

#### नई दिल्ली नगर पालिका की बकाया राशि की वसूली

1466. श्रीमती मैमूना सुल्तान :  
श्री रामेश्वर टांटिया :  
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :  
श्री यशपाल सिंह :  
श्री महेश्वर नायक :

क्या गृह-कार्य मंत्री 23 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1780 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) इस समय नई दिल्ली नगर पालिका ने विभिन्न सरकारी विभागों से कितनी राशि लेनी है ; और  
(ख) इन बकाया राशियों की शीघ्र वसूली करने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सरकार से नीचे लिखे मदों के बारे में कुछ राशियों का दावा किया है और उन्हें सरकार को नीचे लिखी राशि देनी है :—

1. नई दिल्ली नगर पालिका के सरकार के विरुद्ध दावे

1. मकान-कर सेवाओं का शुल्क . . . . .	4,45,02,327 रुपये 74 पैसे
2. सरकारी बस्तियों में बजरी के रास्तों पर झाड़ू लगाना और उद्योगों की सफाई . . . . .	46,84,717 रुपये 53 पैसे
3. सरकारी रिहायशी मकानों के बाहिर टट्टियों के 225 सेटों का रख-रखाव . . . . .	1,68,912 रुपये 41 पैसे
4. नगर पालिका की ओर से कुछ असैनिक निर्माण कार्यों के लिए सरकार के पास जमा की हुई राशियों की वापसी . . . . .	27,36,106 रुपये 74 पैसे
5. थोक में पानी देने के शुल्क का भुगतान . . . . .	45,334 रुपये 68 पैसे

---

5,21,37,399 रुपये 10 पैसे

---

2. सरकार के नई दिल्ली नगर पालिका के विरुद्ध दावे

1. लाभकारी सेवाओं के कारण खर्च की प्रतिपूर्ति . . . . .	1,00,00,000 रुपये 00 पैसे
2. डिप्लोमेटिक एन्क्लेव क्षेत्र को छोड़ कर बाकी के बागवानी के काम . . . . .	18,00,000 रुपये 00 पैसे
3. डिप्लोमेटिक एन्क्लेव क्षेत्र में बागवानी के काम . . . . .	10,75,000 रुपये 00 पैसे
4. बिजली के कामों के बारे में जमा राशियां . . . . .	अभी निश्चित होनी हैं ।

---

1,28,75,000 रुपये 00 पैसे

---

इन दावों और इनके जवाबी की राशियां सही हैं या नहीं, इस बात की जांच हो रही है । समय समय पर निर्माण तथा आवास मंत्रालय नगरपालिका के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करता रहता है और इसके परिणाम स्वरूप कुछ मामले तय हो गये हैं और कुछ भुगतान हो गए हैं । बाकी मामलों के बारे में बातचीत चल रही है । दावों का अंतिम फैसला होने तक, अभी लगभग 177.13 लाख रुपये की राशि सरकार द्वारा नगरपालिका को दे दी गई है ।

## राष्ट्रीय संयंत्रों का संरक्षण

1467. { श्री रामचन्द्र उलाका :  
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या गृह-कार्य मंत्री 2 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय संयंत्रों की रक्षा और रखवाली के लिये एक केन्द्रीय सुरक्षा दल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है और अपनी स्वीकृति केन्द्रीय सरकार को भेज दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). यद्यपि कई राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल बनाने के प्रस्ताव से सहमत हो गए हैं, कुछ ने इस बारे में कई कठिनाइयां बताई हैं ।

(ग) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

## ईराक और कुवैत में तेल सम्बन्धी रियायत

1468. { श्री रामचन्द्र उलाका :  
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईराक और कुवैत में तेल सम्बन्धी रियायत प्राप्त करने के प्रयत्नों में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ; और

(ख) वह किस प्रकार की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) अभी कुछ प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## ग्रामीण संस्थायें

1469. { श्री रामचन्द्र उलाका :  
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री 2 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 804 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दो ग्रामीण संस्थायें स्थापित करने तथा वर्तमान कृषि विज्ञान पाठ्यक्रमों का दर्जा बढ़ाने के प्रस्तावों पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) ग्राम संस्थानों के पुनर्गठन होने तक इन प्रस्तावों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

**विश्वविद्यालयों को मान्यता देना**

1470. श्री विभूति मिश्र : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिये सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं । विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित किए जाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**मद्रास के लिये तीन भाषाओं वाला सूत्र**

1471. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में लागू किये जाने वाले तीन भाषाओं वाले सूत्र में कौन कौन सी भाषायें शामिल की गई हैं ;

(ख) क्या हिन्दी को ऐच्छिक विषय बना दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क)

(i) प्रथम भाषा

प्रादेशिक भाषा (तमिल) अथवा विद्यार्थी की मातृ भाषा (तेलुगु, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, हिन्दी, मराठी)

(ii) द्वितीय भाषा

हिन्दी अथवा अन्य कोई भारतीय भाषा जो उपर्युक्त (अ) के अन्तर्गत अध्ययन न की गई हो ।

(iii) तृतीय भाषा

अंग्रेजी अथवा अन्य कोई विदेशी भाषा ।

(ख) और (ग) जी हां । राज्य सरकार के विचार से, हिन्दी को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाना पर्याप्त होगा ।

**भारतीय सैनिक अकादमी के पास चीनी कारतूसों का पाया जाना**

श्री यशपाल सिंह :  
श्री रामेश्वर टांटिया :  
श्री प्र० चं० बरुआ :

1472. { श्रीमती सावित्री निगम :  
 श्री रामचन्द्र उलाका :  
 श्री बाल्मीकी :  
 श्री महेश्वर नायक :  
 श्री स० मी० बनर्जी :  
 श्री इन्द्रजीत गुप्त :  
 श्री बाजी :  
 श्री अंकार लाल बेरवा :  
 श्री विद्याचरण शुक्ल :  
 श्री हुकम चन्द कछवाय :  
 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह कार्य मंत्री 30 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1570 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सैनिक अकादमी के पास हाल ही में पाये गये कारतूसों के सम्बन्ध में, जो चीन में बने बताये जाते हैं, कोई जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : अभी जांच जारी है और आशा है कि जल्दी ही पूरी हो जायेगी ।

### त्रिपुरा के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता

1473. श्री स० मो० बनर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों को जो प्रतिकर भत्ता दिया जाता था अब बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने प्रार्थना की है कि यह भत्ता जारी रखा जाना चाहिए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला विशेष प्रतिकर भत्ता, न कि प्रतिकर भत्ता, पहली अप्रैल 1961 से बन्द कर दिया गया है ।

(ख) विशेष प्रतिकर भत्ता कम वेतन वाले कर्मचारियों को उनके और त्रिपुरा में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन के बीच के अन्तर को कम करने और साथ ही उस क्षेत्र की महंगाई का ध्यान रखते हुये दिया जाता था । वेतनक्रमों में संशोधन के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 1961 से त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों के वेतनक्रम साधारणतया बढ़ गये हैं । इसलिये विशेष प्रतिकर भत्ते को जारी रखना ठीक नहीं समझा गया ।

(ग) त्रिपुरा के विकास मंत्री ने इस तरह के भत्ते को जारी रखने का अनुरोध किया था ।

### भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन

1474. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :  
श्री दाजी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सघन भ्रष्टाचार-विरोधी आन्दोलन के लिए केन्द्रीय सरकार के कुछ विभागों को विशेष रूप से चुना गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन विभागों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस आन्दोलन के अनुसरण में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं तथा उनसे क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री हाथी): (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4048/65 ]

### Fertilizer Factory near Kotah

1475. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a fertilizer factory is being set up in private sector near Kotah;

(b) if so, when it will be set up and the amount to be spent thereon; and

(c) the capacity of this plant?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan)**: (a) Yes.

(b) According to the time schedule furnished by the party, the plant is expected to go into production in October, 1967. The cost of the project is estimated at Rs. 22.70 crores.

(c) 100,000 tonnes in terms of Nitrogen or 217,800 tonnes of urea, per annum.

### तेल की खोज के लिये फ्रांसीसी सहयोग

1476. { श्री विभूति मिश्र :  
श्री क० ना० तिवारी :  
श्री प्र० चं० बरुआ :  
श्री रामेश्वर टांटिया :  
श्री रवीन्द्र वर्मा :  
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में तेल की खोज के लिए फ्रांसीसी सहयोग प्राप्त करने के लिए

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा फ्रांसीसी तेल फर्मों के बीच बातचीत चल रही है ;  
और

(ख) यदि हां, तो इस सहयोग की क्या संभावनाएं हैं और प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) जैसलमेर में समरूप सहयोग के विस्तार के तौर पर तेल की खोज में इंस्टीट्यूट फ्रांसिस ड्रू पेट्रोल, पैरिस (Institut Francais du Petrole, Paris) की तकनीकी सहायता का प्रवर्धन करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा उक्त इंस्टीट्यूट के बीच में कुछ बातचीत हुई है ।

(ख) सहयोग के व्यौरे के बारे में अभी निर्णय होना है ।

### उत्तर प्रदेश में पौलीटैकनिक संस्थाएँ

**1477. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 तक उत्तर प्रदेश में कितनी पौलीटैकनिक संस्थाएँ खोली गयी थीं ;

(ख) क्या तीसरी योजना की शेष अवधि में इस राज्य में नई पौलीटैकनिक संस्थाएँ खोलने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) उत्तर प्रदेश में पौलीटैकनिक संस्थाओं में अब तक कितने विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है ; और

(घ) 1964-65 में इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितनी राशि देने का विचार है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) 32, यह संख्या उन पांच के अतिरिक्त है जिनकी राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है किन्तु जो अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 1964-65 में 4690 ।

(घ) पालिटैकनिकों की स्थापना और विकास समेत तकनीकी शिक्षा की राज्य आयोजना की सभी योजनाओं के लिए 43.62 लाख रुपए ।

### मंत्रियों की विदेश यात्रा

**1478. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) .1 नवम्बर, 1962 से 27 फरवरी, 1965 तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार के कैबिनेट मंत्रियों, राज्य-मंत्रियों तथा उपमंत्रियों ने किन किन देशों का दौरा किया ;

(ख) प्रत्येक यात्रा पर विदेशी मद्रा सहित कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या मंत्रियों के विदेशों के दौरों के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के समा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### उर्वरक कारखाना, गोरखपुर

1479. { श्री विश्वनाथ पाण्डेय :  
डा० महादेव प्रसाद :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के उर्वरक कारखाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उर्वरक का उत्पादन किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगोसन) : (क) गोरखपुर, उर्वरक कारखाने द्वारा अब तक की गई प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है :—

भूमि अर्जन : यह कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

सिविल कार्य : दिसम्बर, 1964 में निविदा प्राप्त हुए थे। शीघ्र ही इन टैंडरों के आधार पर आर्डर दिए जायेंगे। इस कार्य के अप्रैल, 1965 से शुरु होने की आशा है।

मशीन और संयंत्र की प्राप्ति : मुख्य संयंत्रों की सप्लाई के लिए जापानी प्रदायकों को आर्डर दिये गये हैं। जापान की बन्दरगाह से लगभग 4173 मीटरी टन के उपकरण और मशीनें भेजी गई हैं जिनमें से लगभग 1128 मीटरी टन के उपकरण एवं मशीन स्थल पर पहुंच गये हैं।

उपनगर : टाइप-3 के 200 क्वार्टरों और टाइप-6 के क्वार्टरों के निर्माण की समस्त प्रगति क्रमशः 85 प्रतिशत और 75 प्रतिशत है। टाइप-2 क्वार्टरों के 45 ब्लॉकों का निर्माण कार्य शुरु हो गया है। टाइप-4 क्वार्टरों के लिए कार्य आदेश दिए गये हैं। प्रशासन कार्यालय और प्रशिक्षणार्थियों के होस्टल का कार्य भी प्रगति पर है।

रेलवे साइडिंग : रेलवे अधिकारियों से प्रार्थना की गई है कि वे आन्तरिक रेलवे साइडिंग के दो रेलपथ के कार्य को हाथ में लें।

(ख) जी हां।

(ग) 1967 के शुरु में।

### Corruption Cases

1480. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases out of the cases of corruption referred to Go-

verment by Sanjivita Sadachar Samiti so far on which action has been taken;

(b) the number of persons found guilty of corruption in those cases; and

(c) the number of persons who are being prosecuted?

**The Minister for Home Affairs (Shri Nanda) :** (a) to (c). Action was initiated on all the allegations of corruption in respect of Central Ministries. 52 cases were not proved. Departmental action has been taken or is being taken in respect of 12 cases. 3 other cases were considered *prima facie* such as to deserve further investigation. The remaining 86 cases are under various stages of inquiry. No case has yet reached the stage of prosecution or the stage of a person being found guilty of corruption.

### Training of Engineering College Teachers

**1481. Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement has been reached between Government of India and U.N.O. Special Fund according to which a teachers training centre will be established in the Regional Engineering College of Andhra Pradesh; and

(b) if so, when that will be established as also the amount of money that will be spent on the same?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :** (a) Yes, Sir.

(b) The centre will be established this year at a cost of Rs. 84.44 lakhs.

### अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

1482 { श्री दीनेन भट्टाचार्य :  
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(4) के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को अपने मूल विभाग अथवा पदालि में पदोन्नति के लिये, यदि वे सभी न्यूनतम अर्हतायें पूरी करते हों, तो संघ लोक सेवा आयोग के सामने इन्टरव्यू के लिये जाने की जरूरत नहीं होती ।

(ख) क्या यह भी सच है कि मूल विभाग अथवा पदालि में अधिक ऊंचे पदों और सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के उचित दावों को मानते हुए उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के पारमर्श के क्षेत्र से बाहर रखा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन जातियों के हितों की रक्षा किस प्रकार की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) यह सत्य नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 320(4) के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की अपने मूल विभाग अथवा पदालि में ऊंचे पदों पर भरती अथवा पदोन्नति संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती । जहां कहीं भी सामान्य नियमों

के अधीन, आवश्यकता होती है वहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के व्यक्तिगत मामलों पर आयोग का परामर्श लेना पड़ता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

1483. { श्री दीनेन भट्टाचार्य :  
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन किये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के राजपत्रित अधिकारियों की उनके मूल विभाग या पदाली में वरिष्ठता निर्धारित करने तथा स्थायीकरण के लिए क्या कोई विशेष उपबन्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो नियमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). जब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के राजपत्रित अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया गया हो, उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये कोई विशेष नियम नहीं हैं। वरिष्ठता का साधारण नियम जो सीधी भरती किए हुए व्यक्तियों को, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार शामिल हैं, लागू होता है, यह है कि जिस योग्यता-क्रम में उनका संघ लोक सेवा आयोग या दूसरे चयन प्राधिकारी द्वारा चयन किया जाता है, उसी के अनुसार उनकी वरिष्ठता निर्धारित होती है, जो व्यक्ति किसी पहले चयन के परिणाम पर नियुक्त होते हैं वे किसी बाद के चयन के परिणाम पर नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होते हैं परन्तु यदि शुरु में अस्थायी आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों का स्थायीकरण बाद में जिस योग्यता-क्रम में उनकी नियुक्ति हुई थी उसमें न होकर किसी भिन्न क्रम में हो तो उनकी वरिष्ठता उनकी स्थायीकरण के क्रम के अनुसार होगी, न कि शुरु के योग्यता-क्रम के अनुसार। इसलिये जब विशेष प्रतिनिधित्व तालिका, जिसका ब्यौरा संसद् पुस्तकालय में रखी गयी टिप्पणी में दिया है [देखिये संख्या एल० टी० 4049/65] के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित खाली जगहें शुरु में अस्थायी आधार पर नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाती हैं, वे ऐसी आरक्षित खाली जगहों में अपनी बारी पर स्थायीकरण के लिए पात्र होते हैं। स्थायी होने पर वे उन सब से जो किसी बाद की तिथि से स्थायी होवें वरिष्ठ हो जाते हैं, चाहे वे दूसरे व्यक्ति उनसे पहिले नियुक्त हुए हों।

### माहे में भूमि सुधार

1484. { श्री पोट्टेकाट्ट :  
श्री अ० व० राघवन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माहे में योजना आयोग द्वारा सुझाये गये भूमि सुधारों को लागू करने में क्या प्रगति हुई है ;

- (ख) भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने में देरी के क्या कारण हैं ; और  
(ग) प्रस्तावित विधान के कब तक लाये जाने की समभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) माहे में आजकल माहे बेदखली की कार्यवाही की रोक (संशोधन) अधिनियम, 1964 द्वारा संशोधित माहे (बेदखली की कार्यवाही की रोक) विनियम, 1963 लागू है। यह अधिनियम माहे में काश्तकारों को अपनी जमीन से बेदखल होने से बचाता है और उसमें बेदखल हुए काश्तकारों को फिर से जमीन का कब्जा दिलाने और काश्तकारों द्वारा समर्पण की हुई या छोड़ी हुई जमीन का प्रबन्ध पांडीचेरी के प्रशासक द्वारा किये जाने की व्यवस्थाएं हैं।

(ख) और (ग). पांडिचेरी में भूमि सुधार के बारे में उपयुक्त विधान लागू करने के प्रश्न पर पांडिचेरी की सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

### दिल्ली में एक राजदूतावास से केबल की चोरी

1485. { श्री हुकम चन्द कछवाय :  
श्री अंकार लाल बेरवा :  
श्री यू० द० सिंह :  
श्री बड़े :  
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक पूर्व यूरोपीय देश के राजदूतावास से 32,000 रुपये के मूल्य के केबल हाल में चोरी हुए पाये गये ;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों को पकड़ने तथा मामले की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या हाल में दिल्ली में अन्य कहीं पर भी इसी प्रकार की केबल की चोरी की घटनाएं हुई हैं, यदि हां, तो कहां कहां ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

### उड़ीसा में संस्कृत संस्थायें

1486. { श्री राम चन्द्र उलाका :  
श्री धुलेश्वर मीना :  
श्री राम चन्द्र मलिक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में उड़ीसा में स्वच्छिक संस्थाओं को संस्कृत के विकास के लिये कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

- (ख) इस अवधि में जिन संस्थाओं को अनुदान दिये गये उनके नाम क्या हैं ; और  
 (ग) 1965-66 में इस प्रयोजन के लिये राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं को कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 3,000 रुपये ।

(ख) सम्पादक, मनोरमा, बेरहमपुर (गंजम) ।

(ग) राज्य-वार कोई राशि नियत नहीं की गई है । इस मंत्रालय की संस्कृत के प्रसार के लिए स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं और सम्बन्धित संगठनों/संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के गुणावगुणों के आधार पर विभिन्न राज्यों में संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं ।

### कम मूल्य वाली अमरीकी पुस्तकें

1487. { श्री राम चन्द्र उलाका :  
 श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964-65 में कम मूल्य वाली अमरीकी पाठ्य पुस्तकों (पी० एल० 480 निधि की सहायता से) तथा ब्रिटेन की महान् कृतियों और निदेश पुस्तकों के प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी और किस प्रकार की पुस्तक प्रकाशित की गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): कम मूल्य वाली शिक्षा सम्बन्धी अमरीकी मानक पुस्तकों और शिक्षा सम्बन्धी ब्रिटिश मानक पुस्तकों के पुनः प्रकाशन की योजनाओं के अन्तर्गत 1964-65 के दौरान प्रकाशित अथवा 31-3-65 तक प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की संख्या क्रमशः 109 और 15 है । ये विशेष कर विश्वविद्यालय/कालेज और पालिटेकनिक विद्यार्थियों के लिए हैं । विषयानुसार विवरण इस प्रकार है :—

अमरीकी पुस्तकें : 109

कृषि	.	.	.	4
जीव-विज्ञान	.	.	.	3
वनस्पति-विज्ञान	.	.	.	2
रसायन	.	.	.	3
वाणिज्य	.	.	.	2
अर्थ-शास्त्र	.	.	.	6
शिक्षा	.	.	.	7
शिक्षा-मनोविज्ञान	.	.	.	3

इंजीनियरी तथा टेकनोलौजी	34
भूविज्ञान	4
साहित्य	
गणित	12
चिकित्सा-विज्ञान	4
दर्शन-शास्त्र	4
भौतिकी	5
मनोविज्ञान	6
राजनीतिक-विज्ञान	5
समाज-विज्ञान	2
पशुचिकित्सा-विज्ञान	1
प्राणि-विज्ञान	1

## ब्रिटिश पुस्तकें : 15

वाणिज्य	1
अर्थ-शास्त्र	2
इंजीनियरी तथा टेकनोलौजी	3
विधि	2
गणित	1
चिकित्सा विज्ञान	2
समाज-विज्ञान	1
पशुचिकित्सा-विज्ञान	3

## विद्रोही नागा

1488. { श्रीमती रेणुका बड़कटकी :  
 श्री प्र० चं० बरुआ :  
 श्री हुकम चन्द कछवाय :  
 श्री अंकार लाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागा मनीपुर तथा नागालैण्ड क्षेत्र में उखरूल, तमंगलोंग और माम्रो उपखण्ड में ग्रामीण नागाओं से धन एकत्रित कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियों के स्थान के लिये हुए समझौते के उल्लंघन के सम्बन्ध में नागालैंड में हुई बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता ने गुप्त प्रतिनिधियों को बड़े गरम शब्दों में बोला है। ये बातें शांति दल के ध्यान में भी लाई गई हैं, जिसने इस सम्बन्ध में गम्भीरता प्रकट की है। नागालैंड में राज्य सरकार ने भी ग्रामीणों को यह अनुदेश दिये हैं, कि गुप्त दल को कोई धन न दें।

### त्रिपुरा में शरणार्थी

1489. { श्री दशरथ देव :  
श्री मधु लिमये :  
श्री किशन पटनायक :  
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से वहां पर 1964 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बाद कितने शरणार्थी त्रिपुरा आये हैं ; और

(ख) उन्हें त्रिपुरा तथा अन्य स्थानों में बसाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पुनर्वासि मंत्री (श्री त्यागी) : (क) 1 जनवरी, 1964 से 16 मार्च, 1965 तक 26,035 परिवार जिनमें 1,09,568 व्यक्ति हैं, पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा में आये हैं।

(ख) 4871 परिवारों को भूमि पर बसाया जा चुका है।

200 परिवार जिनके सदस्यों ने राष्ट्रीय विकास दल में नाम दर्ज करवाने के लिये आवेदन पत्र भेजे हैं उन्हें भी बसाया जायेगा और 13 अन्य परिवारों को त्रिपुरा में स्थायी रोजगार पर लगा दिया गया है।

3189 परिवार दूसरे राज्यों में बसाने के लिये भेजे जा चुके हैं।

आवाजाही केन्द्रों में जो शेष 483 परिवार हैं 308 परिवार जिनमें कोई योग्य समर्थ शरीर वाले पुरुष सदस्य नहीं हैं तथा 200 परिवार जिनके सदस्यों ने राष्ट्रीय विकास दल में नाम दर्ज करवाने के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं इनको छोड़ कर उनको भी दूसरे राज्यों में बसाने के लिये भेजा जायेगा।

### शरणार्थियों को सहायता

1490. { श्रीमती रेणुका बड़कटकी :  
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ल्ड काउंसिल फार चर्चेज (विश्व गिरजाघर परिषद्) ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को सहायता देने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए दस लाख डालर देने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सहायता की शर्तें क्या हैं तथा इस सहायता से किन-किन कार्यक्रमों को लाभ होगा ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले नये विस्थापितों को सहायता तथा पुनर्वास के सम्बन्ध में वर्ल्ड काउंसिल आफ चर्चेंज (विश्व गिरजाघर परिषद्) ने आर्थिक तथा तकनीकी सहायता देने की इच्छा प्रकट की है। किसी विशेष राशि के सम्बन्ध में अभी तक सहायता की पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) वर्ल्ड काउंसिल आफ चर्चेंज (विश्व गिरजाघर परिषद्) से जो सहायता प्राप्त होगी वह संभवतः अनुदान के रूप में ही होगी। सहायता यदि स्वीकार कर ली गई तो उसे तकनीकी दस्तकारी की विभिन्न योजनाओं तथा चुने हुए प्रशिक्षण तथा उत्पादन खंड लगाने के लिये उपयोग में लाया जायेगा।

### डाक-तार खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

**1491. श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार खेल-कूद नियंत्रण बोर्ड ने अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् से प्रार्थना की है कि बोर्ड को मान्यता दी जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह प्रार्थना वर्ष 1959 में की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उसे मान्यता देने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बोर्ड ने मंत्रालय से भी बातचीत की थी कि सभी राष्ट्रीय फेडरेशनों से उन्हें सम्बद्ध करने के लिये कहा जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो मंत्रालय की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) जी, हां। इसको मान्यता दे दी गई है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, अक्टूबर, 1960 में एक प्रार्थना प्राप्त हुई।

(ग) अखिल भारत खेलकूद परिषद् ने बोर्ड को परामर्श दिया है कि दो या तीन वर्ष बाद फिर मान्यता के लिए आवेदन करें।

(घ) जी, हां।

(ङ) सभी राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशनों से प्रार्थना की जा चुकी है कि वे इस मामले पर अनुकूल ढंग से विचार करें।

### लन्दन रायल इन्स्टीट्यूट के डिप्लोमे

**1492. श्री जेधे :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लन्दन के (एक) रसायन शास्त्र, (दो) जीव विज्ञान, (तीन) इंजीनियरों, (चार) सर्जनों तथा (पांच) फीजिशियनों के रायल इन्स्टीट्यूटों द्वारा दिये जाने वाले (एक) लाइसेंसियेट, (दो) एसोशियेट तथा (तीन) फ़ैलो के डिप्लोमाओं को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में सरकारी उपक्रमों में नियुक्ति के लिये मान्यता दी जाती है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** रसायन शास्त्री के रायल संस्थान, लन्दन की एसोशिएटशिप, फिजिशियन्स के रायल कालेज, लन्दन की लाइसेंसिएटशिप, मेम्बरशिप और

फैलोशिप तथा सर्जन्स के रायल कालेज, इंग्लैंड की मेम्बरशिप तथा फलोशिप को नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है ।

शेष उपाधियों को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार करने का कोई अवसर उपस्थित नहीं हुआ ।

### पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

1493. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में अनधिकृत प्रवेश के कारण 1964 में कितने पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

### Hindustan Organic Chemical Factory

1494. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) when the construction of Hindustan Organic Chemical Factory at village Posari near Panvel in Maharashtra is likely to be completed ;

(b) whether full compensation has been paid to those farmers whose land was acquired for the factory;

(c) whether any priority for employment in this industry has been given to those landless farmers; and

(d) if so, details thereof?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan)** : (a) Hindustan Organic Chemicals Factory at village Posari near Panvel in Maharashtra is expected to be completed by 1968.

(b) Land has been acquired by the Maharashtra State Government who have given it for the project free of cost. No compensation is therefore required to be paid by the Central Government.

(c) and (d). Government have enunciated the general principles on the recruitment policy of the Public Sector Undertakings, which contain *inter alia* grant of employment to persons displaced by the acquisition of land for the project. A copy of these instructions was laid on the Table of the Lok Sabha by the Minister of Industry on 14-4-61 in reply to Starred Question No. 1520. According to these instructions, Hindustan Organic Chemicals Ltd. would make every effort to give preference to persons displaced from areas acquired for the project.

### हिन्दी विरोधी आन्दोलन

1495. { श्री दलजीत सिंह :  
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :  
श्री सुबोध हंसदा :  
श्री स० च० सामन्त :  
श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी :

क्या गृह-कार्य मंत्री 24 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 119 के उत्तर के

सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण में हिन्दी के विरुद्ध आन्दोलन करने वालों ने जान तथा माल की कितनी हानि की ;

(ख) क्या इस आन्दोलन की विस्तृत रूप से जांच करने तथा इससे लाभ उठाने वाले व्यक्तियों का, दंड देने के हेतु, पता लगाने के लिये कोई आयोग नियुक्त करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने से हुई हानि के बारे में ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 70 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

#### सरकारी सेवाएं

1496. { श्री दिगे :  
श्री द्वारकादास मंत्री :  
श्री तु० अ० पाटिल :  
श्री बसवन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की विभिन्न सेवाओं में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इनमें प्रत्येक राज्य के कितने-कितने कर्मचारी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

#### केरल में नजरबन्द व्यक्ति

1497. श्री अ० क० गोपालन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 दिसम्बर, 1964 के बाद केरल में कितने व्यक्ति नजरबन्द किये गये ;

(ख) क्या केरल में नजरबन्द व्यक्तियों को परिवार भत्ता देने के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या सरकार ने ज्ञापन पर कोई कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सरकार अंग्रेजी शासन काल में या उसके बाद राज्य के नजरबन्द व्यक्तियों को परिवार भत्ता देती रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके अब न देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 145 : इनमें से 4 को अपने मूल निवास के राज्य में भेज दिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

(घ) ब्रिटिश शासन काल में भूतपूर्व देशी रियासत त्रावनकोर कोचीन में परिवार भत्ता दिये जाने के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । केरल सरकार द्वारा (राज्य के निर्माण के पश्चात्) किसी भी मामले में परिवार भत्ता नहीं दिया गया ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### सिंदरी उर्वरक कारखाने में अमोनिया संयंत्र

1498. श्री तन सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1963-64 में सिंदरी उर्वरक कारखाने के अमोनिया संयंत्र में डबल साल्ट का उत्पादन निर्धारित उत्पादन क्षमता का केवल 4 प्रतिशत हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ? .

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं । 1963-64 में डबल साल्ट का वास्तविक उत्पादन 47211 मीटरी टन था, जो कि निर्धारित लगभग 45.4 प्रतिशत है ।

(ख) उत्पादन में निर्धारित क्षमता से कमी होने के कारण इस प्रकार हैं :—

(i) लीन गैस संयंत्र की अपर्याप्त क्षमता के कारण नये अमोनिया संयंत्र में अमोनिया का न्यूनतर उत्पादन ;

(ii) 5000 मीटरी टन अमोनिया का विक्रय, जो कि डबल साल्ट के उत्पादन में 13,000 मीटरी टन की कमी का कारण हुआ ; और

(iii) 1963-64 के दौरान में अनिश्चित श्रमिक स्थिति ।

(ग) योजना अवधि के दौरान में उर्वरकों के देशीय उत्पादन के कार्यक्रम में डबल साल्ट का उत्पादन शामिल नहीं है । इस उर्वरक का आयात भी नहीं है । सिन्दरी के उत्पादन से जो भी सप्लाई प्राप्त होती है सरकार उसका प्रतिबन्धित आधार पर नियतन करती है ।

### व्हिटलें परिषद्

1499. श्री स० मो० बनर्जी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्हिटले परिषद् सम्बन्धी विशेषज्ञ, ब्रिटेन के बी लेसले विलियम्स, सरकार को संयुक्त परामर्श व्यवस्था को समुचित रूप से चलाने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये भारत आये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सुझाव दिये ; और

(ग) सरकार को वह कहां तक स्वीकार्य हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) अपनी भारत यात्रा के दौरान विलियम्स ने भारतीय लोक प्रशासन संस्था में एक व्याख्यान माला दी थी और इस देश में सरकारी कर्मचारियों के लिये एक संयुक्त परामर्श व्यवस्था में दिलचस्पी रखने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के लोगों से भी सम्पर्क स्थापित किया।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उठते ही नहीं क्योंकि उनकी यात्रा सरकार को परामर्श देने के लिये नहीं थी।

### अंकलेश्वर-कोयली पाइप लाइन

**1500. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंकलेश्वर से कोयली तक तेल पाइप लाइन बिछाने का काम भड़ौच में नर्भदा पुल पर रुक गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पाइप लाइन बिछाने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुंमायून कबिर) :** (क) अंकलेश्वर कच्चे तेल की पाइप लाइन के कार्य के मदों में से नर्भदा रेल पुल पारक एक मद है जो कि अभी पूरा होना है ।

(ख) रेल पुल पारक का रूपांकन पश्चिमी रेलवे के परामर्श से तैयार किया जाना था और इस सम्बन्ध में सन्तोष-जनक हल ढूँढने के लिए उनके साथ कई बैठकें हुईं। हाल में ही अभिकल्पों से आलेखन प्राप्त हुए हैं। और सामग्री की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जून, 1965 के अन्त तक इस पाइप लाइन के तैयार हो जाने की सम्भावना है।

### जवाहर ज्योति ले जाने वाली जीप पर हमला

**1501. { श्री दी० चं० शर्मा :  
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 फरवरी, 1965 को कोट्टायम से 12 मील दूर चंगनचेरी में कुछ व्यक्तियों ने जवाहर ज्योति ले जाने वाली जीप पर हमला किया था ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां

(ख) 25 फरवरी, 1965 को लगभग 6 बजे शाम को, लगभग 500 व्यक्ति, जिनमें अधिकतर विद्यार्थी थे, चंगनचेरी में केरल कांग्रेस के चुनाव कार्यालय के सामने इकट्ठे हो गये और उन्होंने उस जीप को रोक लिया जिसमें श्री पी० सी० चेरियन, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, श्री पी० टी० थौमस (चांगनचेरी चुनाव-क्षेत्र से कांग्रेसी उम्मीदवार) तथा दूसरों द्वारा जवाहर ज्योति ले जाई जा रही थी। वह इकट्ठी हुई भीड़ उस ज्योति का उस स्थान पर स्वागत करना चाहती थी। यह सुझाव उस ज्योति को ले जाने वाले लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह उनकी सूची में नहीं था। भीड़ ने तब उस जीप को घेर लिया, श्री पी० टी० थौमस को गालियां दीं और जीप से चार कांग्रेस के झंडे उतार लिये। ड्यूटी पर जो पुलिस थी उसने हस्तक्षेप किया, झंडे वापिस लिये और रूकावट को हटा दिया। इस बीच में भीड़ में से किसी ने श्री पी० टी० थौमस पर एक चप्पल फेंकी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया और 11 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सम्बन्धित धाराओं के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया।

### Solar Energy Instruments at N.P.R.

**1502. Shri S. N. Chaturvedi :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether National Physical Laboratory has manufactured instruments for boiling water and for preparing molasses from palm and sugarcane juice by sun heat;

(b) if so, the prices of the said instruments; and

(c) the extent of saving in the consumption of fuel that would be effected by them?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :** (a) to (c). The details have been published in the Journal of Scientific and Industrial Research, 1959, Vol. 18A, No. 2 (Domestic Solar Water Heater) and No. 5 (Solar Energy Concentrators for concentrating Sugarcane Juice), copies of which are available in the Library of the Parliament.

मोतिया खान, दिल्ली में आग

1503. { श्री रामेश्वर टांटिया :  
श्री मधु लिमये :  
डा० राम मनोहर लोहिया :  
श्री राम सेवक यादव :  
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में मोतिया खान में 28 फरवरी, 1965 को आग लग गई और उससे भारी हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आग बुझाने वाले दल कई घण्टों तक आग पर काबू नहीं पा सके ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(घ) पीड़ित व्यक्तियों को क्या सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) 28 फरवरी, 1965 को जो आग मोतिया खान में लगी थी उसमें लकड़ी के 35 खोखे जल गये। इनमें से 15 रिहायशी थे और 20 गैर-रिहायशी। इस आग के फलस्वरूप लगभग 1.6 लाख रुपये की सम्पत्ति के नष्ट होने का अन्दाजा है।

(ख) जी नहीं। फायर ब्रिगेड के पहले दो दल 1 बज कर 8 मिनट पर अर्थात् सूचना मिलने के बाद दो मिनट में पहुंच गये और 1 बज कर 55 मिनट पर आग पर काबू पा लिया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वहां रहने वाले जिन परिवारों की झुग्गियां तथा अन्य सामान पूरी तरह नष्ट हो गया था उनमें से प्रत्येक परिवार को 25 रुपये की राशि मेजर की सहायता-निधि में से सहायता के रूप में दी गई।

#### केरल में पुलिस की ज्यादतियों के बारे में शिकायतें

1504. श्री अ० क० गोपालन: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छै महीनों में सरकार को केरल में पुलिस ज्यादतियों के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उनकी जांच कर ली है ;

(ग) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उनको क्या दण्ड दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

#### गुजरात तेल शोधक कारखाना

1505. { श्री राम सहाय पाण्डेय :  
श्री रा० वरुआ :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल विशेषज्ञों सहित 10 सदस्यों के सोवियत संघ के संसद सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने देश में पर्यटन करते हुए हाल में गुजरात तेल शोधक कारखाना देखा था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या प्रयोजन था और उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रतिनिधि मंडल की यात्रा की व्यवस्था विशेष रूप से गुजरात शोधनशाला की, जिसका निर्माण सोवियत की सहायता से हो रहा है, प्रगति दिखाने के लिए की गई थी ।

### मध्य प्रदेश में स्कूल विज्ञान प्रयोगशालाएं

1506. { श्री रा० स० तिवारी :  
श्री शिवदत्त उपाध्याय :  
श्री वाडिवा :  
श्री जे० पी० ज्योतिषी :  
डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करने के लिये राज्य योजना से बाहर वित्तीय सहायता के लिये मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उन प्रस्तावों पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). इस विषय में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु, माध्यमिक शिक्षा में सुधार की केन्द्र संचालित योजना के अन्तर्गत 1964-65 के दौरान माध्यमिक स्कूलों की विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सितम्बर, 1964 में मध्य प्रदेश सरकार को 12 लाख रुपये की रकम देने का प्रस्ताव किया गया था ।

### दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109

1507. श्री शं० ना० चतुर्वेदी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में संघ राज्य क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अधीन कितने अभियोग चलाये गये ; और

(ख) इन में से कितने मामले ऐसे थे जिनमें संबंधित व्यक्ति सम्पन्न थे और उन पर निर्वाह के प्रत्यक्ष साधन न होने के कारण अभियोग चलाया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपर्युक्त (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 2,027 ।

(ख) कोई नहीं ।

## केरल में नज़रबन्द व्यक्ति

1508. { श्री कोल्ला वेंकैया :  
श्री म० ना० स्वामी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के उन नज़रबन्द व्यक्तियों को, जो उस राज्य सभा की विधान सभा के लिये चने गये हैं, रिहा किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). भारत की वामपक्षी साम्यवादी पार्टी के सक्रिय सदस्यों को इसलिये नज़रबन्द किया गया था ताकि उन्हें भारत की सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, जन सुरक्षा तथा व्यवस्था के लिये खतरा उत्पन्न करने वाले कार्य करने से रोका जा सके। उन नज़रबन्दों में से कुछ के चुनाव में आ जाने मात्र से इन कारणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार उनकी रिहाई के बारे में तभी विचार कर सकती है जब उसे यह तसल्ली हो जाय कि वे अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरनाक नहीं रहे।

## दिल्ली के स्कूलों में लाइब्रेरियन

1509. श्री शिवचरण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लाइब्रेरियनों के भिन्न भिन्न वेतन-क्रम हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके वेतन-क्रमों में एकरूपता लाने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) विषय विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## दिल्ली में स्कूल शिक्षा

1510. श्री रामपुरे : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि दिल्ली में स्कूल शिक्षा की देखभाल करने के लिये एक संविहित बोर्ड बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) सरकार का इस समय, ऐसे किसी बोर्ड की स्थापना का विचार नहीं है।

## ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में प्रश्न

### RE : CALLING ATTENTION NOTICES—(QUERY)

**अध्यक्ष महोदय :** सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

**श्री हेम बरुआ (गोहाटी) :** क्या मैं आपकी राय जान सकता हूँ ।

**अध्यक्ष महोदय :** केरल में राष्ट्रपति का शासन जारी रखने के सम्बन्ध में कई ध्यान दिलाने वाली सूचनाएँ दी गई थीं । गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि उनको समय चाहिये और वह शुक्रवार को इसका उत्तर देंगे । परन्तु आज वह तैयार हैं और आज शाम साढ़े पांच बजे उनका उत्तर देंगे । श्री अलगेशन ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) :** मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप प्रधान मंत्री से यह प्रार्थना करें कि हिन्द महासागर में अमरीकी वायुयान वाहक के सम्बन्ध में प्रश्न के उत्तर से जो भ्रम उत्पन्न हुआ है उसको स्पष्ट करें । आपने कहा था कि आप इस सम्बन्ध में पूछ-ताछ कर रहे हैं अब मैं आप से प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रधान मंत्री से प्रार्थना करें कि वह इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें क्योंकि विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित हो चुका है ।

**श्री नाथ पाई (राजापुर) :** मैं जो विषय कल उठाना चाहता था वह बहुत महत्वपूर्ण था । यह भारतीय पुलिस अधिकारियों को सीमा के उस पार गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में है । यदि आप इसकी इजाजत न दें तो मैं इसे नहीं उठाना चाहता । परन्तु आप यह तो मानते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री हेम बरुआ ।

**श्री हेम बरुआ :** मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दिलाने वाली सूचना देना चाहता हूँ । गृह-कार्य मंत्री ने 12 मार्च को पेकिंग के साथ वामपंथी कम्युनिस्टों के सम्बन्धों के बारे में जो वक्तव्य दिया था उस पर चीनी दूतावास ने जो आपत्ति की है, यह उसके सम्बन्ध में है । उन्होंने गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया है । एक विदेशी दूतावास ने संसद की कार्यवाही पर आपत्ति की है ।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री मधु लिमये ।

**Shri Madhu Limaye (Monghyr) :** I had given a calling attention notice regarding the analysis of Kerala elections by Home Ministry, as reported in newspapers. I want to know whether the Home Ministry would be used for drawing conclusions in favour of one party or against another party?

**Shri Onkar Lal Berwa (Kota) :** I had also given a calling attention notice about Kairon's murder. I have not received any reply to that.

**Mr. Speaker :** I have got other notices with me. I am waiting for other members to speak.

**Shri Muthiah (Tirunelveli) :** I have also given a calling attention notice.

**Mr. Speaker :** I have received that. Shri Yashpal Singh.

**Shri Yashpal Singh :** When I am not receiving any reply, how can I ask questions?

**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) :** आपने सामान्य कार्यप्रणाली को क्यों बदल दिया है कि उन विषयों के सम्बन्ध में हम आपके कक्ष में आपसे चर्चा करें ?

**अध्यक्ष महोदय :** यही चीज में सभा के सामने रखना चाहता हूँ । जब मैं माननीय सदस्यों को यह कहता हूँ कि वह इस प्रकार इन विषयों को न उठाये तो वह जिद्द करते हैं ; और कुछ चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि मैं ना भी नहीं कर सकता । अब मैं सभा से पूछता हूँ कि इस प्रक्रिया को अपनाया जाये कि नहीं । मेरे पास रोज 25 से 30 सूचनाएँ आ रही हैं ।

**कुछ माननीय सदस्य :** जी नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं केवल विरोधी सदस्यों से पूछता हूँ । मेरे पास रोज 25 से 30 सूचनाएँ आती हैं। मुझे प्रत्येक के सम्बन्ध में यहां चर्चा करनी पड़ती है और उन का उत्तर देना पड़ता है। क्या यह सम्भव है ? मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ । क्या यह सम्भव है कि मैं प्रत्येक सदस्य की ध्यान दिलाने वाली सूचना के सम्बन्ध में यह बताऊँ कि उसके बारे में क्या किया गया है । अतः मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूँगा कि जिस कार्य प्रणाली का मैंने पहले उल्लेख किया था उसी का अनुसरण करें, अर्थात् जब भी उनको कोई शिकायत हो तो वह मुझे लिख सकते हैं ।

यह कहा गया है कि प्रधान मंत्री के कथन से काफी भ्रम उत्पन्न हो गया है । परन्तु जब प्रधान मंत्री ने स्पष्ट बता दिया है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने किसी पोत अथवा वायुयान वाहक के लिये नहीं कहा था तो मैं उनसे वक्तव्य देने के लिये कैसे कह सकता हूँ और विशेषकर जब उनके पास सूचना भेजी गई तो उन्होंने कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा था वह अन्तिम और ठीक है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह नहीं कि उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया । परन्तु जब दयाभाई पटेल ने कहा कि वह अमरीकी दूतावास से सभी पत्र प्रस्तुत करेंगे तो प्रधान मंत्री सकपका गये और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । उनको लोक सभा में इसे स्पष्ट करना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि दयाभाई पटेल ने यह कहा है तो क्या मैं प्रधान मंत्री से वक्तव्य देने के लिये कह सकता हूँ ? यदि वह चाहें तो स्पष्टीकरण दे सकते हैं ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उन्हें कहें कि वह स्पष्टीकरण करें ।

**अध्यक्ष महोदय :** किसी पर दबाव डालने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** मुझे समझ में नहीं आता कि इस विषय पर और प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, जब कि मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने किसी वायुयान वाहक को हमारे जल-प्रांगण में आने के लिये नहीं कहा था । यह कहा गया था कि यह कलकत्ता के करीब आया था । परन्तु यह बातें बिल्कुल निराधार हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

### सभा पटल पर रखे गए पत्र

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स और हिन्दुस्तान इन-सैक्टिसाइड्स के वार्षिक प्रतिवेदन, परीक्षित लेखे, -समीक्षाएं आदि ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, बम्बई की वर्ष 1963-64 की वार्षिक रिपोर्ट, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4040/65 ।]

(2) (एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एण्टीवायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, की वर्ष 1963-64 की वार्षिक रिपोर्ट, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4041/65]

(3) (एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली, की वर्ष 1963-64 की वार्षिक रिपोर्ट, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति ।

(दो) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4042/65]

## राज्य सभा से सन्देश

### MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सूचना देनी है :—

“राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 1965 जो राज्य सभा द्वारा 23 मार्च, 1965 की बैठक में पारित किया गया है, की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश मिला है ।”

## उद्योग विकास तथा विनियम) संशोधन विधेयक

### INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL

राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सचिव : श्री मान्, मैं राज्य द्वारा पारित उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 1965 की प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

## तारांकित प्रश्न संख्या २२६ के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 226

### सरकारी कार्यालयों में काम के घंटे

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि 3 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 226 के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्रपाल सिंह द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का जो उत्तर मैंने दिया था उसमें कुछ अशुद्धि थी, वह दूसरे वेतन आयोग की महीने में शनिवारों को छुट्टी देने की सिफारिश के सम्बन्ध में था। वास्तविक स्थिति यह है कि दूसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि एक शनिवार को छोड़कर दूसरे शनिवार को छुट्टी होनी चाहिये। परन्तु सरकार महीने में एक ही शनिवार को छुट्टी देने के लिये सहमत हुई है।

### गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

#### साठवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति का साठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

### सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—contd.

अध्यक्ष महोदय : वर्ष 1965-66 के सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। श्री रामकृष्णन अपना भाषण जारी रखें।

श्री पी० रा० रामकृष्णन् (कोयम्बटूर) : वित्त पूंजी बढ़ाने के लिये तीन उपाय किये गये हैं, परन्तु यह इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त नहीं है। मेरा सुझाव है कि लाभांश कर समाप्त कर दिया जाये, और यदि वह यह नहीं करना चाहते तो उनको कोई खंड प्रणाली अपनानी चाहिये। बोनस शेयरों पर पूंजी लाभ कर को समाप्त कर देने, अधिकार को समाप्त करने और कम्पनी करारोपण को कम कर देने का मैं सुझाव देना चाहता हूँ। लाभांश से आय को अर्जित आय समझा जाय।

उत्पादन में वृद्धि करने के लिये भी वित्त मंत्री ने तीन प्रकार के प्रोत्साहन दिये हैं।

यह उपाय चयनात्मक और विभेदात्मक है। इससे सरकार का अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ गया है। इन उपायों से, निस्संदेह, उत्पादन में वृद्धि होगी। निर्यात-प्रोत्साहन के लिये जो वित्त मंत्री ने कर में रियायत की है, उससे मुझे आशा है कि इससे निर्यात में वृद्धि होगी। हमारी अर्थ-व्यवस्था में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में जो शत्रुता का भाव है उससे कोई भी देश का नागरिक प्रसन्न नहीं होगा। उपभोज्य वस्तुओं के उद्योग में गैर-सरकारी व्यापारियों के उतरने पर जो आशंकाएँ प्रकट की जा रही हैं, उसमें शायद सभी उद्योगपति शामिल नहीं हैं।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि देश की अर्थ-व्यवस्था में तभी सुधार होगा जब कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी। हमें अपनी जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगानी चाहिये। मुद्रा का प्रसार उत्पादन से अधिक नहीं होना चाहिये।

**श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित (फूलपुर) :** जिस प्रकार प्रधान मंत्री तथा उनके सहयोगियों ने पिछले कुछ महीनों के तूफान का सामना किया और राज्य का काम चलाया, उसके लिये मैं उनकी सराहना करती हूँ। हमारे देश की क्या हालत होती यदि राज्य की बागडोर विरोधी दल के हाथ में होती।

पिछले 17 वर्षों से हमें कई छोटी और बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कुछ समस्याएँ तो हमारी अपनी बनाई हुई थी, परन्तु वह मुख्यतः विश्व की स्थिति के कारण थी। यह सच है कि हमने गलतियाँ भी कीं और हमारी प्रगति भी पर्याप्त नहीं रही, परन्तु यदि सरकार की निन्दा कम की जाती और सहयोग अधिक दिया जाता तो शायद इतनी गलतियाँ न होतीं।

मुझे बजट के सम्बन्ध में इतना अनुभव नहीं कि मैं वित्त मंत्री की प्रशंसा अथवा निन्दा कर सकूँ। परन्तु जो थोड़ा सा सामान्य ज्ञान मेरे पास है उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि हम जिस समय से गुजर रहे हैं और जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उनको देखते हुए किसी भी वित्त मंत्री के लिये ऐसा बजट बनाना कठिन है जो सभी को संतोष दे सके। यह अच्छा होता कि उन लोगों को कुछ राहत मिल जाती जिन्हें उसकी काफी आवश्यकता थी। मैं बजट तथा प्रतिरक्षा की आलोचना उसके लिए योग्य लोगों पर छोड़ देती हूँ। हमारा देश इस समय नैतिक अभाव के संकट से गुजर रहा है। यह बहुत ही गम्भीर संकट है। मनुष्यों तथा समाज में गिरावट आ रही है और यही हमारी समस्याओं की जड़ है। हमें अपने देश के नैतिक उत्थान के लिये कुछ करना चाहिये। हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है क्योंकि अनैतिकता और गिरावट को हमने स्वीकार कर लिया है। अन्य शब्दों में हमने भ्रष्टाचार को भी सामान्य चीज मान कर स्वीकार कर लिया है। समाज में जो पतन हो रहा है उस को हम इस सभा और देश में स्वीकार कर रहे हैं। यदि एक भी ऐसा वर्ग होता जो उसके विरुद्ध आवाज उठाता अथवा उन नैतिक तत्वों को पुनःस्थापित करने का प्रयत्न करता जिनको हमने खो दिया है तो शायद स्थिति में आज कुछ सुधार होता। इसके लिये किसी एक मंत्री को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। इसका एक कारण यह भी है कि हमने उन चीजों का विरोध करने के बचाये उनको स्वीकार कर लिया है।

वित्त मंत्री ने जो प्रस्ताव उन लोगों के सामने रखा है, जो वर्षों से सरकार को कर नहीं दे रहे थे अथवा धन छिपाया हुआ है, मैं उनका घोर विरोध करती हूँ। मेरे विचार में सरकार को छिपा हुआ धन निकालने के लिये अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिये। यह भी एक कारण है कि सरकार किसी भी चीज पर काबू नहीं पा रही है। क्या गलत है और क्या ठीक है, सरकार को इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति अपनानी चाहिये। हम सरकार से भाषण काफी सुन चुके हैं। अब हमारे नेताओं को कोई ठोस काम करके दिखानी चाहिये।

मैंने अपने चुनावों को तब लड़ा जब देश में खाद्य संकट का पूरा जोर था। मुझे अनाज की कमी और अकाल के सम्बन्ध में कुछ पता है क्योंकि जब काठियावाड़ और बंगाल में अकाल पड़ा था मैंने वहाँ काम किया था। परन्तु मैं बंगाल के दुर्भिक्ष की तुलना खाद्य संकट से नहीं कर रही। परन्तु उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री की उदासीनता पर मैं बहुत हैरान हूँ। जबकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फूलपुर में लोगों ने अनाज के अभाव के कारण कई दिन से चूल्हा नहीं जलाया था, जो उत्तर उन्होंने उस समय

दिये, उनको सुनकर मैं बहुत ही हैरान हूँ। यदि हमने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया तो लोग निराशा हो जायेंगे। हमें आश्वासन दिया गया कि अनाज आ रहा है और मैंने भी अपने निर्वाचन भाषणों में यही वायदा किया कि समुद्र पार से हमारे लिए अनाज आ रहा है। परन्तु मैं जानती हूँ कि जो एक भी दाना अनाज का बाहर से आ रहा है वह हमारे आत्मविश्वास को कम कर रहा है। मैं जानती हूँ कि हमारे देश के लोग इस सहायता के लिये आभारी हैं, और सरकार ने भी धन्यवाद कर दिया है। परन्तु जैसी स्थिति इस समय देश में है, यदि यह चलती रही तो निकट भविष्य में देश के लिये बहुत बड़ा संकट बन जायेगी। यदि एक खाद्य संकट और आया और हमें बाहर से अनाज मंगवाना पड़ा तो हमारा आत्मविश्वास बिल्कुल समाप्त हो जायेगा।

मैं इस देश में जहाँ कहीं भी गई, आपात स्थिति अथवा खतरे की भावना कहीं भी नहीं थी। हमारा मनोरंजन और पार्टियां उसी प्रकार चल रही हैं। मैं निन्दा नहीं कर रही क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता नहीं है उनके लिये आलोचना करना बहुत आसान होता है। परन्तु मैं बहुत नम्रता से उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ जो स्थिति में सुधार कर सकते हैं। यद्यपि पार्टियां देने में कोई हानि नहीं है, परन्तु जिस प्रकार की पार्टियां हम देते हैं उनमें ऐसी चीजें रखी जाती हैं जो साधारण व्यक्ति के लिये स्वप्नमात्र हैं। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि, पश्चिमी अतिथि जो इन पार्टियों में आते हैं, ने कई बार कहा है कि जब देश में अनाज का इतना अभाव है और बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता है तो पार्टियों में इतना क्यों व्यर्थ किया जाता है ?

मेरा ध्यान इस समय पश्चिम के देशों की ओर जा रहा है जहाँ यदि किसी वस्तु की थोड़ी भी कमी हो जावे तो हर व्यक्ति लाइन लगा कर सामान खरीदता है। इसका परिणाम यह होता है कि वहाँ कोई विशेष शोर इस कारण नहीं मचता क्योंकि प्रत्येक समझता है कि सब को बराबर कठिनाई प्रतीत हो रही है। परन्तु यहाँ तो बात ही दूसरी है। यदि ऐसी परिस्थिति यहाँ हो जावे तो लोग शोर मचाना आरम्भ कर देते हैं। जब यहाँ चीनी की कमी होती है तो हलवाईयों की दुकानें मिठाईयों से भरी रहती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं न कहीं कोई त्रुटि है। यह ऐसी चीजें हैं कि जिससे हमारी समाजवादी व्यवस्था को भी खतरा है।

आज जिस चीज की हमें आवश्यकता है, वह है चिगारी जोकि अभी तक हमें नहीं मिली है। हम इसके लिये सरकार की ओर देख रहे हैं ताकि हम आपस के भेदभाव भुलाकर सब मिकर चलें और यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह सबके लिये चाहे वह सरकारी दल हो अथवा विरोधी दल, हानिकारक होगा।

एक त्रुटि जो इस देश में आ गई है वह यह है कि हम ठीक निश्चय समय पर नहीं ले पाते हैं। कहीं भी कोई ठोस निर्णय नहीं किये जा रहे हैं और यही कारण है कि स्थिति खराब होती है। पहले तो यह बातें शायद सम्भव भी थी परन्तु आज तो विज्ञान का युग है और इसलिये एक एक क्षण का मूल्य है। इसलिये यदि कोई बुरी परिस्थिति भी है तो उसका जोरदार ढंग से मुकाबला करना चाहिये।

हमारे सामने चट्टानें खड़ी हैं। चाहे केरल अथवा कश्मीर की समस्या हो और चाहे शेख अब्दुल्ला अथवा वियतनाम की समस्या हो, कोई निर्णय दिखाई नहीं देते। हम अनिर्णय वाली परिस्थिति के दास बनते जा रहे हैं। मेरे विचार में समाजवाद ही एक ऐसा तरीका है जो हमें इन से पार निकालेगा। यह केवल हमारे लिये ही नहीं अपितु एशिया और अफ्रीका के देशों को भी सुदृढ़ कर सकता है और

खंडन करने वाली शक्तियों का मुकाबला कर सकता है। यह सच है कि हमने समाजवादी ढंग का समाज बनाना स्वीकार कर लिया है। मुझे इसका अर्थ पता नहीं लेकिन मैं समाजवाद को एक बड़े रूप से कह रही हूँ। ऐसा दिखाई देता है कि समाजवाद के कार्य पूर्ण होने में इसलिये कमी आ रही है कि हम समाजवाद को गम्भीरतापूर्वक पूरा करना नहीं चाहते।

जब नये विचार आते हैं तो उन पर अमल करना थोड़े से व्यक्तियों पर छोड़ दिया जाता है और वे चाहे कितने ही भी बड़े हों, आखिर मनुष्य हैं, आज जैसी स्थिति में असफल रह जाते हैं। इसलिये मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करती हूँ कि जो निर्णय एक बार ले लिये जायें, उन्हें यहाँ की जन्ता पूरा करे। हमें समाजवाद केवल नारे लगाने के लिये ही नहीं अपनाना है।

हमारी नीति बड़ी साफ होनी चाहिये और इसे पूरा करना भी साफ दिखाई देना चाहिये। यह तब होगा जब हमारे नेता उस पर दृढ़ता से चलेंगे। हमारे देश में जो पुराने विचार हैं उन के समाप्त होने में कुछ समय लगेगा।

हम जब भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो "परम्परा का" नाम लेकर हमें पीछे खेंचा जाता है। परन्तु मैं ऐसा करने वालों से पूछती हूँ कि उस समय विज्ञान नहीं था। अन्तरिक्ष काल नहीं था। न ही उस समय कोई अणुबम थे। यदि हमें कल कोई कार्य करना है तो पहले हमें भारत की स्थिति पर विचार करना होगा।

मुझे नेतृत्व शब्द पसन्द नहीं है लेकिन आज की दुनिया में नेतृत्व को छोड़कर एक और चीज है और वह है सहयोग, एक दूसरे को समझना तथा अपने कार्य का एक दूसरे से समन्वय करना। आज के संसार में हमें एक दूसरे का हाथ बंटाना चाहिये तथा आदान प्रदान करना। यदि हम ने ऐसा नहीं किया तो, दूसरों का नेतृत्व करने की बात तो दूर रही, हम अपने देश का भी नेतृत्व नहीं कर सकेंगे।

हमें अब फिर से उठना है और हमें उठना आता भी है और पहले उठ भी चुके हैं। सरकार डरती क्यों है और किस चीज से डरती है? यह सारा देश सरकार के साथ है और हम भी जो इस सदन में हैं, इस सरकार तथा प्रधान मंत्री, के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। ताकि वह देश के भाग्य को सुधारें।

मैं प्रधान मंत्री और उन के सहयोगी से प्रार्थना करती हूँ कि वे निश्चय के साथ आगे बढ़ें और अपना उद्देश्य पूरा करें और हम उन के पीछे श्रद्धा तथा निष्ठा से चलेंगे। लेकिन, यह तभी होगा कि वे अपने सिद्धान्त न छोड़ें। तभी एक नया युग आयेगा।

श्री नारायण दाण्डेकर (गोंडा) : अध्यक्ष महोदय, यह बजट बहुत चालाकी से बनाया गया है तथा होशियारी से प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री ने कुछ प्रसंनीय सिद्धान्तों का उल्लेख किया है परन्तु जब इस बजट पर किया गया वित्त मंत्री के भाषण का (ख) भाग पढ़ते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि जो आशाएँ इस से बंधी हैं उन के पूरे होने की सम्भावना नहीं है सिवाय इसके कि व्यक्तिगत कर में कुछ सहारा मिला है।

श्री मसानी ने बजट की पहचान के लिये तीन मापक रखे हैं। एक यह है कि इसका मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे इसका भुगतान शेष पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इसका विदेशी मुद्रा पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है; तीसरे इस में आर्थिक विकास की कितनी सम्भावना है। परन्तु यह मापक तो “इज्मों” (Isms) के नाम पर धीमे पड़ गये। कोई कहता था कि इस में समाजवाद है तथा दूसरे इस में पूँजीवाद ढूँढ रहे थे। परन्तु मैं तो इन चक्करों में पड़ने की अपेक्षा कुछ और मापक ढूँढना चाहता हूँ जिस से इस बजट का ठीक स्वरूप पता चल सके। मेरा स्वयं का कहना तो यह है कि इसे जांचने के लिये यह देखना है कि इसका साधारण बुद्धिमान नागरिक पर क्या प्रभाव पड़ता है।

इस सम्बन्ध में मेरे सामने भी तीन प्रश्न आते हैं। एक यह है कि साधारण नागरिक को पिछले 15 वर्षों में क्या क्या सहना पड़ा। दूसरे उसने इस से क्या आशाएँ बांधी थीं। तीसरे इन आशाओं का इस बजट में क्या बना? जब मैं साधारण व्यक्ति की बात करता हूँ तो मेरा आशय तो धनी लोगों से नहीं था। मेरा आशय तो उन लोगों से है जिनकी आय 15000 रुपये के लगभग है अथवा उससे कम है। इस देश में ठीक एक साधारण व्यक्ति के एक उसकी पत्नी तथा उसके चार बच्चे होते हैं। उसकी प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 1964-65 में आज के मूल्यों पर 360 रुपया होनी चाहिये। इस लिये मैं इस बजट को ऐसे व्यक्तियों के दृष्टिकोण से जाचूंगा क्योंकि हमारे देश में बहुसंख्या उनकी ही है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि एक साधारण व्यक्ति इस से आशा क्या रखता था। एक तो वे यह चाहते थे कि उन पर और अप्रत्यक्ष करों का बोझ न पड़े। दूसरे वे नहीं चाहते थे कि उनकी आय मूल्यों के बढ़ने के कारण कम न हो जावे। तीसरे वे चाहते थे कि उनकी आय कुछ न कुछ बढ़ जाये। ऊपर बताई तीन बातों से बजट की पहचान की जाती है।

अब मैं पहली बात की पूर्ति पर आता हूँ और कहूंगा कि वह आशा पूरी नहीं हुई और उन पर अप्रत्यक्ष कर लग गये हैं। ऐसे ही व्यक्तियों की आय भी कम हो गई है। वैसे इन अप्रत्यक्ष करों का सीधा प्रभाव साधारण जन्ता पर पड़ता है।

यह कहा जाता है कि सरकार अधिक धन को इसलिये जन्ता से लेना चाहती है ताकि इससे जन्ता के पास वस्तु खरीदने को कम धन रहे। मैं ऐसी योजना के हक में नहीं हूँ।

दूसरी आशा जो इस से बांधी थी वह थी कि इस से मूल्य न बढ़ने पावें ।

इस बारे में मैं वित्त मंत्री को उन के वे वचन याद दिला दूँ जो अभी पूरे नहीं हुए । उन्होंने कहा था कि प्रशासन के व्यय में कमी करेंगे । ऐसे ही उन्होंने बार बार कहा था कि बचत करने की आवश्यकता है तथा रुपया या कारोबार में लगाने को प्रोत्साहन मिलने की आवश्यकता है ।

मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि इन वचनों को पूरा करने की कोई आशा इस बजट में दिखाई नहीं देती । 1964-65 का बजट भी कहने को 11 करोड़ रुपये के घाटे का था । परन्तु वास्तव में वह 91 करोड़ रुपये के घाटे का बजट था । ऐसी ही 1965-66 का बजट भी कहने को तो 10 करोड़ रुपये बचत का बजट है परन्तु वास्तव में यह 181 करोड़ रुपये का घाटे का बजट है क्योंकि इसमें 191 करोड़ रुपया वह भी जोड़ना चाहिये जो उन्होंने पी० एल० 480 के अन्तर्गत उधार लिये हैं ।

इस बजट को यदि घाटे का बजट कहा जाय तो उचित होगा । सरकार जो, सहायता पी० एल० 480 के अधीन लेती है उसको ध्यान में रख कर तो कहना चाहिये कि यह बजट घाटे का बजट है । इस के विरोध में बहुत कुछ कहा जायगा परन्तु यह बात है सच । हम पी० एल० 480 का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं । एक तो हम हम खाद्य-पदार्थ आयात करते हैं और दूसरे धन कमाते हैं । इस कारण तो देश में कृषि की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । पी० एल० 480 पर अधिक निर्भर करना हमारे लिये बहुत हानिकारक सिद्ध होगा । स्फीति को रोकने के लिये कार्यवाही अभी करनी होगी । इस बारे में वित्त मंत्री ने कि हमें अपने खर्चों में बहुत कमी करनी होगी । बहुत अनावश्यक खर्च हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ बने हुए हैं । उनको कम करना होगा । इस बजट का अवलोकन करने पर पता चलता है कि कि सभी मदों पर व्यय में वृद्धि हो रही है । प्रतिरक्षा के व्यय के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा । हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय यह निश्चय किया था कि सभी संसाधनों का लाभ उठाया जायगा । चीनी आक्रमण उसके पश्चात् हुआ है । अतः हमें अन्य स्रोतों से भी धन लेना है । यह कहा जाता है कि प्रतिरक्षा पर होने वाला व्यय हम स्वयं सहन करेंगे और विकास योजनाओं का व्यय भी हम अपने पास से ही करेंगे । इस बात को मैं समझ नहीं पाता हूँ कि यह कैसे हो सकता है । हमें अपने व्यय में कमी करनी पड़ेगी, अब यह सरकार का काम है कि किन मदों पर खर्चों में कमी की जा सकती है । वित्त मंत्री ने स्वयं ऐसी ही बात कही है । केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में राज्यों के व्यय की ओर भी ध्यान देना होगा ।

[ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।  
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] ]

मूल्यों में वृद्धि के कारण जनसाधारण के आय का एक बड़ा भाग समाप्त हो गया है । बजट में उस के लिए कुछ नहीं किया गया है । पूंजी बाजार को ठीक करने

के लिये क्या किया जा रहा है ? हमारे देश में साम्यवादी अर्थव्यवस्था नहीं कि जहाँ पर सभी चीजों पर सरकार का नियंत्रण हो । हम अपने पूँजी बाजार को ठीक करना है । हमें अपने समाज के उन समुदायों से धन लेना होगा कि जो बचत कर सकते हैं । लोगों को प्रोत्साहन देना होगा कि वे अधिकाधिक धन विकास कार्यों के लिये दें । पूँजी बाजार की आज इतनी दुर्दशा हो गई है कि इसकी बहुत अधिक सहायता करनी पड़ेगी । पूँजी बाजार और स्टाक एक्सचेंज बहुत समय से बन्द पड़े हुए हैं । वित्त मंत्री ने जो रियायतें दी हैं वे साधारण पर्याप्त होतीं परन्तु आज की स्थिति में वे काफी नहीं हैं । इन से राजस्व पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा । बैंकों के ब्याज दर में कई बार परिवर्तन से ब्याज मुद्रा बाजार और पूँजी बाजार में परिवर्तन आ गया है । बैंकों में जमा किये गये ब्याज का दर 7 प्रतिशत हो गया है । ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ है । ऋण पत्रों के दर में भी साथ साथ वृद्धि हो गई है । इस पर कर व्यवस्था और कठिन हो गई है । इस पर पुनर्विचार होना चाहिये । इस संबंध में अधिक ढाँचे पर भी विचार होना चाहिये ।

पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने अधिकर-ढाँचा बहुत अच्छा बनाया था । मैंने उसका स्वागत किया था । उसमें अब ब्याज ढाँचे में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन होना चाहिये ।

लाभांश कर के बारे में वित्त मंत्री ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि कम्पनियां गड़बड़ कर सकती हैं । इस बारे में मेरा सुझाव है कि 1959 से पहले कर की व्यवस्था उचित थी । एक आधार वर्ष बनाकर लाभांश कर लगाया जा सकता है । बोनस शेयरों पर वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष जो कर लगाया उस की मैंने सराहना की थी । परन्तु कम्पनियों द्वारा जारी किये गये बोनस शेयरों पर बोनस कर को मैं समझ नहीं सका हूँ । मेरे विचार में जो कम्पनियां बोनस शेयर जारी करती हैं पर कर लगाना उचित नहीं । उन को इस से कोई लाभ नहीं होता वे तो केवल कागज के टुकड़े जारी कर देते हैं और वह भी पहले वाले अंशधारियों को ।

मेरा सुझाव है कि इस जटिल कर ढाँचे के स्थान पर सरल सा कोई ढाँचा बनाया जाय । इसमें इस प्रकार सुधार किया जाय कि इससे समझना एक व्यवित के लिये कठिन न हो ।

मेरा सुझाव है कि धन कर से पांच साल के लिये छूट होनी चाहिये । इस बात पर मैंने पिछले सत्र में धन कर (संशोधन) विधेयक पर बोलते समय भी जोर दिया था । अब इस बात को आंशिक रूप में मान लिया गया है । मेरे विचार में यह सभी विषयों में लागू होना चाहिये । जहाँ बचत और पूँजी लगाने का प्रश्न है वित्त मंत्री ने बहुत अच्छा कार्य किया है । इस सम्बन्ध में मैं केवल वार्षिकी जमा के योजना के बारे में कठक कहना चाहता हूँ । यह एक अनिवार्य जमा

योजना के समान है । यह 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिये बहुत कठिनाता की योजना है । इसका धन वापिस लेने के लिये बहुत से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पड़ते हैं । यदि एक आदमी की मृत्यु हो जाय तो ये सब काम उसकी विधवा को पूरे करने पड़ेंगे । इस योजना से सरकार को कोई विशेष लाभ भी नहीं हो रहा है । मेरा सुझाव है कि 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिये यह योजना स्वैच्छिक बना दी जाय । यदि वे चाहें तो इस योजना का लाभ उठायें तो ठीक है नहीं तो यह अनिवार्य नहीं होनी चाहिये । अब में कम्पनियों पर लगाये गये करों के बारे में कुछ कहूंगा । सरकार कम्पनियों के विस्तार खर्च पर 20 प्रतिशत की छूट देती है । अब इसे कुछ विधियों पर 25 प्रतिशत देने का प्रस्ताव है । इससे सभी उद्योगों का विकास नहीं होगा । सभी को 20 प्रतिशत की रियायत मिलनी चाहिये ।

आजकल प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था प्रचलित है । सरकार का निर्णय है कि यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिये । सरकार इन पर कर लगाती है । मेरे विचार में इन पर कर नहीं होना चाहिये । हां उन कम्पनियों पर यह हो सकता है कि जिन में विदेशी पूंजी लगी हो ।

वित्त मंत्री ने उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये उत्पादन शुल्क में छूट की घोषणा की है और इस आशय के प्रमाण पत्र आदि जारी करने को कहा है । मैं इस काम को सराहनीय काम समझता हूं । यह प्रमाण पत्र भुगतान आदि के लिये भी प्रयोग में लाने की अनुमति होनी चाहिये । यह रियायत सभी उद्योगों को होनी चाहिये । जनसाधारण की आशाओं के अनुसार यह बजट नहीं है ।

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad): It is a pity that this Government is not able to work in a right manner. I have tried to collect figures regarding deaths in this country during August, September 1964. Figures pertaining to entire country are not available. There are about 250 Municipal Committees maintain statistics in this respect. During August 1964 there were 2.7 deaths for every 1,000 persons. The figure for corresponding month of 1963 was 2.1. Thus there was an increase of .6. This was due to shortage of food grains. I can pass on this note to the hon. Minister. There are about 30 crores people in India who do not get adequate food. Government should make some effort to improve the lot of these 30 crores of people. They should be provided with food then they will be able to contribute towards the nation-building activities.

How will this happen? There is a talk of fertilisers. Grants are given to various institutions for production of more fertilisers. But what will you do with fertilisers if you do not have adequate supply of water to irrigate the fields. In the absence of water, fertilizers will only harm the fields. Although this is not important, yet I do not find any progress in this field. Only 5 crore acres of land is irrigated in India now, whereas there is no provision for irrigating another 26 crores acres of land. In the absence of irrigation facilities, all other plan programmes will be adversely affected.

I have suggested many times how this can be brought about. But the Minister has not paid any heed to it. There appears that their thinking has been

clouding by cobwebs. One of these mental cobwebs is of raising standard of living; another is of modernising everything. Recently I paid a visit to Bhopal where I saw Heavy Engineering Workshop, which is also an exercise in modernity. There are working 64 British experts. The sum spent on providing facilities etc. to these facilities comes to one-third of the total sum spent on 12 to 13 thousand Indian workers. If this is the only way left to us to modernise ourselves, then I would advocate not to go in for the services of such experts and we should rather rely on our own indigenous experts.

I was talking of mental cobwebs. Even in foreign affairs, the same mental cobwebs are in evidence. This country is the only country in the world which is constantly losing its land to foreigners. Very recently it has lost 13 thousand acres of land from 25th January to 3rd March this year, as is clear from the statement of the Minister of Foreign Affairs. When they are questioned about it, the Minister describes that land is a "disputed" territory. This is the only government in the world which takes the plea of calling its own land as "disputed territory" when it loses the same to others. I warn to abandon such policies because by calling your own land as "disputed territory" you provide the enemy with an instrument to harm you. The Government should honour the map which it got as on 15th August 1947.

Regarding Pakistan, I will only say that it should not be put on par with China. People of India and Pakistan are of the same stock and can again be united. But it cannot be said about Chinese. There can be a confederation of India and Pakistan.

It is sometimes said that the Indian Government sought help of the United States Government to help the former in Air Power. I am of the opinion that if any country invades Indian territory as left to it on 15th August 1947, it is the duty of the government to undo that attack by any means and no policy or anything should stand in its way of asking for help from any quarter. Indian Government asserts that it did not seek any such help. I say it is bad if it did not seek it.

There is a mention of Bandung, and Belgrade conferences and about policy of non-alignment. In those conferences only two disputes are mentioned. Cuba gets its case adopted in such conferences against the U. S. A. and Arab countries get their views adopted against Israel and China even though it is not always present at such conferences gets its view adopted. Only India remains the loser and never gets its views adopted. About South Asia, especially I want to say that India should not do anything whereby the power of China, who has attacked India, may increase and the power of those countries who helped India then or who may help it in future, may decrease. Whether it is the case of Vietnam or Malaysia, we should not say anything which may be of help to China.

We should make it clear that we would defend our territory with our own power and if it is not possible, we will seek others' help in it. The Arabs are doing it and others too are doing it. Only we are hesitant.

People ask, why in the face of such failures of the Government, you do not win the elections? I want to remind you about the Tammany Hall of New York. It was a Democratic Party but was most corrupt party in the world, yet it used to win elections on a scale that name would defeat it. The reason for its victory was that it would help people in their small matters such as admission of somebody in the hospital, admission of children to school, helping one in getting

[Dr. Ram Manohar Lohia]

ban and so on and so forth. Due to this it would win elections. The same is the case with congress Party. Opposition parties cannot help people in their small jobs as mentioned above.

I want to suggest a few things for elections although they are not complete remedies for having fair elections. First of all on the election day no motors, trucks etc. should be permitted to be used on election day in the Constituency. No candidates should distribute voters' slips and only government should provide those slips. This will avoid wastage.

I would suggest checkings of account books of Shri T. T. Krishnamachari and others in relation to what they had when the Britishers left India and what they have now. Krishnamachari & Co. had an asset of Rs. 20—30 lakhs when Britishers left and now it is estimated to be to the tune of Rs. 3 to 4 crores. Is it socialism? There is not a single member of the cabinet of 15 persons were who has not improved financially his lot or the lot of the members of his family. The way in which they have got this money may also be enquired. The desire to raise standard of living, the desire to become modern and the desire to copy Britain and America have brought ruin to this country. Those in upper strata should be brought down to a level below Rs. 1000. There are 150 categories from minimum to maximum pay ranges in the Government workshop which I mentioned a little while ago.

There should not be more than 8 categories.

Now I want say something about Lok Sabha. We have been defamed here very much. It is the duty of all of us to work here with dignity. But this should be done according to rules. I have read about the proceedings of many Parliaments but I have not come across anywhere time is given according to the number of members of political parties and not according to what the speakers have got to say.

I want to tell the leader of the House that if he continues to follow the policies of ex-Prime Minister, Shri Nehru, the country will become poor day by day and will go on losing its territory to others. I want him to ponder over these things seriously.

Now the government thinks that prices have come down. But it is because the farmers have sent their foodgrains to the market and hence this downward trend in prices is artificial. But after two or three months the prices will again rise.

I have received a letter saying how a poor man, who was selling rice in the market was arrested and later on let off after charging from him Rs. 150.00. Small mills of rice have been made to close down and in their places big mills have been put into operation and they thereby loot people. I, therefore, want that the interests of poor people may be attended to sympathetically.

श्री व० बा० गांधी ( बम्बई नगर-मध्य दक्षिण ) : श्रीमान मैं तीन बातों को मुख्य रूप से लूंगा । एक है मूल्यों में वृद्धि , दूसरी है हमारी विदेशी मुद्रा स्थिति की और तीसरी है मुद्रा आयोग की स्थापना के बारे में । मूल्यों की वृद्धि एक स्थायी बात हो गई है । पिछले 10 वर्षों में मूल्य बढ़ते ही गये हैं । यह कहा जाता है कि हमारे यहां कृषि उत्पादन में कमी रही है । परन्तु हम आयात भी तो बढ़ा रहे हैं । ऐसी स्थिति में मूल्यों की इस प्रकार वृद्धि नहीं होनी चाहिये ।

औद्योगिक क्षेत्र में हमारा उत्पादन काफी बढ़ गया है । हमारा कार्य बहुत संतोषजनक रहा है । इस क्षेत्र में की वस्तुओं के मूल्य भी बढ़े हैं । इस लिये हमें सोचना है कि इस के क्या कारण हैं । वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था में एक प्रकार की परिपक्वता आ गई है । देश में लोगों की ऋण शक्ति बहुत बढ़ गई है । इस के फलस्वरूप वस्तुओं का अभाव हो गया है । हम ने घाटे की अर्थव्यवस्था भी की थी । हमारे विकास कार्यों पर व्यय में वृद्धि हुई है इन सब परिस्थितियों के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है । अब प्रश्न यह है कि इन मूल्यों को और बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है । इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना होगा ।

हमारी विदेशी मुद्रा के बारे में स्थिति संतोषजनक नहीं है इस में कई बार संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है । इसका एकमात्र है कि हम अपना निर्यात बढ़ाकर अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करें । परन्तु इस कार्य में अभी पूरी नहीं मिल रही है ।

विदेशी भंडियों में हमारे मूल्य अधिक बताये जाते हैं । इस के लिये आंशिक रूप में हमारा सरकार जिम्मेदार है । सरकार की कर नीति भी इस का एक कारण है कि विदेशी मुद्रा की गम्भीर स्थिति के कारण हमें चिन्ता है । इसके लिये हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा विधि तथा अन्य स्रोतों से सहायता भी मांगी है । परन्तु यह सब अस्थायी उपाय है । वास्तव में हमें अपना निर्यात बढ़ाना चाहिये ।

मेरा सुझाव है कि सरकार एक मुद्रा आयोग की स्थापना करे । आप इसे मुद्रा तथा स्वर्ण आयोग भी कह सकते हैं । इस आयोग को मुद्रा तथा स्वर्ण के पूरे प्रश्न पर विचार करने को कहा जाय । इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में सहायता मिलेगी । सरकार को इस सुझाव पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करना चाहिये ।

**डा० सरोजिनी नहिषी** (धारावाड़—उत्तर) : बजट देश के लोगों की आशाओं का प्रतिबिम्ब होता है । देश के आर्थिक विकास की एक झलक उस में देखने को मिलती है । वित्त मंत्री को बजट बनाते समय देश के विकास तथा सुरक्षा का ध्यान विशेषरूप से रखना पड़ा है । ऐसी स्थिति में उन्हें यह देखना है कि कर ठीक प्रकार से एकत्र हो और उन का व्यय भी उचित प्रकार से किया जाय । आज्ञादी के इन वर्षों में देश के जनसाधारण में संतोष की भावना नहीं आयी है । सरकार अपने समाजवाद के घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई है । हमें देश से निर्धनता दूर करनी है । देश में सभी लोगों के लिए प्रगति के बराबर अवसर उपलब्ध कराने हैं । किसी विकासशील देश में मूल्यों का बढ़ाना आवश्यक है परन्तु इस की कोई सीमा होनी चाहिये । हमारे यहां मूल्य बहुत अधिक बढ़े हैं । पिछले दो वर्षों में यहां 24 प्रतिशत वृद्धि हुई है । यह वृद्धि जनसाधारण के लिए सहन करना बहुत कठिन बात है । फिर आवश्यक वस्तुओं का अभाव भी हो गया है । ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से क्या राहत दी गई है ? वर्तमान बजट एक अच्छा बजट है । इस के लिए वित्त मंत्री की सराहना होनी चाहिये । उन को यह देखना होगा कि इस को कार्यान्वित करते समय भी जनता के हितों का ध्यान रखा जाय । देश न सरकार तथा संसद को यह काम सौंपा है कि राष्ट्र के कार्यों को सुचारु रूप से चलाया जाय । देश के

## [डा० सरोजिनी महिषी]

सुरक्षा का ध्यान रखा जाय। हमारे अधिकारियों का भी यह कर्तव्य है कि संसद् द्वारा मंजूर की गई धनराशियों का ठीक प्रकार से उपयोग करें। कई बार देखा गया है कि अनुपूरक मांगों द्वारा प्राप्त किया गया धन भी उपयोग में नहीं लाया जाता। इस प्रकार की टिप्पणी लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में की गई है।

आज हमारे देश में सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। इस में खाद्य पदार्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राज्य सरकारें अपनी योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति में लगी हैं। और लगभग सभी राज्यों ने घाटे के बजट बनाये हैं। इस वर्ष केन्द्रीय बजट में घाटा नहीं है। आशा करनी चाहिये कि देश का भविष्य उज्ज्वल है। केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि राज्यों की सहायता करे और देखे कि दिये गये धन का ठीक उपयोग होता है। इसको एक प्रकार का समन्वय कार्य करना होता है। केन्द्रीय सरकार राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराती है परन्तु यह धन राज्य सरकारें उपयोग में नहीं लाती और कई बार वापिस कर दिया जाता है। यह सभी का कर्तव्य हो जाता है कि धन का उचित ढंग से उपयोग हो। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना होगा और समयानुसार कार्य करना होगा। वित्त विभाग को विदेशों का ऋण चुकाने के लिए जो धन दिया जाता है वह भी बिना उपयोग के ऐसे ही पड़ा है। विदेशी मुद्रा भी स्थिति भी संतोषजनक नहीं है इन्हीं कारणों से वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं, और परियोजनाओं की पूर्ति में विलम्ब हो रहा है। सरकार को इस ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि यदि सरकार सतर्कता से कार्य करे तो वांछनीय प्रगति हो सकती है।

वित्त मंत्री ने इस वर्ष व्यवितगत कर में कुछ रियायतें दी हैं। देश में जनसधारण को इस से कुछ राहत मिलेगी। उत्पादन शुल्क में भी कुछ कमी की गई है। इसका भी स्वागत होगा। आज देश में करों का ढांचा बहुत टढ़ा है। लोगों को इसे समझने में बहुत कठिनाई होती है। कई बार ऐसे होता है कि कर विभाग के अधिकारी व्यर्थ में ही जनता को तंग करते हैं। इस बार वित्त मंत्री ने इस में कुछ सुधार के प्रस्ताव किये हैं। यह बहुत अच्छी बात है। निगमित क्षेत्र में भी रियायतें दी गई हैं। इस सम्बन्ध में हमें एकाधिकार का प्रवृत्ति का दमन करना चाहिये। देश के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन् देने के लिए जो कार्यवाही की जा रही है मैं उस की सराहना करती हूं। यदि हमें अपना निर्यात व्यापार बढ़ाना है तो इस कार्य के प्रचार आदि के लिए निर्धारित धन का ठीक प्रकार से उपयोग होना चाहिये। 1963-64 के इस के लिए अनुदानों का प्रयोग नहीं किया गया। इसी तरह जो धन विदेशों में मंडियों आदि के सर्वेक्षण के लिए दिया गया था वह भी ऐसे ही पड़ा रहा। इस ओर ध्यान दिया जाय।

विदेशों में जो प्रदर्शनियां और मेले आदि लगते हैं उन के लिए विदेशी कम्पनियों से बीमा कराया जाता है। यह ठीक नहीं है। इस से देश को हानि होती है। हमें यह बीमा अपने देश की कम्पनियों से ही कराना चाहिये। लोक लेखा समिति ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इस ओर ध्यान दिलाया है। वित्त मंत्री इस ओर ध्यान दें। कृषि के क्षेत्र में किसानों को अधिक दाम दिलाये जा रहे हैं। परन्तु रुपये की कीमत कम हो जाने के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ते ही जा रहे हैं। किसानों को आवश्यक सुविधायें भी उपलब्ध नहीं की जाती हैं। सिंचाई

की परियोजनायें बिलम्ब से पूरी होती हैं। सरकार आश्वासन तो देती है कि खेती के क्षेत्र में सहायता मिलेगी। अच्छे बीज, और खाद आदि उपलब्ध की जायगी। कुछ गवेषणा केन्द्रों की स्थापना की बात भी का जाती है। परन्तु सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय नहीं है। सरकार कोई समिति नियुक्त करती है। उस की रिपोर्ट पर शक्यी तरह विचार नहीं होता और आगे कोई प्रगति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम अपना उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि हमें उत्पादन बढ़ाना है और रक्षित भंडार स्थापित करना है तो अपनी कार्य प्रणालियों में आवश्यक परिवर्तन करना होगा। हमें अपने अनुभव से लाभ उठाना होगा और भविष्य के लिए सतर्क होना होगा।

**Shri M. L. Varma (Chittorgarh):** I congratulate the Finance Minister for the Budget he has presented to the House. Together with that I may also state that the Finance Minister deserves congratulations for his proposal of a uniform scale of pay for the border police. We still find a good deal of economic inequality in this country. There are people even to-day who are living in the houses where there are one thousand rooms. I think the Government should occupy such big bungalows owned by only a few Capitalists and utilise them properly. Similarly the hoarded money should also be unearthed and the same may be invested in Industries. All efforts should be made to eradicate corruption and march towards the goal of Socialism. I may also urge that the highest limit of salary should be one thousand rupees and the lowest one hundred Rupees untaxed.

There is a general complaint that the claims which are made about the increasing agricultural production are not brought into action. The produce per acre of an agriculturist is more than the production in the Government farms. I would like to impress upon the Government that the management of the agricultural farms should be entrusted to actual farmers and they should be provided with the opportunities of obtaining specialised knowledge in foreign countries. It is also necessary that the farmers, the labourers and the small businessmen should be given more concessions. It should be ensured that the real workers are benefited from the schemes. I shall also urge that the time has come when the privy purses of the ex-rulers of States should be stopped.

I also feel that there is an acute shortage of roads on the border. Land measuring crores of acres is lying idle, because there are no irrigation facilities. This land can produce sufficient foodgrains for the country. I am of the opinion that if the huge amount which is spent on the import of foodgrains is spent on the required facilities for agriculture, the country can become self-sufficient in this direction. It is very necessary to point out that there are no roads in NEFA. It is also very strange that we have not been able to decide about the NEFA debate during the Chinese attack. The country still likes to know as to who was responsible for all this. No officer or the Minister has been given any punishment for this blunder. We see with our own eyes that several thousand acres of land have been illegally occupied by the aggressors.

It is also a fact that there is shortage of roads, water and other facilities in the Kutch area. Government should seriously pay attention to this aspect of the matter. We should also see that the nomadic denotified and scheduled Tribes are still living half naked in hills. They require water, education, wood and roads. The tribals in Bastar are subjected to harsh cruelty. So much so that their names are not registered in the voters' lists. The Pakistani Police have been committing atrocities and looting the people living on the borders. No check has been imposed on their activities.

[Shri M. L. Verma]

I am of the opinion that if we really want something to do we must understand that the entire economic and administrative structure requires to be changed altogether. That is the only way to remove poverty and to usher an era of socialism. Those who are accustomed to ply in the air should be made realists and the budget should aim ultimately the good of poor and general people.

**Shrimati Sahodra Bai Rai** (Damoh) : I wholeheartedly support the timely budget put forward by the Finance Minister. In Every field the country has gone ahead and development work is going on every where in the Country. I would like to point out a few things for the consideration of the honourable Minister.

Steps should be taken to develop Madhya Pradesh by giving adequate funds etc. Taccavi loans should be given to agriculturists and they should be remitted in view of less agricultural production due to inadequate rain last year. I may draw the attention of the House to the fact that irrigation facilities in Madhya Pradesh are not sufficient. Every effort should be made in this direction to improve them. We should also take up small industries in Madhya Pradesh. Barren land should be distributed among landless people.

It is also a well-known fact that certain officers indulge in corrupt practice. We should be vigilant in this direction and a watch should be kept on corrupt officers. This wide spread lawlessness should also be checked by stern measures. We should also be aware of the espionage activities of the enemy countries. We should be quite alert in this regard also.

There is also a complaint of the people that the money sanctioned for the education etc. of the poor people is not being properly disbursed by the officers. I may urge that proper step should be taken to ensure that such funds are correctly distributed. Educational facilities in the rural areas are inadequate. In every village there should be a school up to middle standard. The Government should help those educated persons who want to go abroad for higher studies. Proper medical facilities and maternity arrangements should be provided in the rural areas. Drinking water should also be sufficiently provided. There should be more wells for adequate supply of drinking water.

Agricultural labour is in a very had plight. We should see that he is adequately paid. Housing arrangements for teachers should also be made by the Government. They should also be given their pay in time. Radio stations should be set up in the rural areas, so that the Ministers should have a direct contact with the masses. Educational and other concessions should be given to Harijans, Adivasis and backward persons belonging to higher castes.

The widows of the army personnel who died while defending the country's frontiers should be helped by the Government. Our borders should be adequately safe-guarded. Some concrete steps should be taken in that direction. I really feel sorry that our villages are very badly neglected. I would urge the Government that due attention should be paid to the problems of the rural areas.

**श्री कर्णी सिंहजी** (बीकानेर) : वित्त मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। उसके लिए मैं उन्हें अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करता हूँ। आज तक मैंने 13 बजट देखे हैं, मेरे विचार में यह बजट उन में से एक सर्वोत्तम बजट है। वित्त मंत्री ने देश

की आवश्यकताओं और कमियों का बहुत ही बारीकी से और मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया है। आयकर कम किया गया है इसके लिए भी मैं वित्त मंत्री महोदय की सराहना करता हूँ। वैयक्तिक आय कर के कम होने का इस लिए भी स्वागत है कि इससे कर अपवंचन तथा अस्वस्थ तौर-तरीके प्रायः समाप्त हो जायेंगे और स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा। वित्त मंत्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

अपना यह विश्वास तो मैंने कई बार व्यक्त किया है कि कराधान किसी लोक-तंत्री देश में कुल आय से अधिक नहीं होना चाहिये। हमारे देश में आर्थिक असमानता बहुत दिनों तक और बहुत हद तक नहीं रहनी चाहिये। परन्तु जिस ढंग से वित्त मंत्रालय निचोड़ रहा है वह ढंग भी ठीक नहीं कहा जा सकता। यदि हम समझते हैं कि देश में धन का समान वितरण नहीं हो रहा तो हमें इसे तुरन्त समाप्त कर देना चाहिये। भूमि की खरीद पर उस प्रकार कर नहीं लगाया जाना चाहिये जैसे कि अब लगाया गया है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय इस बारे में कुछ गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और इस दिशा में ठीक ढंग की व्यवस्था कर देंगे।

एक अन्य सुझाव, उद्योगों को बड़े बड़े नगरों से उठा कर छोटे शहरों में ले जाने का है। वित्त मंत्रालय ने इस दिशा में कार्यवाही भी की है। छोटे शहरों में उद्योगों पर कम कर लगाये हैं। ऐसा करके हम काफी लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकेंगे। इसी तरह देश के समक्ष परिवार नियोजन की समस्या है। बढ़ रही आबादी के बारे में समचित कार्यवाही की जानी चाहिये। अब तो राष्ट्रपति ने भी इस को एक समस्या माना है। तीन से अधिक बच्चे पैदा करने वालों पर कर लगाया जाना चाहिये। यदि हम गरीबी और भूख को हटाना चाहते हैं तो इस दिशा में कोई विधान बनाना ही होगा। कराधान से इस रोग को काफी हद तक रोका जा सकता है।

आज जो देश में निराशा का वातावरण है, उसके सम्बन्ध में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने जो विचार व्यक्त किये हैं वह बहुत ही ठीक है। सदन के सदस्यों ने उनके विचारों की सराहना की है। अच्छा है कि कांग्रेस दल के व्यक्तियों ने वास्तविक रोग की ओर संकेत किया है, और उनके इस साहस को सर्वत्र देश में श्रद्धा से देखा गया। हमारे देश को स्वतन्त्र हुए 18 वर्ष हो गये हैं। इस पर भी हम अभी गरीबी को दूर नहीं कर पा रहे। लोगों को हम रोटी और मकान नहीं दे सके। आबादी का ज्यादा होना भी इसका एक कारण है। देश की एकता का प्रश्न भी एक सजीव समस्या है।

देश में साम्प्रदायिक भावनाओं को काफी भड़का दिया गया है। ऐसी समस्याएँ पैदा हो गई हैं जो कि हमें कई पीढ़ियों तक उलझाये रखेंगी। मेरा निवेदन है कि हमें, चाहे हम कांग्रेस दल के हों अथवा विरोधी पक्ष के साम्प्रदायिक नारों से दूर रहना चाहिये। हमें निराशा का वातावरण निर्माण नहीं करना चाहिये। प्रस्तुत स्थिति का ठीक ढंग से सामना करना चाहिये। यह तो हम सब महसूस करते हैं कि हमारे सामने बड़ी विकट स्थिति है। हमारे सामने खाद्य समस्या है, कीमतें बढ़ रही हैं। हमें बड़ी वीरता से इन समस्याओं का सामना करना है।

आशा की जाती है कि देश में जाति तथा सम्प्रदाय की भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए कुछ किया जायेगा। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को साम्प्रदायिक नारे

[श्री कर्णी सिंहजी]

नहीं लगाने चाहियें। वास्तविक राष्ट्रीय एकता लाने के लिए सभी जातियों और सम्प्रदायों के उम्मीदवारों को देश के विभिन्न भागों से चुनाव लड़ना चाहिये। लोगों के मन में बहुत निराशा है। निर्वाह व्यय में वृद्धि और खाद्य-समस्याएँ इसके बहुत बड़े कारण हैं। निराशा के कारण युवकों में विद्रोह फैल रहा है। परन्तु एक नये, सुदृढ़ और एकीकृत भारत के निर्माण के लिए उन्हें ठीक मार्ग पर डालना होगा।

हिन्दी को देश की राष्ट्रीय भाषा बनाना ही होगा परन्तु अंग्रेजी ने अभी महत्वपूर्ण कार्य करना है। जब तक विज्ञान और शिल्प की अधिकाधिक पुस्तकों का अनुवाद न हो जाये हमें अंग्रेजी पर निर्भर रहना होगा। वित्त मंत्री को यह बताना चाहिये कि जहां तक विदेशी विनिमय का सम्बन्ध है स्थिति में सुधार में कितना समय लगेगा। राजनैतिक दलों को बड़े व्यापारियों के धन पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। जब तक ऐसा होता रहेगा भ्रष्टाचार जारी रहेगा।

[ श्री सोनावाने पीठासीन हुई ।  
Shri Sonavane in the Chair ]

यह खेद की बात है कि राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में, जो कि राजस्थान का सबसे अधिक उत्पादन वाला क्षेत्र है, लोगों को आयातित गेहूं खरीदना पड़ता है जबकि स्थानीय गेहूं बम्बई और कलकत्ता चला जाता है जहां समृद्ध व्यक्ति उसे खरीद सकते हैं। सरकार भी माऊते जो राजस्थान के मरूस्थल भागों में खाने के काम आता है दूसरे भागों में पशु चारे के काम आने के लिये भेज दिया जाता है। बेरोजगार युवकों की समस्या को सुलझाने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। भारी संख्या में हमारे युवक और युवतियां बेकार हैं।

हमारी जन-शक्ति के गुणप्रकार में सुधार करने पर बल दिया जाना चाहिये। युवा विद्यार्थियों को अपने देश पर गर्व होना चाहिये। स्कूल तथा कालेजों में ठीक प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिये। यदि हमारा शिक्षा का स्तर कम होगा तथा विद्यार्थियों को ज्ञान के अवसरों का अभाव चलता रहेगा तो देश दूसरे दर्जे का देश ही बना रहेगा। शिक्षा के गुण प्रकार पर बल दिया जाना चाहिये।

जब तक हमारे लोगों में काम करने की तीव्र इच्छा नहीं होती, देश समृद्ध नहीं बन पायेगा। हमारे इंजीनियरों को भवन-निर्माण इस प्रकार करना चाहिये जिससे उन पर ऋतु का प्रभाव न पड़े ताकि बड़े बड़े भवनों में वातानुकूलन पर व्यय होने वाली विद्युत्-शक्ति का उपयोग उद्योगों के लिए किया जा सके। सभी राजनैतिक दलों को दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि भविष्य में विद्यार्थियों को उनके द्वारा प्रदर्शन, आग लगाना, लूट-मार तथा गूंडागर्दी जैसी कार्यवाहियों के लिए नहीं बर्ता जायेगा। सभी धर्मों के लोगों को मिलकर राष्ट्रीय एकीकरण लाना चाहिये। देश के सभी विभिन्न मतों और वर्गों को लड़ाई छोड़ एक हो जाना चाहिये। आज हमारे ऊपर चीन और पाकिस्तान आंखें गड़ाये बैठे हैं। हमें स्थिति की नाजुकता महसूस होगी और हम शीघ्र ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते जायेंगे। देश से गरीबी शीघ्र ही दूर हो जायेगी।

**Shri D.D. Mantri(Bhir):** In order to have self satisfaction some relief has been given in taxes but you cannot say people will be satisfied with this Budget. The relief for the common man in the budget are welcome, but it is

really regretted that duty on the Kerosene oil is not reduced. We should understand that if the high prices like this will continue the relief given will be practically meaningless. I may propose that Price stabilisation Board should be appointed.

I may also point out that the terms of reference of the Agricultural Commission are very defective. My fears are that it may not be able to fix remunerative price for the agriculturists. I also feel that there should be uniform taxation policy for five years, so that the people may get some satisfaction by the reliefs that are given. We must remain vigilant regarding the difficulties experienced in the matter of food last year. That should not be allowed to be repeated. As now the food corporation has been set up, it may be hoped that the situation might improve. It is really a pity that all incentives are given to the rich people and poor agriculturists are being neglected. We must pay attention to the need of the poor agriculturists.

( अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए । )  
( *Mr. Speaker in the Chair* )

In this country there is much talk about the black money. Black money is the outcome of defects in the system of taxation. I am of the opinion that the policy of giving concession to the hoarders of unaccounted money will not draw out such a black money. In the other hand it will give an incentive for tax evasion. I shall hope upon the Government that they should take stern legal measures in the matter.

I feel that the budget ought to have provided for some incentives for greater production of agricultural goods. But nothing has been done. Some necessary help to the producers can be given by the Government. I may state that without such things we cannot hope for the success of our plans. This is also essential that the disparity in the income of an agriculturist and that of an industrial worker must be reduced. Farmers should be supplied with cheaper fertilisers at lesser price. Rates of power meant for irrigation and agriculture should also be considerably reduced. The growers should also be assured of a remunerative price.

We must not ignore the danger of the inflow of foreign private capital in this country. It is a very harmful thing. If we encourage such a capital our own economy will be totally shattered. We should not dream that we would dictate terms to the foreign investors. This Policy is not in keeping with the industrial Policy Registration. We should very seriously reconsider this matter. Together with the regional unbalances in the matter of development must be removed. Industries in the public sector should be increasing by set up in the rural area. That is the only way to stop the migration of people from villages to the cities. Government should try to take the common man with them.

श्री रा० गि० दुबे (बीजापुर-उत्तर) : मैं वित्त मंत्री की बजट प्रस्थापनाओं का स्वागत करता हूँ। विरोधी पक्ष का विरोध तर्क संगत नहीं है। विरोधी पक्षों का परस्पर कोई एक मत नहीं, उनकी विचारधारायें परस्पर विरोधी हैं। मेरा निवेदन यह है कि बजट हमारी औद्योगिक नीति सम्बन्धी स्वीकृत संकल्प के अनुरूप ही है। हमने यह निर्णय किया हुआ है कि आधारभूत उद्योगों को सरकार के नियन्त्रण में रखा जाय। उपभोक्ता वस्तुओं

[श्री रा० गि० दुबे]

के उद्योगों तथा पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों के सारे प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । हमने यह भी निर्णय किया है कि भारी उद्योगों को स्थापित किया जाय ताकि देश पूंजीगत वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भर हो सके ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री की प्रशुल्क तथा मुद्रित नीतियों के कारण मूल्यों के सम्बन्ध में प्रचलित प्रवृत्तियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है । चीजों के भाव कम हुए हैं । अनाज दालों तथा अन्य वस्तुओं के दाम तो काफी हद तक कम हुए हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि खाद्य के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये । साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि इस मामले में आत्मनिर्भरता पर जोर नहीं देना चाहिये बल्कि हमें फालतू उत्पादन का भी प्रयत्न करना चाहिये । यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है ।

काश्मीर के मामले में चिन्तित रहने के साथ-साथ हमें अपने पूर्वी सीमान्त को नहीं भूल जाना चाहिये जो पूर्वी पाकिस्तान से घुसपैठ का सुगम स्थान है । इस समय शरणार्थियों के आगमन की जो रफ्तार है, पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का एक भी व्यक्ति नहीं रह जायेगा । पाकिस्तान से किसी बात चीत के समय उस प्रश्न पर विचार किया जाय । पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पाकिस्तान के बीच एक साझे बाजार के बारे में विचार किया जाय ताकि लोग निर्बाध रूप से आ और जा सकें तथा यदि किसी निश्चित समय में अल्पसंख्यक अपनी सम्पत्ति का तबादला करना चाहें तो उन्हें ऐसा करते की अनुमति हो ।

सरकारी क्षेत्रों के उत्पादन के बारे में मेरा निवेदन यह है कि हमें यह याद रखना चाहिये कि पूंजीवाद भी कई बार काफी प्रगतिशील सिद्ध हो जाता है । हमें सरकारी क्षेत्र के साथ साथ गैर-सरकारी क्षेत्र को भी पनपने का अवसर देना चाहिये । हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि साम्यवाद एक दिन में प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

इन शब्दों के साथ मैं पजट का समर्थन करता हूँ ।

**Shrimati Vijaya Raje Scindia (Gawalior) :** I welcome this Budget, It will give relief to the common-man. We were having deficit Budget for the last so many years and as a result prices continued rising higher and higher. This Budget gives a ray of hope because no new tax has been proposed. The Finance Minister has taken into account all this problems facing the country while preparing this Budget. I appreciate this Budget as due importance has been given to the defence requirements of our country. The Chinese aggression had exposed our weakness. In this Budget additional provision has been made for strengthening our defence preparedness. We should congratulate the Finance Minister for this. The question of security of our country is the most vital question for us. There have been happenings on our border daily. The neighbouring countries are amassing their armies on frontier. It is very disturbing. We have to be very careful and vigilant in such circumstances.

Tax on silver has been reduced in this Budget. It will have very good results. The farmers did not bring their produce to the market and the result of rise in prices. This new step will prompt them to bring their produce i.e. wheat etc. to market. In order to boost the agricultural production our Government should conduct survey of all lands and bring more land under cultivation.

I find that farmers prefer to come to cities. This tendency should be checked. We should set up small scale industries in villages. There are provisions in this Budget for bringing down the prices. It is a very [good thing. It will help in bringing down the prices of other essential things also.

This Budget will encourage the trade. It has so many incentives to offer. It offers hope and confidence for starting new industries. It will also help in increasing the industrial production. This Budget gives exemption from duty to newly established industrial concerns very liberal policy has been made in this respect. The Finance Minister has not resorted to direct taxes this time.

This Budget can be termed a people's Budget. India is a much taxed country. There is heavy taxation in other countries but there is simultaneously good compensation for this in those countries. People are provided so many facilities in those countries. It is the duty of our Government to give proper guidance to industry and trade. If we increase our production we can increase our exports. In that way we can earn more foreign capital. This Budget is forward step to achieve these goals.

It is a matter of gratification that more money has been provided for education. During the pre-independence period this subject was the most neglected subject. We have not been able to make the desired progress in this field. Lakhs of our countrymen are yet illiterate. We must special attention to this problem. The money provided in this regard is thus inadequate. If we are able to educate all our people it will help us in solving so many problem. One such problem is the population problem. We should impart religious and moral education of to students. It will help in building character of our youngmen. Our present system of education requires drastic changes.

The present system is a faulty one. It does not inculcate a sense of responsibility in students. We find so many agitations by student community these days. Government should pay proper attention to this problem.

The controversy over the language question has agitated the mind of every Indian. It has hit the emotional intigration of our country. It is a very sad matter for all of us. Our leaders had decided that we must have a link language. Once it has been decided we must stick to that decision. All the longuages of our country are impotent. We must make every effort to propagate them. The link language should be a subject of study from primary stage to university stage of education. We cannot have a foreign language as link language. English can continue as an associate language. It is very useful for international purposes. We should stop this countroversy now and all bitterness should varnish. The official language should be given all encouragement.

In the end I congratulate the Finance Minister for this Budget.

**Shri Prakash Vir Shastri** (Binjor) : I congatulate Shrimati Vijay Lakshmi Pandit for her speech. She has proved that country is above party. At the time of formulation of third plan! it was proposed to levy taxes to the tune of Rs. 1100 crores during this plan period, but during the first four years of the plan the taxes levied are of the order of Rs. 2050 crores. The present abnormal increase in prices is the result heavy taxation. Only ten days before duty on import was increased by 10 p.c. Now it is claimed that this year's Budget has brought relief. I cannot understand this.

[Shri Prakash Vir Shashtri]

Government has not been able to control its expenditure. Nobody is against the expenditure on defence of the country. So far as the assistance to the state Governments is concerned, the central Government should exercise some control on them. Now-a-days about 25,000 teachers are on strike in Utter Pradesh—my state. They are demanding the revision of pay scale. Central Government should give some assistance to U.P. Government to meet the genuine demand of teachers. Along with this Government should have some control on state Government's finances.

The Estimates Committee had asked the Government to curb the tendency of granting deputation allowance. This tendency is on the increase now. If a person of special qualification is sent on deputation and is granted allowance for that, it can be understood, but now this practice is being followed in ordinary cases also. Government should think over this matter and stop this practice.

Now Public Accounts Committee had drawn the attention of the Government to the faulty Budgeting by Government in 1964-65. It is not good. This has been proved in last year's estimates. It is also claimed that Government has shown surplus money by its efficient working, but in reality the preparation of estimates was not proper. Proper attention should be paid to this.

[ उपाध्यक्ष महोदय योठासीन हुए  
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair* ]

We are to pay back loans to 24 countries. In 1951-52 we owed a debt of Rs. 35 crores and in 1964 it has swelled to 3000 crores. It means our borrowings have gone up by 87 times during the last 14 years. In comparison money received by Government from within the country is much less. We are inviting foreign investment in large quantity. It is not in the interest of our country. It will have adverse effect on the economy of our country. Government should think over this matter.

Regarding black money the Minister has said that no definite figure can be given about it. He has given some time for its disclosure. I hope the Minister will take every step to unearth hidden money. I suggest that a probe may be conducted to know the cause of this tendency. Government should give some encouragement by which people may bring out such money.

The level of prices has gone during recent months. According to statistics compiled by the Reserve Bank of India there has an increase of 17.7 percent during the last three months of year 1964. One of the causes for this is the decrease in production during the year 1964. If proper care is not taken by the Government it will have very adverse effects.

Government has announced an increase in the dearness allowance of its employees. Similar increase will have to be effected by state Governments. All this will add to the burden on public exchequer.

During last two years there has not been any increase in the investment in new industries. This thing has been pointed out by Shri G.L. Mehta. Most of the existing public undertakings are running at loss. It is easy to start an undertaking. We should see that it runs efficiently and earns due profit. One thing we should see always is the interest of our young men. We should

try to absorb our young technicians and engineers in our factories etc. They have announced some concessions to the corporate sector. They should be given more concessions. We have to make the economy stable. First of all action should immediately be taken to control the prices. Position regarding foreign exchange is also becoming alarming. We should utilise the maximum production capacity of industries. Agricultural production should be given the first priority.

I would urge the Government to pay proper attention and take every action on the reports of the Public Accounts Committee. It is an important responsible committee and its suggestions are very constructive.'

**योजना मंत्री (श्री ब० र० भगत) :** विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बजट की आलोचना की है। मैं उनकी राय के बारे में कुछ नहीं कह सकता। उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। मैं कुछ बातें स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। कुछ ने कहा है कि यह बजट चालाकी से बनाया गया है। कुछ ने कहा है कि कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ नहीं किया गया है। कई सदस्यों ने सरकारी क्षेत्र की आलोचना की है।

यदि आज की आर्थिक स्थिति को देखा जाय तो पता चलेगा कि इससे अच्छा बजट नहीं बनाया जा सकता था। पिछले कई वर्षों में राजस्व बढ़ाने के कई कारण थे। सब से मुख्य कारण तो देश में आपातकाल की घोषणा थी। हमारे देश पर आक्रमण हुआ। हमें उसका मुकाबला करने के लिये तैयार होना था। इसके साथ साथ हमें अपने विकास कार्यों को भी बढ़ाना था। इन सब बातों के होते हुये भी इस वर्ष कोई नया कर नहीं लगाया गया है। इसका सब जगह स्वागत हुआ है। हम इस स्थिति में नहीं हैं कि करों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। हमारी अर्थ-व्यवस्था ने इतनी प्रगति अभी तक नहीं की है। हमें इस संबंध में बहुत सावधान होना है। इस बार रियायतें देते समय वित्त मंत्री ने बड़ी सावधानी से काम लिया है।

यह कहा गया है कि लाभांश कर तथा बोनस कर समाप्त क्यों नहीं किया गया। इस बारे में नई कम्पनियों को पांच वर्ष के लिये रियायत दे दी गई है। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं कि वित्त मंत्री निगमित क्षेत्र के विरुद्ध हैं। व्यक्तिगत करों के बारे में कुछ सदस्यों ने कहा है कि वर्तमान कर ढांचा बड़ी आय वालों पर अधिक राहत देता है परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं। इसका आपको अध्ययन करने से पता चल जाएगा। हमने यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया जैसी संस्थायें खोल दी हैं कि जहां लोग रुपये के बचत करके जमा कर सकते हैं। श्री मसानी ने इस्पात आदि पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की आलोचना की है। इन वस्तुओं पर व्यापारियों को बहुत अधिक लाभ होता है। इसलिये शुल्क में वृद्धि की गई है।

अतिरिक्त आय को उन चीजों में राहत देने में लगाया, जिसको कि काफी व्यापक रूप में लोग प्रयोग में लाते हैं। इसमें भी भावना यही थी कि सामान्य व्यक्ति को राहत देना है और बचतों को प्रोत्साहन देना है। विनियोजन की सहायता की भी इसमें भावना है। इससे अर्थव्यवस्था को एक नया मोड़ मिल सकता है। अतः उन सभी परिवर्तनों के समूचे प्रभाव के परिणामस्वरूप, सारी की सारी अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा मिला है। इस बारे में यह तर्क भी दिया गया है कि आय व्ययक सन्तुलित नहीं है। और उसका कारण यह कि वित्त मंत्री ने आयात पर 10 प्रतिशत कर लगाया है। और इसके अतिरिक्त 90 करोड़ रुपये अथवा 100 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। इस सारी स्थिति के लिये केवल एक ही तर्क दिया जा सकता है कि यह सब उपाय केवल मुद्रा विनिमय की गम्भीर

स्थिति का सामना करने के लिये किया गया है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह मुद्रास्फीति वाला बजट है। और उसके लिये तर्क यह दिया गया है कि पी० एल० 480 की तिधियों को सम्मिलित कर लिया गया है। इस सन्दर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम खाद्यान्न मंगवा रहे हैं और उसके लिये भुगतान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम यह प्रयत्न कर सकते हैं कि क्या यह मुद्रास्फीति है अथवा यह एक ढंग है जिससे कि मुद्रास्फीति रोकी जा सकती है? मेरा निवेदन यह है कि इससे फालतू धन समेटा जा रहा है, अथवा धन के स्थान पर वस्तुओं को प्राप्त किया जा रहा है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि अन्य देशों में ब्याज की दरें बहुत अधिक हैं और इस सन्दर्भ में भारत की तुलना अन्य देशों से की है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि भारत की स्थिति की तुलना किसी विकसित तथा उन्नत देश से नहीं की जा सकती। उन्नत देशों का विकास विविध प्रकार से हुआ है। हमारी स्थिति कुछ दूसरी है। हमारी स्थिति तो यह है कि हमें वित्तीय साधन उपलब्ध होने बहुत कठिन हो रहे हैं। अतः स्वाभाविक ही है कि हमारे ब्याज दर अधिक होंगे। इस अवस्था के कारण ही मेरा यह कहना है कि हमें वित्तीय अनुशासन कायम करना होगा। जो भी दुर्लभ वस्तुएँ हैं उनका वितरण प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। यह कहना बिल्कुल गलत है कि सारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और वे अपेक्षित योगदान प्रस्तुत नहीं कर रहे। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र का अंशदान निरन्तर बढ़ता रहा है। हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते।

अवक्षयण के लिये और ब्याज के 32 करोड़ रुपये अदा कर देने के पश्चात् "हिन्दुस्तान स्टील" को 1962-63 में 25 करोड़ रुपये और 1963-64 में 5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इस बात की पूरी आशा की जा रही है कि आने वाले वर्ष में इसे 6 करोड़ का लाभ होगा। इसी तरह सभी कारखाने प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं और जितना सम्भव है, अधिकतम स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं। 30 व्यापारिक समवायों के वर्ष 1963-64 के सन्तुलन विवरणों से, जिन्हें कि सभा पटल पर रखा गया है, यह पता चलता है कि आय औसतन 7.5 प्रतिशत के लगभग हुई है। यह आशा की जा सकती है कि 1964-65 और 1965-66 में निश्चय ही और अधिक बढ़ेगी।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स और हिन्दुस्तान मैशीन टूल 20 और 22 के बीच लाभ कमा रहे हैं। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने गत वर्ष 20 लाख का लाभ कमाया है, जबकि उससे पिछले वर्ष उसने एक करोड़ 25 लाख रुपये का लाभ कमाया था। इसका कारण यह है कि सारा विस्तार कार्य उस समय हुआ, जब मांग कम हुई थी। घाटे का दूसरा कारण यह भी है कि इसने कुछ रेलवे कोयला खानें, जो कि लगभग समाप्त हो चुकी थीं, ले लीं। इस बात की पूरी आशा है कि मांग बढ़ेगी और इससे काफी लाभ कमाया जा सकेगा।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यह कहना कि सरकारी क्षेत्र कुछ नहीं है, देश भक्ति की बात नहीं है। यह कहना देश की अर्थ व्यवस्था पर बड़ी चोट करना है। इसका कोई अन्य विकल्प ही नहीं है। सरकारी क्षेत्र के लाभ का प्रभाव गैर सरकारी क्षेत्र पर भी पड़ता है। यह भी गलत है कि हमने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की है। सरकारी क्षेत्र के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। गैर-

सरकारी क्षेत्र के मुख्य समर्थकों को यह समझना चाहिये कि क्योंकि उन्होंने भी गैर-सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण मदों के निर्माण को सरकारी क्षेत्र में से लेकर धन का विनियोजन किया है, अतः उन्हें काफी लाभ प्राप्त हुआ है। इन्होंने सरकारी क्षेत्र में इस्पात, मशीन निर्माण जैसे बड़े बड़े उपक्रम आरम्भ किये हैं कि काफी विशाल और व्यापक होने के कारण उनकी अपनी समस्याएँ हैं। यह बात तो बड़ी स्पष्ट ही है कि इनके बिना देश अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकता। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस दिशा में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के स्थान पर, गम्भीरता से सोच समझ कर स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

इसी प्रकार विदेशी सहायता की बात है। हम पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम बहुत अधिक विदेशी सहायता पर आश्रित हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि विदेशी सहयोग और विदेशी प्राविधिक जानकारी का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अब हम उस स्थिति पर पहुँच गए हैं जबकि हम अपने रूपांकन संघ बना सकते हैं और अपने इंजीनियरों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। मैसर्स दस्तूर एंड कम्पनी को कायम रखा जायेगा और इसे और सुदृढ़ किया जाएगा। हम उस स्थिति पर पहुँच गए हैं जबकि हमें परियोजना संबंधी आयोजन कार्य करना होगा। उचित आयोजन से कठिनाई पैदा करने वाला समय कम हो जाता है और योजना के लिये अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। परियोजना संबंधी आयोजन त्रुटिहीन होना चाहिये। प्रशिक्षण और रूपांकन संघों के कार्य में सुधार से सरकारी क्षेत्र की, जो विकसित हो रहा है, कार्य भविष्य में अच्छा होगा।

तीसरी योजना के पहले तीन वर्षों में कृषि में संभावित दर पर प्रगति नहीं हुई तथा परियोजना के कुछ तरीकों के अनुसार संगठन पीछे रह गये हैं। परन्तु यह सच नहीं है कि धन, विदेशी मुद्रा अथवा उपकरणों के अभाव के कारण कृषि की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब हम कृषि पर सब से अधिक बल दे रहे हैं। चौथी योजना में हम चाहते हैं कि एक स्वनिर्मित कृषि कार्यक्रम बनाएं जहां कृषि को एक परियोजना समझा जाए जैसे औद्योगिक परियोजना। हमें सारा माल, सारी मशीनरी तथा उपकरण चाहियें जिनसे 1200 लाख टन का उत्पादन हो सके। सरकार ने ऐसा मूल्य निश्चित किया है जिससे कृषक को अधिक उत्पादन करके अधिक धन कमा सकने के लिये काफी प्रोत्साहन मिल सकेंगे।

हमने औजारों और उर्वरकों आदि के लिये एक योजना बनाई है और सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें होंगी। हम देखेंगे कि कृषकों के लिये सुविधाओं अथवा प्रोत्साहनों तथा खाद्य आदि की कमी के कारण है कृषि को हानि न हो। हमें उपभोग के प्रमाणों और आय के प्रमाणों को बढ़ाना है। हमें लोगों को काम देना है। ऐसा सहकारी क्षेत्र में तथा कृषि-सह-उद्योग क्षेत्र में भी करना होगा। हमें इस प्रकार का निर्माण करना है क्योंकि हम देश में समाजवाद का निर्माण करना चाहते हैं।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री की देन शांति, प्रगति और समाजवाद है और हम उस पर देश का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं आय व्ययक इस दिशा में एक प्रयास है। चौथी योजना को इसी भावना से ही कार्यान्वित किया जायेगा। हमें आशा है कि हम अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। मेरा निवेदन है कि हमें बजट को भी इसी प्रकार के दृष्टिकोण से देखना चाहिये।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : मैं वित्त मंत्री को इस बात के लिये मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सचेत और बचत वाला बजट प्रस्तुत किया है। इससे यह पता चलता है कि सरकार अपनी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के प्रति सचेत है। उन्होंने आने वाले वर्ष की भारतीय अर्थ व्यवस्था का आशामय चित्र प्रस्तुत किया है। मेरा निवेदन है कि हमें असम के पहाड़ी जिलों की समस्याओं की ओर भी ध्यान देना चाहिये। मेरा सुझाव है कि योजना आयोग को एक अध्ययन गुट नियुक्त करना चाहिये जो कि असम के पहाड़ी जिलों के लिये आर्थिक तथा सामाजिक विकास की समस्याओं पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों के घुस आने से प्रभावित पूर्वी भारत के सीमावर्ती जिलों की विशेष समस्याओं की जांच के लिये एक संसदीय समिति भी नियुक्त की जानी चाहिये। इस क्षेत्र में प्रतिरक्षा तथा विकास की समस्याएँ एक साथ हल की जानी चाहियें। मेरा आग्रह यह है कि अध्ययन दल तथा संसदीय समिति को अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र प्रस्तुत कर देनी चाहियें ताकि चौथी योजना अपने अन्तिम रूप में अधिक व्यावहारिक बनाई जा सके। और उसके अनुसार अपेक्षित अर्थ व्यवस्था को भी विधिवत् रूप दिया जा सके।

{ [अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]  
MR. SPEAKER in the Chai }

मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि असम के पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात तथा संचार समस्याओं को सब से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये। इन सब का संबंध देश की प्रतिरक्षा के साथ है। असम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा बिहार के कुछ भागों में पाकिस्तानियों का घुस आना एक गम्भीर समस्या है। असम में लाखों पाकिस्तानी मुसलमान घुस आये हैं। ये लोग राज्य की गम्भीर भाषा स्थिति का अनुचित लाभ उठा कर स्थिति को और भी खराब कर रहे हैं। इससे गड़बड़ वाली स्थिति पैदा हो रही है। सरकार को इस मामले में पूर्ण रूप से जागरूक रहना चाहिये और स्थिति पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन यह है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के पुनर्वास के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। यह दुःख की बात है कि पहले आये हुये विस्थापितों का पुनर्वास अभी तक उचित ढंग से नहीं हुआ है। कृषकों को भूमि देकर अन्य वर्गों को उद्योगों इत्यादि में, सम्भव हो तो सरकारी क्षेत्र में, रोजगार दिया जाना चाहिये। चाय पर कई प्रकार के कर लगे हुये हैं, मेरा निवेदन यह है कि अच्छा हो यदि चाय पर केवल केन्द्र ही शुल्क इत्यादि लगाये। चाय उत्पादकों को राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्जित राजस्व में से अनुपाततः भाग देदे। जन शब्दों से मैं आय व्ययक का समर्थन करती हूँ।

-----

केरल में राष्ट्रपति के शासन सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में वक्तव्य  
STATEMENT ON : PROCLAMATION REGARDING PRESIDENT'S  
RULE IN KERALA

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : माननीय सदस्यों को पता ही है कि केरल में जो 4 मार्च, 1965 को चुनाव हुये, उसमें किसी भी दल का बहुमत नहीं है। राज्यपाल 8 मार्च से 16 मार्च,

तक प्रयास करते रहे हैं कि किसी प्रकार विभिन्न दलों से बातचीत करके इस समस्या का कोई हल निकाला जाय। उन्हें इस दिशा में कोई सफलता न मिलने पर, उन्होंने 13 मार्च की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राज्य विधान सभा के हाल के चुनावों के फलस्वरूप किसी लोकप्रिय सरकार का बनाना संभव नहीं है तथा उन्होंने राष्ट्रपति से सिफारिश की है कि वह संविधान के अनुच्छेद 365 के अन्तर्गत एक उद्घोषणा जारी करें। एक राज्य सरकार के बनाने के लिये समझ संभव मार्गों की खोज के उद्देश्य से राज्यपाल ने विभिन्न दलों के साथ सविस्तार बातचीत की है।

यद्यपि श्री नम्बूद्रीपाद ने ऐसा अनुभव किया है कि वह विभिन्न गुटों तथा व्यक्तिगत रूप से विधान सभा के सदस्यों से बातचीत करने की स्थिति में हैं तथा कि वह एक गैर-कांग्रेस सरकार बनाने के समर्थ हैं, केरल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं ने वक्तव्य दिया है कि वे कम्युनिस्टों के साथ मिलकर कोई मंत्रिमंडल बनाने को तैयार नहीं हैं और न ही वह उनका समर्थन करने को तैयार है कांग्रेस का रवैय्या यह है कि जो भी सरकार बने, वह उसके प्रति संवैधानिक विरोधी दल का कृत्य निभाएगी तथा उस सीमा तक उसकी नीतियों का समर्थन करेगी जिस तक कि वे कांग्रेस की नीतियों के संगत हैं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जहां यह इच्छा प्रकट की है कि सब से बड़े दल को सरकार बनाने के लिये कहा जाना चाहिये, वहां यह भी कहा है कि वे कम्युनिस्ट (मार्क्सिस्ट) पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे तथा कि वह सहयोग का रवैय्या अपनाते हुये विरोधी दल बने रहेंगे। इस परिस्थिति में राज्यपाल ने महसूस किया है कि कम्युनिस्ट पार्टी को काम चलाने के लिये अपेक्षित बहुसंख्या प्राप्त नहीं है चाहे उनके दल के नजरबन्द सदस्यों को छोड़ भी क्यों न दिया जाए।

राज्यपाल ने कांग्रेस दल के किसी अन्य दल से मिलकर सरकार न बनाने के निर्णय को ध्यान में रखा तथा केरल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की मिली-जुली शक्ति केवल 37 होने से अन्य सभी सम्भावनाएं खोजीं और वह इस निर्णय पर पहुंचे कि कोई भी दल अन्य दलों अथवा वर्गों के सहयोग से भी किसी स्थिर सरकार बनाने योग्य नहीं है। उप-राष्ट्रपति, जो इस समय राष्ट्रपति का कार्य भार सम्भाले हुये हैं ने राज्यपाल की रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार के पश्चात् विद्यमान उद्घोषणा को समाप्त करके एक नई उद्घोषणा जारी की है जिसके अनुसार राष्ट्रपति ने केरल सरकार के सभी कृत्य तथा राज्यपाल को प्राप्त तथा उनके द्वारा वर्ते जाने वाले सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं।

श्रीमान्जी मैं उपराष्ट्रपति द्वारा, जो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जारी की गई दो उद्घोषणायें और नई उद्घोषणा के खंड (घ) के उपखंड (एक) के अनुसरण में उनके द्वारा जारी किये गये आदेश की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। मैं राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन की संक्षिप्त प्रति भी सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्कालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4065/65]

**Shri Madhu Limaye (Monghyr) :** This is strange matter, the state Legislative Assembly is being dissolved immediately after the elections. This has never happened before in the history of the country, though there has been President's rule several times at several places. I raise my point of order and submit that meeting of the state Assembly should be commenced and full opportunity should be given to the parties to set up a democratic administration. In this connection I draw your attention to sections 163, 164, 172, 174, 175 and 356.

**Mr. Speaker :** The Home Minister has tried to explain the same situation.

श्री नि० चं० चटर्जी : बिना विधान सभा की बैठक बुलाये राज्यपाल विधान सभा भंग कैसे कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य यह समझता है कि न्याय नहीं हुआ तो वह अदालत में जा सकते हैं ।

श्री ही० ना० मुखर्जी : स्थिति कुछ विचित्र सी हो गयी है । सभी संसदीय परम्पराओं की उपेक्षा करके यह उद्घोषणा की जा रही है । यह इस सदन के साथ भी अन्याय है और संविधान की दृष्टि से भी अनुचित बात है । यह परम्परा भी बहुत बुरी परम्परा है जिसका निर्माण किया जा रहा है । इससे देश की विधि की भी हत्या की जा रही है । जब कि संसद् का अधिवेशन चल रहा है, राष्ट्रपति इस प्रकार की उद्घोषणा नहीं कर सकते । राष्ट्रपति के अधिकार बहुत बढ़ा दिये गए हैं उन्हें कम करना होगा ।

श्री बड़े (खारगोन) : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य के लिये तिथि निर्धारित की थी, परन्तु आज अचानक ही राष्ट्रपति की उद्घोषणा के संबंध में उन्होंने अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर दिया है । हो सकता है कि मंत्रियों ने इस प्रकार की उद्घोषणा के लिये राष्ट्रपति से सिफारिश की हो, परन्तु मेरा निवेदन है कि संसद का सत्र चल रहा हो तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिये । दलों को सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

**Mr. Speaker :** I am not allowing a discussion on this issue. The honourable members are insisting that it is against the Constitutional provision, I may submit, that in this connection, I cannot give any verdict and take any responsibility in this connection. The Supreme Court can decide this matter. The statement has been given and there cannot be any objection to that.

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : यह प्रश्न तकनीकी रूप में विधि का नहीं है, औचित्य का है । सदन ने पूछे बिना राष्ट्रपति से आदेश प्राप्त कर लेना जिसे कि अब चुनौती नहीं दी जा सकती । अदालत में जाने वाली बात ठीक है, परन्तु वह उचित नहीं है । केरल के राज्यपाल ने बिना विधान सभा की बैठक बुलाए ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । क्या विधान सभा अपने प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती ? मैं चाहता हूँ कि इस दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार किया जाए ।

श्री रंगा (चित्तूर) : कल तो श्री नन्दा समय मांग रहे थे, आज वह वक्तव्य दे रहे हैं । राष्ट्रपति को गलत परामर्श दिया गया है । गृह-कार्य मंत्री ने सदन का अनादर किया है । इस प्रकार के कृत्यों से लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के प्रति वफादार कैसे रहा जा सकता है । खेद यह है कि संविधान में ऐसी स्थिति के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । उस समय ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की गयी थी ।

**Shri Madhu Limaye :** Sir, this is clear negation of democracy and against your instructions. As a protest I walk out.

[इस के पश्चात् श्री मधु लिमये सभा भवन के बाहर गये ।]

[*Shri Madhu Limaye then left the House*]

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : क्या केरल की विशेष स्थिति के कारण वहां श्री रंगा द्वारा सुझावित स्विस ढंग की सरकार स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार करने का सरकार का इरादा है!

श्री नन्दा : हम सारे प्रश्न को संविधान के उपबन्धों के अनुसार ही विचार कर रहे हैं ।

श्री वारियर : सरकार ने विद्रोही कांग्रेसियों को ही सरकार बनाने का अवसर क्यों नहीं दिया ? सरकार ने इसके लिए प्रतीक्षा क्यों नहीं की ? विधान सभा बुलाने के बाद उन्हें अवसर दिया जा सकता था, परन्तु इसका प्रयोग नहीं किया गया ।

नन्दा : राज्यपाल ने सारी सम्भावनाओं को देख लिया था और कोई भी दल सरकार बनाने समर्थ नहीं था और कांग्रेस किसी भी दल का समर्थन करने को तैयार नहीं थी।

श्री दी० चं० शर्मा : जो भी व्यवस्था की गयी है, क्या उसके अन्तर्गत सामान्य व्यक्ति के हितों की रक्षा होती रहेगी ?

श्री नन्दा : इस सन्दर्भ में यह विचार उपयुक्त नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : सदन स्थगित होता है ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 25 मार्च, 1965/चैत्र 4, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday March 25, 1965/Chaitra 4 1887.**